www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 29 अगस्त-04 सितंबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

उठो जवानो तुम्हें जगाने

क्रांति द्वार पर आई है

मनीष कुमार

एक कहावत है, प्याज़ भी खाया और जूते भी खाए. ज़्यादातर लोग इस कहावत को जानते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है. एक बार किसी अपराधी को बादशाह के सामने पेश किया गया. बादशाह ने सज़ा सुनाई कि ग़लती करने वाला या तो सौ प्याज़ खाए या सौ जूते. सज़ा चुनने का अवसर उसने ग़लती करने वाले को दिया. ग़लती करने वाले शख्स ने सोचा कि प्याज़ खाना ज़्यादा आसान है, इसलिए उसने सौ प्याज़ खाने की सज़ा चुनी. उसने जैसे ही दस प्याज़ खाए, वैसे ही उसे लगा कि जूते खाना आसान है तो उसने कहा कि उसे जूते मारे जाएं. दस जूते खाते ही उसे लगा कि प्याज़ खाना आसान है, उसने फिर प्याज़ खाने की सजा चुनी. दस प्याज़ खाने के बाद उसने फिर कहा कि उसे जूते मारे जाएं. फ़ैसला न कर पाने की वजह से उसने सौ प्याज़ भी खाए और सौ जूते भी. यहीं से इस कहावत का प्रचलन प्रारंभ हुआ. आज कांग्रेस पार्टी के लिए यह कहा जा सकता है कि अन्ना के मामले में उसने सौ जूते भी खाए और सौ प्याज़ भी.

अन्ना हज़ारे का आंदोलन आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है. अन्ना को देश के कोने-कोने से जनता का समर्थन मिल रहा है. आज सरकार के साथ-साथ देश के सभी राजनीतिक दलों के सामने यह आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है. समस्या यह है कि हर राजनीतिक दल अन्ना के आंदोलन को समझने में भूल कर रहा है. यह आंदोलन सिर्फ़ जन लोकपाल का आंदोलन नहीं है. यह आंदोलन पिछले 20 सालों से चल रही नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के ख़िलाफ़ है. यह 20 सालों की सरकारी योजनाओं और नीतियों के ख़िलाफ़ जनता का फ़ैसला है. सरकार विकास के आंकड़े दिखाकर भ्रम फैलाने को सुशासन कहना पसंद करती है. हक़ीक़त यह है कि शहर रहने के लायक नहीं रहे. कुछ मेट्रो शहरों को छोड़कर देश में कहीं पर 24 घंटे बिजली नहीं है. दिल्ली जैसे शहर में साफ़ पानी नहीं है. छोटे शहरों में ढंग की चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं. नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है. आम आदमी का जीवन नारकीय हो गया है. किसी भी अस्पताल में जाइए, वहां डॉक्टर गिद्धों की तरह मरीज़ों से पैसे लूटते मिल जाएंगे. सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है. सरकार ने पूरे देश को एक ऐसे भंवर में डाल दिया है, जहां जीवित रहना ही एक अभिशाप बन गया है. लोग पूरी व्यवस्था से तंग आ चुके हैं. लोगों में नाराज़गी है कि सरकार उनकी परेशानी और दु:ख-दर्द को ख़त्म करना तो दूर, उसे समझने का भी प्रयास नहीं कर रही है. यही अन्ना के आंदोलन के समर्थन का आधार है. इस आंदोलन में शहरी मध्य वर्ग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है. इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि अन्ना का आंदोलन इंटरनेट के ज़रिए फैला हुआ आंदोलन है. देश चलाने वालों, सभी राजनीतिक दलों और उद्योगपतियों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस आंदोलन में ग्रामीण और आदिवासी शामिल हो गए तो यह मान लीजिए कि इस देश का प्रजातंत्र ख़तरे में आ जाएगा. जो लोग यह समझ रहे हैं कि यह आंदोलन सिर्फ़ जन लोकपाल के लिए है तो यह उनकी एक बड़ी भूल होगी. जन लोकपाल इस जनांदोलन का सिर्फ़ तात्कालिक कारण है. और वह भी इसलिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने लोकपाल के मामले में राजनीतिक फ़ैसले न करके प्रशासनिक फ़ैसले लेने का जुर्म किया है.

जे पी आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर ने इंदिरा गांधी से कहा था कि जे पी के ख़िलाफ़ तीखे बयान देने से पार्टी को बचना चाहिए. फ़क़ीर और राजा के बीच जब भी जंग होती है तो जीत हमेशा फ़क़ीर की होती है. इसलिए फ़क़ीरों और संतों से नज़रें झुका कर बात करनी चाहिए. यह सुनकर इंदिरा गांधी तिलमिला उठी थीं. आज देश में वैसा ही माहौल है. दुःख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी में आज कोई चंद्रशेखर नहीं है.

इस आंदोलन में जो लोग शामिल हो रहे हैं, वे धन्य हैं. जो लोग अब तक शामिल नहीं हुए हैं, उनके पास मौक़ा है. अन्ना का आंदोलन लोकपाल तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. आने वाले दिनों में न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन होगा, चुनाव सुधार के लिए आंदोलन होगा. घर में बैठने का वक़्त ख़त्म हो गया है. हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए सड़कों पर उतरना होगा.

कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ग़लती यह है कि लोकपाल क़ानून बनाने के मामले में उसने टीम अन्ना के साथ धोखा किया, देश की जनता के सामने झूठ बोला. जब जंतर-मंतर पर अन्ना का आंदोलन हुआ और एक संयुक्त समिति बनाई गई तो सरकार ने यह वायदा किया कि दोनों पक्ष मिलकर लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करेंगे. दोनों पक्षों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन जब सरकार ने लोकपाल बिल तैयार किया तो उसने टीम अन्ना के सुझावों को दरकिनार कर दिया. इसका हल निकल सकता था, अगर प्रधानमंत्री ने इसमें मध्यस्थता की होती. सिविल सोसायटी के सुझावों को लोकपाल में शामिल करके संसद में उन पर अलग वोटिंग कराई जा सकती थी. अगर ऐसा होता तो अन्ना भूख हड़ताल पर नहीं जाते, लेकिन सरकार ने कड़ा रुख़ अपनाया. सरकार की तरफ़ से अन्ना की टीम को साफ़-साफ़ यह कह दिया गया कि आपको जो भी सुझाव देना है, स्टैंडिंग कमेटी के सामने दे सकते हैं. सत्ता का नशा कहिए या फिर क़ानून के ज्ञाता होने का अहंकार, कपिल सिब्बल ने जब भी अपनी ज़ुबान खोली, वह एक तानाशाह नज़र आए. डॉ. मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल, चिदंबरम और मनीष तिवारी बोलते चले गए, अन्ना हजारे को जनता का समर्थन बढ़ता चला गया. सर्वोच्च कोटि का वकील होने और जनता का प्रतिनिधि होने में एक अंतर होता है. प्रजातंत्र में राजनीतिक सवालों का जवाब संविधान और सीआरपीसी की धाराओं से नहीं दिया जाता है. इससे टीवी चैनलों पर होने वाली बहस को तो जीता जा सकता है, लेकिन यह जनता के दिलों पर राज करने का रास्ता बिल्कुल नहीं बन सकता. मौजूदा सरकार में वकील से मंत्री बने लोगों को यही बात समझ में नहीं आई. कांग्रेस के प्रवक्ता और मंत्री बहस करते गए और लोगों की नाराज़गी बढ़ती चली गई.

टीम अन्ना के पास अनशन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. वैसे भी अन्ना पहले ही यह कह चुके थे कि अगर सरकार ने जन लोकपाल बिल को संसद में पेश नहीं किया तो वह अनशन करेंगे. यहां सरकार से एक और चूक हुई. सरकार ने लोकपाल का सारा श्रेय ख़ुद लेने के चक्कर में विपक्ष को इस मामले से दूर ही रखा. यही वजह है कि इस मुद्दे पर कोई एक मत नहीं बन सका. जब अन्ना ने अनशन का ऐलान किया, तब लोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई. कई बड़े नेता इसमें शामिल थे. इस बैठक में रक्षा मंत्री ए के एंटोनी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने जनता की भावनाओं को महत्व देने की बात कही थी, लेकिन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, गृह मंत्री चिदंबरम ने इसे नकार दिया. कपिल सिब्बल ने क़ानूनी पक्ष रखा था. इस बैठक में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के नेता जनता के मूड को नहीं समझ सके. सरकार ने अन्ना का विरोध करने का फ़ैसला ले लिया. किसी भी नज़रिए से इसे राजनीतिक फ़ैसला नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जनमत अन्ना के साथ था. कांग्रेस ने ख़ुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली.

कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता हैं मनीष तिवारी. पहले उनके इस बयान को देखिए. कांग्रेस की एक स्पेशल प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा, हम किशन बाबूराव उर्फ़ अन्ना हज़ारे से पूछना चाहते हैं कि तुम किस मुंह से भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अनशन की

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना था, उस समय झारखंड में अपनी नियुक्ति कराने के लिए अधिकारियों में होड़ मची थी.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

बाबुओं की कमी

देश में नौकरशाहों की कमी सरकार के लिए चिंता का विषय है. इसके अलावा वन प्रबंधन और डाटा संग्रह विभाग में अधिकारियों की कमी है. वन्यजीव संरक्षण के लिए कर्मचारियों की जरूरत महसूस की जा रही है. इसके बावजूद इस कमी को पूरा करने में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है. पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक, वन्यजीव महकमे में कम से कम 40 फीसदी पद रिक्त हैं. एक तरफ वन्यजीव संरक्षण की बात बड़े ज़ोरदार तरीके से की जाती है, लेकिन अधिकारियों की कमी निश्चित तौर पर चिंताजनक है. सरकार की यह अनिच्छा समझ से परे है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के बाद सरकार के इस रवैये की काफी आलोचना हुई. एनएसएसओ के अधिकारियों की मानें तो उनके अनुभवी सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों पर गौर करना तो दूर, सरकार इन्हें ढंग से संभाल नहीं पा रही है. मुख्य सांख्यिकीविद् के मुताबिक, संबंधित मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बावजूद 30 फीसदी पदों को बिना वजह देरी किए जाने के कारण नहीं भरा जा सका.

एक शर्मनाक कथा

इस तरह के वाकये हों और भला बिहार का नाम न आए, यह हो नहीं सकता. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अक्सर चर्चित रहने वाले बिहार ने बहुत सारी ऐसी इबारतें लिखी हैं, जिनमें कुछ सराहनीय हैं और कुछ लज्जाजनक. बिहार की राजनीति में एक समय किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले लालू प्रसाद यादव ने नौकरशाही को किस हद तक निरीह–लाचार बना दिया था, यह बात किसी से छुपी नहीं है. बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत उनके जमाने में क्या थी, इसका अक्स आज भी वे अधिकारी महसूस करते हैं, जो लालू प्रसाद के जमाने में बिहार में कार्यरत थे. बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना था, उस समय झारखंड में अपनी नियुक्ति कराने के लिए अधिकारियों में होड़ मची थी. एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष मैथ्यू ने अपनी एक रिपोर्ट में, जो उनकी पीएचडी का विषय भी रहा है, बिहार में भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया है. उनका मानना है कि जब लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी सत्ता में थी, उस वक्त राज्य में सारा कामकाज कागजी होता था. उस दौरान बिहार में बाबूगिरी अपने चरम पर थी, लेकिन अब उसी बिहार में परिदृश्य काफी बदल चुका है. खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का पालन बखूबी कर रहे हैं. लालू शासन की तुलना में मौजूदा शासन कहीं बेहतर है. अगर बिहार में विकास देखना है तो किसी भी गांव का रुख करें, आपको ग्रामीण विकास का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

खनन सचिव के लिए ख़तरे की घंटी

नौकरशाही में अर्श से फर्श पर आना आम बात है. कभी आंखों का तारा रहे 1976 बैच के आईएएस अधिकारी एवं मौजूदा खनन सचिव सुब्रह्मण्यम विजय कुमार सरकार से मतभेद के कारण मंत्रालय से बाहर किए जा सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, सब कुछ ठीकठाक रहा तो दोनों मंत्रियों समेत मौजूदा सचिव को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि कुमार का अगला आशियाना श्रम मंत्रालय हो सकता है.

सारंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में

वर्ष 1977 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी एवं मौजूदा सचिवालय सचिव डॉ. मृत्युंजय सारंगी का अगला ठिकाना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय होगा. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यहां उनकी नियुक्ति सचिव पद के लिए होगी. सारंगी उत्तर प्रदेश कैडर के 1975 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. पी सी चतुर्वेदी का स्थान लेंगे.

वीणा बनीं संयुक्त सचिव

आंध्र प्रदेश कैडर की 1985 बैच की आईएएस अधिकारी वीणा ईश की नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में की गई है. वह सुनील कुमार का स्थान लेंगी.

अरविंद एनबीसीसी के नए सीवीओ

उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को शहरी विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) नियुक्त किया गया है.

उठो जवानो तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है

पृष्ठ एक का शेष

बात करते हो. ऊपर से नीचे तक तुम भ्रष्टाचार में ख़ुद लिप्त हो. इसके अलावा मनीष तिवारी ने अन्ना को एक दिमाग़ी तौर पर बीमार प्राणी बताया. मनीष तिवारी के इसी बयान ने उन्हें विलेन बना दिया. देश की जनता के साथ–साथ कांग्रेस पार्टी के कई सांसद मनीष तिवारी से नाराज़ हैं. मनीष तिवारी जनता की नज़रों से तो गिरे ही, अब पार्टी भी उनका साथ नहीं दे रही है. उन्हें मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी गई है. वह उदास हैं, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया. जबकि हक़ीक़त यह है कि अन्ना हज़ारे पर हमला करने का फ़ैसला मनीष तिवारी ने नहीं, बल्कि पार्टी के नेताओं ने लिया था. अन्ना ने जब जय प्रकाश पार्क में धारा 144 लागू होने के बावजूद अनशन करने का अपना फ़ैसला सुनाया तो पत्रकारों ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से इस पर प्रतिक्रिया मांगी. पार्टी की ओर से जवाब यह मिला कि सारे सवालों का जवाब रविवार को स्पेशल प्रेस कांफ्रेंस में दिया जाएगा. आम तौर पर कांग्रेस पार्टी रविवार को प्रेस कांफ्रेंस नहीं करती है. मनीष तिवारी ने अन्ना को एक ही सांस में फासीवादी, माओवादी और अराजकतावादी क़रार दिया. मनीष तिवारी ने जिस लहज़े में अन्ना पर हमला बोला, जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे कांग्रेस पार्टी की छवि सत्ता के नशे में चूर एक अहंकारी पार्टी की बन गई. 14 अगस्त यानी रविवार की स्पेशल प्रेस कांफ्रेंस कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बन गई.

इस ग़लती के बावजूद कांग्रेस संभल सकती थी, लेकिन वह अपने ग़लत फ़ैसले को सही साबित करने के चक्कर में एक के बाद एक ग़लतियां करती चली गई. पहले अन्ना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया. कांग्रेस को लगा कि जिस तरह उसने बाबा रामदेव पर आरोप लगाकर उनके आंदोलन की हवा निकाल दी थी, वही हाल अन्ना का होगा, लेकिन यह रणनीति नाकाम हो गई. कांग्रेस पार्टी यह नहीं समझ सकी कि अन्ना बाबा रामदेव नहीं हैं. बाबा रामदेव की तरह उनके पास हज़ारों करोड़ का साम्राज्य नहीं है. अन्ना सचमुच में फकीर हैं, एक संत हैं. इस प्रेस कांफ्रेंस के बाद कांग्रेस को संभलने का दूसरा मौक़ा 15 अगस्त को मिला, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले से देश को संबोधित किया. पूरे देश की नज़रें मनमोहन सिंह पर टिकी हुई थीं कि वह अपने भाषण में अन्ना के बारे में क्या कहने वाले हैं. भ्रष्टाचार और महंगाई पर प्रधानमंत्री से जो उम्मीद थी, वह उससे ठीक उलटा बोले. सरकार ने संभलने के बजाय एक और ग़लती कर दी. मनमोहन सिंह ने लाल किले से अन्ना पर हमला कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं है कि वह एक झटके में भ्रष्टाचार और महंगाई को ख़त्म कर देंगे. ऐसे बयान देकर सरकार जनता में ग़लत संदेश देती है. प्रधानमंत्री के पास अगर जादू की छड़ी नहीं है तो क्या आंखें भी नहीं हैं? उनकी कैबिनेट का एक साथी एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला कर देता है और उन्हें मालूम नहीं पड़ता है. जबकि अब पता चल रहा है कि इस घोटाले के दौरान ए राजा की तरफ़ से हर फ़ैसले के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर बताया जा रहा था. क्या प्रधानमंत्री यह दलील दे सकते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है. अगर प्रधानमंत्री को यह मालूम न हो कि किस मंत्रालय में क्या चल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में सरकारी तंत्र नष्ट हो चुका है. क्या हर मंत्रालय के संयुक्त सचिव का प्रधानमंत्री कार्यालय से रिश्ता ख़त्म हो गया है? मनमोहन सिंह को देश की जनता को यह बताना चाहिए कि आख़िर प्रधानमंत्री कार्यालय का काम क्या है. यही वजह है कि देश की जनता ने मनमोहन सिंह के भाषण को नकार दिया. लोगों की नाराज़गी बढ़ गई. अन्ना ने जनता के मूड को समझा और उन्होंने पहला मास्टर स्ट्रोक 15 अगस्त की शाम को खेला, जब वह अचानक राजघाट पहुंच गए. पूरा देश अन्ना को देख रहा था. छुट्टी का दिन था, लोग टीवी के सामने बैठे रहे. थोड़ी ही देर में वहां भीड़ जुटने लगी. अन्ना को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. बस उठने से पहले उनकी आंखों से कुछ आंसू गिरे और पूरे देश में अन्ना की लहर दौड़ गई.

15 अगस्त की रात शांतिपूर्वक बीत गई. 16 अगस्त की सुबह अन्ना हजारे को राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में हिरासत में ले लिया गया. यहां धारा 144 नहीं लगी थी. पुलिस ने अन्ना और उनके साथियों से यह कहा कि आपको वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास जाना है. जब वे वहां पहुंचे तो उनसे मोबाइल फोन और बाकी सामान निकाल कर बाहर रखने को कहा गया और फिर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया. पुलिस ने गिरफ्तारी की वजह यह बताई कि अन्ना और उनके साथियों से दिल्ली में क़ानून व्यवस्था बिगड़ने का ख़तरा है. सरकार ने अन्ना की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बताकर अपनी गर्दन बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरकार की इस दलील पर किसी ने विश्वास नहीं किया. लोगों को लगा कि अन्ना के साथ अन्याय हुआ है. देश भर में लोग सड़कों पर आने लगे. कई कंपनियों ने अपने दफ्तर बंद कर दिए. एक के बाद एक कई संगठन इस आंदोलन से जुड़ते चले गए. बड़ी संख्या में बच्चे–बूढ़े, छात्र–नौजवान और महिलाएं राजधानी दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़े.

यहां अन्ना ने फिर एक मास्टर स्ट्रोक खेला. उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई का जवाब एक राजनीतिक चाल से दिया और जेल के अंदर ही अनशन शुरू कर दिया. एक तरफ़ संसद में सरकार को विपक्ष की मार पड़ रही थी, दूसरी तरफ देश की जनता सड़क पर खड़ी थी. संसद में विपक्ष प्रधानमंत्री का बयान चाह रहा था, लेकिन सरकार ने उसकी मांग को ठुकरा दिया. चारों तरफ़ से घिरने के बावजूद सरकार का रवैया नरम नहीं हुआ. संसद नहीं चली, लेकिन अगले दिन तक सरकार पर इतना दबाव पड़ गया कि कांग्रेस के कोर ग्रुप ने यह फ़ैसला लिया कि प्रधानमंत्री बयान देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से एक भयंकर भूल हो गई. संसद में उन्होंने यह कह दिया कि अन्ना ने जो रास्ता चुना है, वह लोकतंत्र के लिए नुक़सानदेह है. प्रधानमंत्री के बयान ने आग में घी का काम किया. जनता का सरकार से विश्वास ही उठ गया. आंदोलन और तेज़ हो गया. कांग्रेस के नेता अलग–अलग जगहों पर ग़ैर ज़िम्मेदाराना बयान देते नज़र आए. राशिद अलवी ने यह कहकर चौंका दिया कि अन्ना के आंदोलन के पीछे विदेशी ताक़तों का हाथ है. पूरी घटना देखने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई राजनीतिक फ़ैसले लेने वाला है भी या नहीं.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

जन समर्थन देखकर केंद्र सरकार सहम गई. आंदोलन के तेवर को देखते हुए अन्ना की रिहाई का आदेश दे दिया गया. इसके बाद अन्ना ने सबसे बड़ा फ़ैसला तब लिया, जब उन्होंने कहा कि वह अपनी शर्तों पर जेल से बाहर जाएंगे. वह जेल के अंदर अनशन करते रहे. जेल के बाहर जनता उनके समर्थन में सड़कों पर उतरती रही. अन्ना का आंदोलन जंगल की आग की तरह देश के हर छोटे–बड़े शहरों में फैल गया. अन्ना लोकपाल बिल के संसद में पास होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. सरकार और टीम अन्ना के बीच बातचीत होती रही. पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें अनशन के लिए तीन दिनों का वक़्त दिया था, बाद में पुलिस ने अन्ना को अनशन के लिए रामलीला मैदान और 15 दिनों का वक़्त दे दिया. अन्ना जब जेल से बाहर निकले तो जनसैलाब उमड़ पड़ा. पांच–पांच किलोमीटर तक पैर रखने की जगह नहीं थी. अन्ना की एक झलक पाने के लिए लोग बारिश में भीग कर इंतजार करते रहे. रामलीला मैदान पहुंचते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक सरकार जन लोकपाल बिल को संसद में पास नहीं कराती है, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा, अनशन जारी रहेगा.

1950 में ब्रिटेन के डब्ल्यू एच मोरिस–जोंस ने आधुनिकता, पारंपरिकता और संतों या सेंटली इडियम को भारतीय राजनीति के तीन महत्वपूर्ण आधार बताए थे. भारत के संविधान, संसद एवं न्यायालय को आधुनिक और राजनीति में जाति एवं संप्रदाय को पारंपरिकता से जोड़ा था, लेकिन मोरिस–जोंस ने संतों की भूमिका को अनोखा बताया. उन्होंने भारत में त्याग करने वाले संतों की विशेष भूमिका बताई थी. इस श्रेणी में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को गिना जा सकता है, जिनका जीवन त्याग और संघर्ष की कहानी है. ये नेता लोगों के दिलों में इसलिए बसे, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये तो संत हैं. अन्ना हजारे की सादगी और उदारता लोगों के दिलों में बस गई. लोगों को अन्ना में गांधी दिखते हैं, विनोबा दिखते हैं, जेपी दिखाई देते हैं. कांग्रेस पार्टी के नेताओं और सरकार के मंत्रियों को अन्ना में एक भ्रष्टाचारी, फासीवादी, माओवादी और अराजकतावादी नज़र आया. राजनेताओं और देश की जनता के नज़रिए में अगर इतना बड़ा फ़र्क़ जहां होगा, वहां तो आंदोलन होना निश्चित है. इसके बावजूद अगर सत्ता का अहंकार राजनेताओं के सिर पर चढ़कर बोलेगा तो क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता है.

यह बात कहनी पड़ेगी कि संसद के बाहर पूरे देश में जो नज़ारा था, उससे संसद का औचित्य ही खत्म हो गया, क्योंकि प्रजातंत्र में तो सांसद जनता के प्रतिनिधि मात्र हैं. जब जनता ख़ुद ही सड़क पर उतर कर जन लोकपाल की मांग करने लगे तो उसे प्रतिनिधियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कई लोग यह मानते हैं कि इतिहास ख़ुद को दोहराता है. जब सत्तर के दशक में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हुआ, तब भी हालात यही थे. जयप्रकाश नारायण पर भी कांग्रेस पार्टी विदेशी एजेंट और अराजकतावादी होने का आरोप लगा रही थी. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर उस वक़्त कांग्रेस में थे. वह इंदिरा गांधी से मिले और कहा कि जयप्रकाश नारायण के ख़िलाफ़ इस तरह के बयान से कांग्रेस को बचना चाहिए. इंदिरा गांधी तिलमिला उठीं, लेकिन चंद्रशेखर ने दो टूक कहा कि फकीर और राजा के बीच जब भी जंग होती है तो जीत हमेशा फकीर की होती है. इसलिए फकीर और संतों से नज़रें झुका कर बात करनी चाहिए. आज देश में वैसा ही माहौल है. दु:ख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी में आज कोई चंद्रशेखर नहीं है. देश की जनता को अन्ना को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परेशानी से जूझ रहे देश को जगाने का काम किया है. इस आंदोलन में जो लोग शामिल हो रहे हैं, वे धन्य हैं. जो लोग अब तक शामिल नहीं हुए हैं, उनके पास मौक़ा है. अन्ना का आंदोलन लोकपाल तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. आने वाले दिनों में न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन होगा, चुनाव सुधार के लिए आंदोलन होगा. घर में बैठने का वक़्त ख़त्म हो गया है. हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए सड़कों पर उतरना होगा. आज राम गोपाल दीक्षित की एक कविता याद आती है:–

कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को,
बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को,
आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है,
उठो जवानो, तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है.

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 25
दिल्ली, 29 अगस्त–04 सितंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कम ही लोगों को यह बात मालूम है कि इसी दफ्तर से अन्ना के अनशन या कहें महाक्रांति का पूरा खाका तैयार होता है, समूची रणनीति तैयार की जाती है.

टीम अन्ना
मिलिए पर्दे के पीछे के नायकों से

फोटो-प्रभात पाण्डेय

अगस्त 2011 का यानी अन्ना की क्रांति का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, तब शायद ही इस क्रांति के उन गुमनाम नायकों का उसमें ज़िक्र होगा, जिन्होंने दिन-रात एक करके अन्ना हजारे के लिए इस महाक्रांति की ज़मीन तैयार की. ये परदे के पीछे के वे नायक हैं, जो पिछले एक साल से इस आंदोलन की ज़मीन और जनमत तैयार कर रहे हैं. मीडिया की नज़रों में ये भले न आएं, लेकिन आज जिस महाक्रांति को जनता देख रही है, उसमें इनका सबसे बड़ा योगदान है. चौथी दुनिया ने टीम अन्ना के कुछ ऐसे ही सहयोगियों और उनके योगदान को आपके सामने लाने की कोशिश की है...

शशि शेखर

आप जैसे ही अरविंद केजरीवाल के दफ्तर ग़ाज़ियाबाद के कौशांबी स्थित पीसीआरएफ पहुंचते हैं, वहां आपको कई युवा लैपटॉप से जूझते नज़र आएंगे. कोई मोबाइल पर निर्देश देता नज़र आएगा तो कोई बैनर-पोस्टर संभालता हुआ. दरअसल ये सभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले चल रहे जन लोकपाल आंदोलन की तैयारी में व्यस्त हैं. दरअसल कम ही लोगों को यह बात मालूम है कि इसी दफ्तर से अन्ना के अनशन या कहें महाक्रांति का पूरा खाका तैयार होता है, समूची रणनीति तैयार की जाती है. असल में आज अन्ना का जो आंदोलन इतना बड़ा स्वरूप अख्तियार कर चुका है, उसकी जमीन इस साल के जनवरी माह से ही बननी शुरू हो गई थी. जनवरी में रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की रैली के बाद ही अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को बताया था कि वह जन लोकपाल के मुद्दे पर अनशन करने जा रहे हैं. ज़ाहिर सी बात थी कि अन्ना के अनशन, उनके आंदोलन की पूरी ज़िम्मेदारी अरविंद केजरीवाल पर ही थी और अरविंद केजरीवाल को अपने इन्हीं साथियों पर भरोसा था, जो बिना कोई सवाल किए, पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम करना जानते हैं.

यह हैं नीरज कुमार. अरविंद के पुराने सहयोगियों में से एक. यह आरटीआई पर 2002 से काम कर रहे हैं, जब केंद्रीय आरटीआई कानून 2005 अस्तित्व में भी नहीं आया था. तब एनसीपीआई के शेखर सिंह के साथ यह सूचना अधिकार क़ानून की लड़ाई में शामिल थे. आरटीआई हेल्पलाइन से लेकर नेशनल

आरटीआई अवॉर्ड तक की कमान संभाल चुके हैं. फिलहाल अन्ना के आंदोलन में नेशनल को-ऑर्डिनेशन टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. साथ ही अन्ना के लिए अनशन स्थल, प्रेस कांफ्रेंस के लिए जगह, पुलिस एवं अन्य सरकारी एजेंसियों से अनुमति लेने की जिम्मेदारी इन्हीं की है. नीरज कुमार अन्ना के अनशन-आंदोलन के दौरान पुलिस और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बीच संवाद सूत्र की भूमिका में भी हैं. आंदोलन के दौरान नीरज कुमार देश भर से आए अन्ना के समर्थकों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी काम कर रहे हैं. देश भर के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम काफी धैर्य की मांग करता है, क्योंकि इस काम में लगातर मोबाइल फोन पर व्यस्त रहना पड़ता है. बीते 16 अगस्त को जब अन्ना को गिरफ्तार किया गया, तब नीरज देर रात यानी अगली सुबह 4 बजे तक समर्थकों को मोबाइल पर पल-पल की खबर देते रहे और बताते रहे कि उन्हें अब क्या करना है. दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेने और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले ऋषिकेश कुमार पर वैसे तो पीसीआरएफ के लीगल सेल की जिम्मेदारी है, लेकिन आजकल वह अन्ना के आंदोलन को सफल बनाने के लिए छात्रों, खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को लामबंद करने में लगे हुए थे और अभी भी इस काम में जुटे हुए हैं. जाहिर है, उनकी मेहनत का नतीजा अभी देखने को मिला, जब अन्ना की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों युवा दिल्ली की सड़कों पर उतर आए. इनमें अधिकांश डीयू के छात्र थे. इस आंदोलन को लेकर ऋषिकेश कितने जोश में हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने अन्ना की गिरफ्तारी के विरोध में खुद अपनी भी गिरफ्तारी दी थी. अरविंद की एक और पुरानी सहयोगी हैं स्वाति मालिवाल. स्वाति पिछले कई सालों से आरटीआई और पंचायती राज संस्था में सुधार पर काम कर रही हैं. अन्ना के आंदोलन के लिए जमीन तैयार करने में उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है. स्वाति के जिम्मे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वालंटियर्स को संगठित रखने और उन्हें आंदोलन से जुड़े हर एक निर्णय से अवगत कराने का काम है. इसके अलावा वह जगह-जगह जाकर लोगों को जन लोकपाल बिल के बारे में बताती और इस लड़ाई में शामिल होने के लिए लोगों का आह्वान करती रही हैं. किसी भी आंदोलन की सफलता में मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता. सो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए भी पीसीआरएफ में बाकायदा एक मीडिया सेल है. इस मीडिया सेल में वैसे तो मीडिया के कई लोग समय-समय पर आते-जाते रहे हैं, लेकिन स्थायी तौर पर इस सेल की ज़िम्मेदारी आस्वति मुरलीधरन की है. हर एक दिन, हर एक घंटे की खबर मीडिया के पास पहुंचाना, प्रेस रिलीज तैयार करना, रिपोर्टरों से बातचीत करना उनकी जिम्मेदारी है. ज़ाहिर है, आस्वति अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रही हैं और इसमें उनकी पत्रकारिता की पढ़ाई काम आ रही है. आस्वति 2006 में भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुकी हैं. साथ ही वह एक ट्रेड यूनियन जर्नल के लिए भी काम कर चुकी हैं. मीडिया मैनेजमेंट के इस काम में आस्वति के साथ स्नेहा का योगदान भी महत्वपूर्ण है. अन्ना के आंदोलन की सफलता के पीछे एक बड़ी वजह फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल वेबसाइट्स और एसएमएस जैसी तकनीक को भी माना जा रहा है, लेकिन शायद कम ही लोगों को यह पता होगा कि इस सबके पीछे कौन है. कौन इस तकनीक के सहारे लोगों को आंदोलन से जोड़ रहा है. दरअसल, इस काम के पीछे भी एक पत्रकार है. नाम है शिवेंद्र सिंह चौहान. नौकरी छोड़कर शिवेंद्र इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम से जुड़ गए. फेसबुक और ट्विटर पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से पेज बनाकर लाखों लोगों तक पल-पल की ख़बर पहुंचाई जा रही है और इसका परिणाम भी काफ़ी सुखद रहा है. अन्ना के आंदोलन में युवाओं की बढ़ती भागीदारी के पीछे तकनीक के इस्तेमाल का भी बड़ा योगदान रहा है और इसके लिए शिवेंद्र सिंह चौहान बधाई के पात्र माने जा सकते हैं. अगर बात तकनीक की हो रही है तो आजकल ब्लॉग भी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक अच्छा ज़रिया बन गया है. जन लोकपाल से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने एक ब्लॉग भी बनाया है, जिसकी देखरेख का ज़िम्मा जावेद के पास है. जावेद तकनीक के अच्छे जानकार माने जाते हैं और वह इस ब्लॉग को बखूबी संभाल रहे हैं. जावेद एक अच्छे ग्राफिक्स डिजाइनर भी हैं और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम के लिए एक से बढ़कर एक कार्टून और बैनर आदि भी डिजाइन कर चुके हैं. किसी भी आंदोलन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं पर्चे, पोस्टर और बैनर. लोगों तक अपनी बात पहुंचाने, उन्हें समझाने का एक आसान ज़रिया. दिल्ली में जगह-जगह ये पर्चे, पोस्टर और बैनर पहुंचें और समय पर पहुंचें, इसकी ज़िम्मेदारी है राम कुमार झा की. जब आप राम कुमार को पसीने में लथपथ होकर पोस्टर-बैनर उठाते हुए, पर्चे बांटते हुए देखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अन्ना टीम का यह कार्यकर्ता डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुका है, एनसीसी और एनएसएस से जुड़ा रहा है. राम कुमार पीसीआरएफ में नेशनल आरटीआई अवॉर्ड टीम के लिए आए थे, लेकिन यह उनकी लगन और मेहनत है, जो योग्यता के घमंड से कोसों दूर रहकर वह वैसा काम कर रहे हैं, जिसे आम तौर पर तथाकथित पढ़े-लिखे लोग नहीं करना चाहते हैं. राम कुमार के ही साथी हैं अमित मिश्रा, जो एमबीए की पढ़ाई कर चुके हैं और पीसीआरएफ में नेशनल आरटीआई अवॉर्ड टीम के हिस्सा थे, लेकिन अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की हेल्पलाइन को संभालते हैं और देश भर के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं. अमित के अलावा इस काम में शालू भी अपना योगदान देती हैं.

अन्ना के आंदोलन की शुरुआती सफलता के बाद कई लोग इससे ख़ुद को जोड़ने लगे. बड़े-बड़े लोग. इस उम्मीद में कि इससे उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा और सच भी यही है. आज ऐसे कई लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो इसके शुरुआती दिनों में साथ नहीं थे, लेकिन जब आंदोलन की आग फैली तो नए चेहरे भी सामने आने लगे. ख़ैर, किसी भी आंदोलन के साथ ऐसा ही होता है. लेकिन अन्ना का आंदोलन अगर देश में कोई परिवर्तन लाता है और कुछ अच्छा होता है तो इसका श्रेय पर्दे के पीछे के इन नायकों को भी दिया जाना चाहिए. पर्दे के पीछे के इन नायकों का नाम इतिहास में दर्ज हो या न हो, लेकिन इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा.

shashishekhar@chauthiduniya.com

आज अन्ना का जो आंदोलन इतना बड़ा स्वरूप अख्तियार कर चुका है, उसकी जमीन इस साल के जनवरी माह से ही बननी शुरू हो गई थी. जनवरी में रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की रैली के बाद ही अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को बताया था कि वह जन लोकपाल के मुद्दे पर अनशन करने जा रहे हैं. जाहिर सी बात थी कि अन्ना के अनशन, उनके आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल पर ही थी और अरविंद केजरीवाल को अपने इन्हीं साथियों पर भरोसा था, जो बिना कोई सवाल किए, पर्दे के पीछे रहकर सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना जानते हैं.

कुपोषण और भुखमरी का शिकार समाज का एक बड़ा तबका एक वक़्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरी तरफ़ लाखों टन अनाज की बर्बादी!

भारतीय खाद्य निगम

लापरवाही, मनमानी और भ्रष्टाचार का गढ़

अभिषेक रंजन सिंह

साढ़े पांच दशक पूर्व कई लोक कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया गया भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) आज लापरवाही, मनमानी और भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है. देश का अन्नदाता किसान आज भुखमरी का शिकार है, बदहाली का शिकार है और आत्महत्या जैसे फ़ैसले लेने के लिए मजबूर है, लेकिन उसी के पसीने से उपजा लाखों टन अनाज एफसीआई प्रबंधन की बदइंतज़ामी और बदनीयती के चलते खुले आसमान के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है. देश भर में एफसीआई के क़रीब 1451 गोदाम हैं, जो ज़रूरत के हिसाब से काफी कम हैं. केंद्र सरकार हर साल कुल कृषि उत्पादन का क़रीब 15 से 20 प्रतिशत हिस्सा यानी गेहूं और चावल ख़रीदती है. एफसीआई प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हज़ारों टन अनाज बेहतर भंडारण के अभाव में सड़ जाता है. अनाज की इस बर्बादी के चलते देश की करोड़ों ग़रीब जनता भले ही दो वक़्त की रोटी से वंचित हो जाए, लेकिन भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन के लिए अनाज का सड़ना काफी फ़ायदेमंद है. चौथी दुनिया ने जब एफसीआई के गोदामों का जायज़ा लिया तो प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई. एफसीआई द्वारा ख़रीदा गया लाखों टन अनाज गोदामों, रेलवे प्लेटफार्म और सड़कों पर यूं ही खुले आसमान के नीचे बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाता है. बारिश में भीगने की वजह से अनाज इस क़दर ख़राब हो जाता है कि वह किसी के खाने लायक़ नहीं रहता. आंकड़ों के मुताबिक़, बीते जनवरी माह में एफसीआई के गोदामों में 10,688 लाख टन अनाज सड़ा हुआ पाया गया. अनाज की यह मात्रा 10 वर्षों तक छह लाख लोगों के भोजन के लिए पर्याप्त थी. 1997 और 2007 के बीच 1.83 लाख टन गेहूं, 6.33 लाख टन चावल, 2.20 लाख टन धान और 111 लाख टन मक्का भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में ख़राब हो गया. एफसीआई के गोदामों में अनाज के समुचित भंडारण के लिए पर्याप्त जगह है. फिर भी बड़ी मात्रा में अनाज गोदाम परिसर में खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है.

अनाज की यह बेकद्री देखकर आम आदमी भले ही अपना माथा पीट ले, लेकिन भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हर साल एफसीआई के गोदामों में बर्बाद होने वाला हज़ारों-लाखों टन अनाज शराब उत्पादन में इस्तेमाल होता है. देश की जनता भूखी है और एफसीआई प्रबंधन एवं शराब माफ़िया मालामाल हो रहे हैं. एफसीआई की अनाज भंडारण प्रणाली की खामियों के बारे में जब अदालत और सामाजिक संगठनों द्वारा आपत्तियां दर्ज़ कराई जाती हैं तो वह गोदामों की कमी का रोना रोता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके कई गोदामों में अनाज की जगह शराब का भंडारण हो रहा है, क्योंकि वह जगह उसने किसी और को किराए पर

दे रखी है. एफसीआई में भ्रष्टाचार का आलम यह है, दूसरी ओर केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने की तैयारी में है. वह ऐसा किसके भरोसे करने जा रही है, यह बात समझ से परे है. उल्लेखनीय है कि एफसीआई किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और धान की ख़रीद करती है और ख़रीदे हुए अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से जारी करती है. इसके अलावा क़ीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुला बाज़ार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के ज़रिए बाज़ार में गेहूं की बिक्री करती है. गेहूं और चावल का मित्र देशों को निर्यात भी एफसीआई के भंडारों से ही होता है. इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम मोटे अनाजों और चीनी की भी ख़रीद करती है. चीनी की आपूर्ति कई राज्यों में पीडीएस के माध्यम से की जाती है, जबकि मोटे अनाजों की बिक्री खुले बाज़ार में निविदा के ज़रिए होती है. इस ख़रीद-फरोख्त में भी जमकर धांधली होती है.

आर्थिक संकट

कुप्रबंधन के चलते आज हालत यह है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिससे निजात पाने के लिए उसे केंद्र सरकार से तत्काल करोड़ों रुपये की सख्त दरकार है. यह धन उसे गोदामों में अटे पड़े अनाज के रखरखाव, रबी सीजन में गेहूं की ख़रीद के बकाया भुगतान और चालू खरीफ की फ़सल में धान की ख़रीद के लिए चाहिए. उसने केंद्र सरकार से तत्काल मदद करने की गुहार की है.

गोदामों की क्षमता

एफसीआई के छत वाले गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 225.64 लाख टन है और वहां रखे गए अनाज की कुल मात्रा 218.35 लाख टन है. उत्तर क्षेत्र में एफसीआई के छत वाले गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 127.48 लाख टन है, जबकि उनमें महज़ 111.22 लाख टन अनाज ही रखा गया है. दक्षिणी राज्यों में गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 57.39 लाख टन है, जबकि वहां रखे कुल अनाज की मात्रा 54.24 लाख टन है. पूर्वी राज्यों में गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 23.99 लाख टन है, जबकि वहां मात्र 17.10 लाख टन अनाज रखा गया है. पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित गोदामों में 4.48 लाख टन अनाज रखा जा सकता है, जबकि वहां मौजूद अनाज की मात्रा केवल 3.50 लाख टन है. पश्चिमी राज्यों में स्थित गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 43.30 लाख टन है, जबकि वहां रखे अनाज की मात्रा केवल 32.29 लाख टन है. एफसीआई के गोदामों में अनाज भंडारण की पर्याप्त क्षमता है. फिर भी बड़ी मात्रा में अनाज यहां-वहां सड़ रहा है. अपने गोदामों में पर्याप्त जगह होने के बावजूद एफसीआई बिचौलियों के माध्यम से प्राइवेट गोदाम और वेयर हाउस किराए पर ले रहा है. जानकार सूत्रों का कहना है कि इस काम के लिए आला अफसरों को मोटा कमीशन मिलता है. एफसीआई प्रशासन को दोहरा फ़ायदा हो रहा है. पहला तो यह कि वह जगह की कमी बताकर प्राइवेट गोदाम और वेयरहाउस किराए पर लेता है और उसमें कमीशनबाज़ी होती है तथा दूसरा यह कि सड़ा अनाज कौड़ियों के मोल शराब उत्पादकों को बेचने से वहां भी मोटी मलाई हाथ आ जाती है.

खाद्य सुरक्षा विधेयक और एफसीआई

आम आदमी को भरपेट भोजन का क़ानूनी हक़ देने के लिए खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा. सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सुझाव पर अमल किया तो अगले कुछ महीनों बाद 72 प्रतिशत जनता को 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल मिलने लगेगा, लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर का अंदाज़ा अनाज की सरकारी ख़रीद, उसके भंडारण और वितरण से जुड़ी अनियमितता को देखकर सहज लगाया जा सकता है. अनाज की ख़रीद-बिक्री के मामले में एफसीआई के अधिकारियों के भी अपने कुछ खेल हैं. कुछ महीने पहले विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार जितना पैसा लगाती है, उसका 40 फ़ीसदी ही अनाज की शक्ल में लोगों तक पहुंच पाता है. इतने छिद्रों से भरी भ्रष्ट और लचर व्यवस्था के तहत लाया जा रहा खाद्य सुरक्षा क़ानून लोगों का पेट भर देगा, इसकी कोई उम्मीद फ़िलहाल तो नहीं दिखती. कुपोषण और भुखमरी का शिकार समाज का एक बड़ा तबका एक वक़्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरी तरफ़ लाखों टन अनाज की बर्बादी! यह स्थिति लोक कल्याण का दंभ भरने वाली सरकार और उसकी नीतियों पर सवाल खड़े करती है. आंकड़ों के अनुसार, देश की 21 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी ग़रीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी में आती है. पांच साल से कम आयु के सात फ़ीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वहीं 52 फ़ीसदी महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं.

अनाज सड़ने के कारण

एक रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत का अनाज प्रबंधन संकट में है. पिछले कुछ वर्षों में खपत की तुलना में भारी स्टॉक जमा हो गया है. एफसीआई के गोदामों में जगह की कथित कमी, कोल्ड स्टोरेज का अभाव, गोदामों का दूसरे कामों में उपयोग और उचित प्रबंधन न होने से अनाज सड़ रहा है. कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल अपने कोल्ड स्टोरेज में भर रखा है. इस वजह से सरकारी अनाज रेलवे स्टेशनों पर खुले आसमान के नीचे पड़े-पड़े ख़राब हो रहा है. हालांकि सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से अनाज का भंडारण करने की बात कही है. कोल्ड स्टोरेज के संबंध में उसने एक योजना विजन-2015 तैयार की है, जिसके तहत गोदामों में अनाज के संरक्षण की ज़िम्मेदारी इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईजीएमआरआई) को सौंपी गई है.

भारत में खाद्यान्न उत्पादन

हमारा देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित है और इसकी 60 फ़ीसदी से अधिक आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है. हालांकि पिछले पांच दशकों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान अन्य सेवा क्षेत्रों की तुलना में घटा है, लेकिन अभी भी जीडीपी में इसकी अहम भूमिका है. यही वजह है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 4 फ़ीसदी विकास दर का लक्ष्य रखा गया है.

महंगाई की आग

विवाद और शरद पवार के बीच काफी नज़दीकी रिश्ता है. एफसीआई के गोदामों में सड़ते अनाज के बारे में कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का अक्षरश: पालन नहीं किया जा सकता. अनाज भले ही सड़ जाए, लेकिन उसे मुफ़्त में ग़रीबों को देना संभव नहीं है. भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, इसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एवं मध्य प्रदेश के गोदामों में जाकर देखा जा सकता है. पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जिस देश में हज़ारों लोग भूखे मर रहे हों, वहां अन्न के एक दाने की बर्बादी भी अपराध है. इस पूरे मामले में हम भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली को क्लीन चिट नहीं दे सकते. एफसीआई के गोदामों में क्या हो रहा है, इस पर नज़र रखने का काम प्रबंधन को करना चाहिए, लेकिन इस मामले में वह पूरी तरह असफल रहा है.

arsingh@chauthiduniya.com

वर्कर्स यूनियन की नाराज़गी

भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन ख़ुद को चाहे जितना पाक-साफ बताए, लेकिन यहां कार्यरत हज़ारों मज़दूर उनकी बातों से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते. एफसीआई हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन का कहना है कि अधिकारियों के लिए यह जन्नत साबित हो रहा है, वहीं यहां काम करने वाले मज़दूरों की हालत बदतर होती जा रही है. यूनियन के अध्यक्ष हरिकांत शर्मा का कहना है कि यहां कार्यरत मज़दूरों के चार वर्ग हैं. पहले नंबर पर विभागीय कर्मचारी हैं, जिनकी देश भर में कुल संख्या 20 हज़ार है. दैनिक वेतनभोगी मज़दूरों की संख्या 31 हज़ार है. नो वर्क-नो पे व्यवस्था के अंतर्गत कुल कामगारों की संख्या 3 हज़ार है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले मज़दूरों की कुल संख्या 25 हज़ार है. विभागीय कर्मचारियों को छोड़कर बाक़ी कामगारों की हालत काफी दयनीय है. यूनियन की प्रमुख मांगों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) लागू करना, नोटिफाइड डिपो में नो वर्क पे सिस्टम लागू करना, समस्त श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी देना, पहले की तरह विभागीय अथवा डीपीएस के मृत श्रमिकों के आश्रितों को अनुकंपा केआधार पर नौकरी देना, बोनस संशोधन अध्यादेश 2007 के अनुसार डीपीएस और नो वर्क-नो पे में कार्यरत श्रमिकों को बढ़ी हुई दर से बोनस, एक्सग्रेशिया का भुगतान, ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करना और बंद पड़े रेल साइडिंग को दोबारा खोलना आदि शामिल हैं. यूनियन का आरोप है कि भारतीय खाद्य निगम ऐसी निरंकुश संस्था है, जो न अदालत का फ़ैसला मानती है और न सरकार के निर्देशों का पालन करती है. ग़लत नीतियों की वजह से हर साल हज़ारों टन अनाज खराब हो जाता है. गोदामों की कथित कमी की आड़ में एफसीआई प्रबंधन कमीशनबाज़ी कर रहा है. कुछ साल पहले विशेष ज़रूरत पड़ने पर 1 रुपये 20 पैसे प्रति स्क्वायर फीट की दर से प्राइवेट गोदाम किराए पर लिए जाते थे, वहीं अब सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए 3 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से गोदाम किराए पर लिए जा रहे हैं. हैरत की बात यह है कि एफसीआई अपने गोदाम दूसरों को किराए पर दे रहा है. यूनियन का कहना है कि पिछले कई वर्षों से एफसीआई प्रबंधन नए मज़दूरों की भर्ती नहीं कर रहा और श्रमिकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है. प्रबंधन की मंशा है कि श्रमिकों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती चली जाए, ताकि ठेके पर मज़दूरों को रखने का रास्ता साफ हो जाए. पिछले पांच वर्षों के दौरान 6 हज़ार अधिकारियों की नियुक्तियां की गईं, लेकिन मज़दूरों की नहीं. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के महासचिव और राज्यसभा सदस्य तपन सेन ने केंद्र सरकार को मज़दूर विरोधी क़रार देते हुए कहा कि वह बिचौलियों के हाथों में खेल रही है. सरकार नहीं चाहती कि एफसीआई की पहचान एक मज़बूत और पारदर्शी संस्था के रूप में हो. सेन के मुताबिक़, एफसीआई वर्कर्स यूनियन के हक़ों की खातिर देश की सभी ट्रेड यूनियनें एकजुट हैं.

ये टांगिया मज़दूर परिवार वनाधिकार क़ानून के तहत जिन ज़मीनों पर अपना दावा कर रहे थे, उन पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना इनकी मर्ज़ी के पौधारोपण करा दिया गया था.

जम्मू-कश्मीर

आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति

शाहजहां अफ़ज़ल

धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर को न जाने किसकी नज़र लग गई है. कुदरत के अनमोल उपहारों से सजी इस धरती की संस्कृति पर इतिहास को हमेशा गर्व रहा है. आधुनिक परिवेश में शिक्षा हासिल करने के बावजूद यहां के नौजवान कभी भी बड़े-बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान के पाठ को नहीं भूले. यही कारण है कि उनकी छत्रछाया में जीवन की कठिन से कठिन डगर को भी वे आसानी से पार कर पाने में सक्षम रहे. उग्रवाद की गुमराही के शिकार नौजवानों ने जब अपनों के ख़िलाफ़ बंदूक उठाई तो इन्हीं बुजुर्गों के स्नेह ने उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटने की राह को आसान बनाया. लेकिन इन दिनों कश्मीर का जो मंजरनामा है, वह कोई और ही दास्तां बयां करता है. जिस नई नस्ल पर कश्मीर की संस्कृति नाज करती थी, अब उसी के आचरण में ख़तरनाक तब्दीली देखने को मिल रही है. धैर्य रखना, संघर्ष और बर्दाश्त करने की ताक़त की जगह नई पीढ़ी जीवन की नई परिभाषा गढ़ती जा रही है. अपने अलावा किसी अन्य के दृष्टिकोण को सिरे से ख़ारिज करना और मुश्किलों के समय स्वयं को असहाय महसूस करना आम बात होती जा रही है.

युवाओं में इस बात की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है कि चुनौतियों से लड़ने के बजाए ज़िंदगी को ही समाप्त कर लेना सभी समस्याओं का हल है. यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में राज्य में आत्महत्या करने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. ऐसा ख़तरनाक क़दम उठाने वालों में महिलाओं की संख्या काफ़ी है. एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 17 सालों में कश्मीर के क़रीब 24 हज़ार लोगों ने आत्महत्या के प्रयास किए, जिनमें तीन हजार कामयाब रहे. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें अधिकतर की उम्र 16-25 वर्ष की है. इस वर्ष के पहले छह महीनों में अब तक कश्मीर में करीब तीन दर्जन से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की. इनमें 12 की जान नहीं बचाई जा सकी. इस प्रवृत्ति में हर साल वृद्धि देखी जा रही है. आत्महत्या करने वालों में 60 प्रतिशत महिलाएं थीं, जिनमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से हैं. उत्तरी कश्मीर के हिंदवारा और कुपवाड़ा क्षेत्रों में ही इस वर्ष के पहले छह महीनों में एक दर्जन से अधिक नौजवान लड़के- लड़कियों द्वारा आत्महत्या जैसे ख़तरनाक कदम उठाने के मामले दर्ज किए गए हैं. जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ऐसे केवल 9 मामले ही सामने आए थे.

राष्ट्रीय अपराध लेखा ब्यूरो के अनुसार, हर वर्ष विश्व में आत्महत्या करने वालों में 20 प्रतिशत भारतीय होते हैं. ब्यूरो की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रत्येक चार मिनट पर एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है. अकेले 2009 में देश में एक लाख 27 हजार 151 लोगों ने अपनी जीवन लीला अपने हाथों समाप्त कर ली, जो 2008 की तुलना में 1.7 प्रतिशत अधिक है. आत्महत्या करने वालों की औसत आयु राष्ट्रीय स्तर पर 15-44 वर्ष है. जबकि जम्मू-कश्मीर में यह 18-40 वर्ष के बीच है. आत्महत्या के कारणों पर गौर करें तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं पाई जातीं. रिपोर्ट के अनुसार, अधिकतर आत्महत्याएं घर में डांट, पारिवारिक कलह, बेरोजगारी अथवा साथी से मनमुटाव जैसी छोटी-छोटी बातों की वजह से की जाती हैं. बीती 21 जून को कश्मीर के हिंदवारा अंतर्गत पुजवां ब्लॉक निवासिनी रुखाना ने महज इसलिए आत्महत्या की कोशिश की, क्योंकि उसके और पति के बीच मोबाइल फोन के लिए झगड़ा हुआ था. तीन दिनों बाद इसी जिले के दर्दपुरा निवासिनी एक 20 वर्षीय युवती ने घरेलू कामकाज को लेकर माता-पिता की डांट के बाद जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी. शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ सैयद अमीन ताबिश के अनुसार, घाटी के 65 प्रतिशत लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जो उन्हें आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है. खतरनाक रूप से बढ़ती इस नकारात्मक प्रवृत्ति ने सबको चिंता में डाल दिया है. बार-बार यह प्रश्न उठने लगा है कि आख़िर युवा पीढ़ी को स्वयं को समाप्त कर लेना ही समस्या का हल क्यों नज़र आने लगा है.

विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे कई कारण हैं. कश्मीर विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्राध्यापक मंज़ूर अहमद कहते हैं कि बदलते सामाजिक परिवेश में युवा पीढ़ी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना धैर्य और लगन के साथ किया जा सकता है, लेकिन युवाओं में सहनशक्ति समाप्त होती जा रही है.

विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे कई कारण हैं. कश्मीर विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्राध्यापक मंजूर अहमद कहते हैं कि बदलते सामाजिक परिवेश में युवा पीढ़ी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना धैर्य और लगन के साथ किया जा सकता है, लेकिन युवाओं में सहनशक्ति समाप्त होती जा रही है. घर और समाज के बढ़ते दबाव के बीच उन्हें स्वयं को साबित करना होता है और ऐसा कर पाने में असफल नौजवान अपनी जिंदगी को बेकार समझ लेते हैं. इसके अलावा तनाव, बेरोजगारी और ख़ौफ़ भी आत्महत्या को बढ़ावा देने में अहम साबित हो रहे हैं. कुपवाड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुलाम नबी जान के अनुसार, आत्महत्या के लिए पारिवारिक कलह के साथ-साथ टीवी संस्कृति को भी बहुत हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है, जिसने परस्पर संवाद को खत्म कर दिया है. हर कोई टीवी के कार्यक्रमों के अनुसार अपनी दिनचर्या निर्धारित करने लगा है. परिणामस्वरूप किसी के पास इस बात की फुर्सत नहीं होती है कि वह टूटते-बिखरते युवाओं की भावनात्मक जरूरतों को समझे. कहते हैं कि जीवन प्रकृति का दिया सबसे अनुपम उपहार है, जिसमें खुशी और गम, सफलता और असफलता का आना-जाना लगा रहता है. कठिनाइयों का मुक़ाबला हौसले और जज्बे के साथ किया जाता है. अगर यह सच है तो आज की युवा पीढ़ी में इसका अभाव क्यों होता जा रहा है? ऐसे कौन से कारण हैं, जिन्होंने उन्हें आत्महत्या को कठिनाइयों से बचने का शॉर्टकट रास्ता बताया है. बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, जिनके जवाब अगर जल्द नहीं खोजे गए तो परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं. (चरखा)

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

उत्पीड़न के ख़िलाफ़ वन गूजरों का आंदोलन

रजनीश

बीते 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में वन टांगिया महिलाओं ने एक बार फिर प्रशासन के जोर-जुल्म के खिलाफ जोरदार आंदोलन करके उन चार मजदूरों को रिहा करा लिया, जिन्हें डिप्टी रेंजर की फर्जी-झूठी तहरीर के आधार पर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था. जानकारी के अनुसार, बीते 13 अगस्त को तहसील मनकापुर के वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा बसाए गए बुटाहनी टांगिया गांव से 4 लोगों खुशीराम, शिवराम, अमर सिंह और रामरंग को डिप्टी रेंजर अच्छेवर यादव की झूठी तहरीर के आधार पर गिरफ़्तार कर लिया गया था. खुशीराम वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन को लेकर पूरी जागरूकता और जानकारियों के साथ क्षेत्र में सक्रिय है. इस गिरफ्तारी के विरोध में यहां के टांगिया गांवों बुटाहनी, अशरफाबाद और मनीपुर की सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों ने थाना छपिया का घेराव कर लिया और पूरी रात बरसात में भीगते हुए वन विभाग एवं पुलिस-प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाज़ी की. यह घेराव और नारेबाज़ी अगले दिन शाम तक गिरफ़्तार किए गए चारों लोगों की रिहाई होने तक जारी रही. महिलाओं ने ऐलान कर दिया कि जब तक उनके साथी मज़दूरों को बाइज़्ज़त बरी नहीं किया जाएगा, तब तक वे घेराव खत्म नहीं करेंगी. थानाध्यक्ष सिकंदर यादव द्वारा चालान काटकर चारों लोगों को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच के साथ मिलकर वनाधिकारों के लिए पिछले काफी समय से आंदोलनरत टांगिया वन मज़दूर महिलाओं और उत्तर प्रदेश निगरानी समिति की विशेष आमंत्रित सदस्य रोमा द्वारा विरोध किए जाने पर ज़िलाधिकारी से विचार-विमर्श करने के बाद चारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.

बीते 29 जून को गोंडा से 600 किलोमीटर दूर सहारनपुर में वन गूजर एवं वनाधिकार कार्यकर्ता नूर जमाल को भी ठीक इसी तरह वन विभाग के रेंजर की तहरीर पर थाना बेहट पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था. वन विभाग के इशारे पर राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस-प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाइयां आम बात हो गई हैं. गोंडा की तहसील मनकापुर के वन क्षेत्र में बसे टांगिया गांव बुटाहनी के खुशीराम, शिवराम, अमर सिंह और रामरंग के खिलाफ डिप्टी रेंजर द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के तहत दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर इन चारों को गिरफ़्तार कर लिया. यह कार्रवाई थाना छपिया पुलिस द्वारा की गई, जबकि बुटाहनी गांव थाना मनकापुर क्षेत्र में आता है. इससे आक्रोशित महिलाओं-पुरुषों ने रात को ही थाने का घेराव कर लिया और पुलिस एवं वन विभाग के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की. सूचना मिलने के बावजूद कोई भी आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने नहीं आया. छपिया थानाध्यक्ष सिकंदर यादव का कहना था कि 80 हज़ार रुपये का जुर्माना जमा कराने पर ही इन्हें छोड़ा जाएगा, वरना चालान काट दिया जाएगा.

दरअसल ये टांगिया मज़दूर परिवार वनाधिकार क़ानून के तहत जिन ज़मीनों पर अपना दावा कर रहे थे, उन पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना इनकी मर्जी के पौधारोपण करा दिया गया था. इसके पूर्व भी इन मजदूरों की खेती की ज़मीनों पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर अच्छेवर लाल यादव द्वारा टांगिया पद्धति से पौधारोपण का कार्य कराया जाता रहा है. वह 100 एकड़ से अधिक ज़मीन पर कब्जा करके इन्हीं मज़दूरों से बंधुआ के रूप में खेती करा रहा था. बीते साल जब राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच का एक स्वतंत्र जांच दल इन टांगिया गांवों में गया तो ये सारे तथ्य सामने आए. जांच दल में वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई राज्य निगरानी समिति की विशेष आमंत्रित सदस्य रोमा भी शामिल थीं. उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नेतराम, प्रमुख सचिव (वन) चंचल तिवारी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण बलविंदर सिंह से स्वयं मिलकर उनके समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की. ऊपर से सरकारी दबाव पड़ने पर अच्छेवर यादव को इन टांगिया मज़दूरों की ज़मीन छोड़नी पड़ी. इसके बाद से लगातार खुशीराम को अच्छेवर यादव जान से मारने और झूठा मुक़दमा दर्ज कराकर गिरफ़्तार कराने की धमकियां दे रहा था. सरकार के आदेश पर टांगिया गांवों में वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी ज़िलाधिकारी द्वारा तेज़ी से चलाई गई, लेकिन उपज़िलाधिकारी मनकापुर ने डिप्टी रेंजर अच्छेवर यादव एवं डीएफओ के बहकावे में आकर दावों की सुनवाई पर रोक लगा दी. दूसरी बात यह कि वनाधिकार क़ानून का प्रशिक्षण प्राप्त खुशीराम का उपज़िलाधिकारी से बहस करना भी उन्हें अखर गया. वन विभाग द्वारा क़रीब 10 दिनों पूर्व दी गई झूठी तहरीर के आधार पर पुलिस इन टांगिया मज़दूरों को गिरफ़्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही थी. खुशीराम पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहा है, कई दिनों तक वह स्थानीय अस्पताल में भर्ती भी रहा. बावजूद इसके पुलिस ने उसे और तीन अन्य मजदूरों को उनके घरों से उठा लिया.

एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार वन क्षेत्रों वाले ज़िलों में वन समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार कर बनाए गए वनाधिकार क़ानून को क्रियान्वित कराने के लिए प्रयासरत है. वह दुधवा के कोर जोन में बसे गांव सूरमा को राजस्व का दर्जा देने और गोरखपुर, महराजगंज एवं गोंडा में वन टांगिया गांवों को नियमित करने जैसे कई सराहनीय काम कर चुकी है, लेकिन वन विभाग सरकार की मंशा पर पलीता लगाने पर आमादा है और स्थानीय पुलिस-प्रशासन नियमों के विरुद्ध उसकी मदद कर रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में पिछले वर्ष आवंटित साढ़े तीन हज़ार से अधिक आवासों में से बीस-तीस फ़ीसदी आवास अधूरे हैं.

इंदिरा आवास योजना

जहां देखो वहां घपला

सुरेंद्र अग्निहोत्री

विकास का पहिया राजनीति के मकड़ जाल में उलझ कर आम आदमी के लिए कैसे परेशानियां पैदा करता है, इसे उत्तर प्रदेश में रहने वाले ग़रीबों से ज़्यादा कौन समझ सकता है. 1980 में ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत शुरू की गई इंदिरा आवास योजना अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नज़र आ रही है. केंद्र द्वारा मिलने वाले बजट से चल रही यह योजना राजनीतिक नामकरण के चलते प्रशासनिक उपेक्षा का दंश सहने को मजबूर है. भौतिक सत्यापन के दौरान हज़ारों इंदिरा आवास ढूंढे नहीं मिल रहे हैं. राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में जब योजना का भौतिक सर्वेक्षण किया गया तो अनेक चौंकाने वाले मामले प्रकाश में आए. नाम किसी के, रहता कोई और है. कहीं प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं, लेकिन इंदिरा आवास मिल गया है. सरकारी रिकॉर्ड में आवास दर्ज है, लेकिन हक़ीक़त में आवास नाम की चीज नहीं. कहीं-कहीं तो सरकारी कर्मचारियों ने निजी आवासों को भी इंदिरा आवास क़रार देने की कोशिश की. जनपद लखीमपुर खीरी के कजरिया गांव निवासी सेवाराम ने अपनी गाढ़ी कमाई से मकान बनवाया. एक दिन कुछ सरकारी कर्मचारी उस पर नीले रंग की पट्टी बनाकर इंद्रा लिखने लगे तो उसने पूछा कि उसका निजी मकान इंदिरा आवास योजना में कैसे आ गया. यह पूछते ही सरकारी कर्मचारी भाग खड़े हुए.

इसी जनपद के मितौली ब्लॉक के रामपुर मजरे में शिक्षा मित्र शिवराम ने कई पक्के मकान होने के बावजूद अलग-अलग नामों से पांच इंदिरा आवास हासिल कर लिए, जिन पर न नाम पट्टिकाएं हैं और न उनके बनने का वर्ष अंकित है. शिवराम के पांच भाइयों के बीच 30 बीघे की काश्तकारी है. पहले आवासीय पट्टे के तौर पर उन्हें ज़मीन आवंटित की गई, फिर मां लीलावती, भाभी निर्मला, राजेंद्री, विद्या देवी और भतीजे को इंदिरा आवास मिल गया. लखनऊ के माल ब्लॉक के ग्राम सालेह नगर निवासी जगन्नाथ की ख़ुशी का ठिकाना उस समय नहीं रहा, जब बीते वर्ष इंदिरा आवास के लाभार्थियों की सूची में उनका नाम आ गया, लेकिन जब वह मकान बनाने के लिए पैसा निकालने बैंक पहुंचे तो पता चला कि उन्हीं के नाम वाले एक आदमी ने ग्राम प्रधान की मिलीभगत से आवंटित धन निकाल लिया है. जगन्नाथ के सारे सपने एक पल में बिखर गए. ग्राम जिंदाना निवासी सुरेश पुत्र रामचरण के साथ भी यही हुआ. इंदिरा आवास के लिए उन्हें मिला पैसा गांव के ही एक युवक पाल पुत्र भगोले ने निकाल लिया. गांव नौबस्ता निवासी मोती को उसकी पत्नी के नाम पर इंदिरा आवास आवंटित हुआ, जबकि उसकी मृत्यु डेढ़ साल पहले हो चुकी थी. मोहनलालगंज के ग्राम करनपुर निवासिनी रामकुमारी पत्नी रामेश्वर को वर्ष 2003-04 में इंदिरा आवास आवंटित हुआ था. रामकुमारी बताती हैं कि 26 हज़ार रुपये मिलने थे, लेकिन मिले केवल सात हज़ार. उसमें केवल दीवार खड़ी हो पाई, छत बननी बाक़ी है. गोंडा जनपद में इंदिरा आवास के नाम पर बेघर लोगों के साथ खेल खेला जा रहा है. वर्षों पहले आवास निर्माण के लिए धनराशि तो दे दी गई, लेकिन क़रीब दो हज़ार आवास विभाग को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं. इसमें क़रीब पांच करोड़ रुपये से अधिक के गोलमाल की आशंका है. मैनपुरी में इंदिरा आवास पाने वाली सरोज कुमारी का कहना है कि सिर्फ़ नाम हो गया कि इंदिरा आवास मिल गया, मिलने वाली धनराशि का आधा हिस्सा तो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी खा गए और आवास आज भी अधूरा पड़ा है. उर्मिला देवी बताती हैं कि बेवा होने की वजह से उन्हें पिछले वर्ष इंदिरा आवास दिया गया था, जो अभी भी अधूरा है. आवास मंजूर कराने के लिए सात हज़ार रुपये पड़ोसी से उधार लेकर प्रधान को दिए थे. इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी ने अपनी जान-पहचान की दुकान से गिट्टी, बालू, सीमेंट और ईंटें दिलवाईं, जो काफी महंगी मिली थीं. इसके बाद आठ हज़ार रुपये और देने पड़े. अभी तक छत नहीं डलवा सकी. इंदिरा आवास आवंटन में हो रही धांधली को रोकने के लिए डीएम द्वारा ग्राम प्रधानों से पात्रों के नाम लेने के बाद गोपनीय तरीक़े से चयन करके चयनित लाभार्थियों को पत्र द्वारा आवास मिलने की सूचना देने का तरीक़ा निकाला गया. इसमें भी ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने सेंध लगा दी. उन्होंने भेजी गई सूची में आने वाले सभी लाभार्थियों से एडवांस कमीशन तय करने का फंडा निकाल लिया यानी जिसका चयन हो जाएगा, उसके पैसे रख लिए जाएंगे और जिसका नहीं होगा, उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे. वाराणसी में भी इंदिरा आवास योजना का यही हाल है. बीपीएल परिवारों की जितनी संख्या है, उसके पांच प्रतिशत लोग भी योजना से लाभांवित नहीं हो पा रहे हैं. नरऊर गांव की माया और मीरा अफसरों से इंदिरा आवास हेतु गुहार करते-करते थक गईं. कासमपुर निवासी जगदीश सैनी के पास आवास के नाम पर झोपड़ी है. मेहनत-मज़दूरी करके पेट पालते हैं. 2002 में बनी बीपीएल सूची में नाम न होने के कारण उन्हें इंदिरा आवास का पात्र नहीं माना गया.

राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में पिछले वर्ष आवंटित साढ़े तीन हज़ार से अधिक आवासों में से बीस-तीस फ़ीसदी आवास अधूरे हैं. कानपुर के पतारा, भीतरगांव, घाटमपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर और सरसौल ब्लॉक में इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची नहीं है. इन ब्लॉकों के 2772 लोगों को बिना प्रतीक्षा सूची के ही आवास बांटे गए. इलाहाबाद में भी इंदिरा आवास योजना में जमकर खेल हुआ. अपात्रों को आवास आवंटित कर दिए गए. सप्ताह भर पहले निगरानी समिति की बैठक में इरुवा ब्लॉक के हुलसा में 17 लोगों के आवंटन रद्द करने की बात कही गई, जिन्होंने ग़लत तरीक़े से आवास लिए. प्रतापगढ़ में छह माह पहले बाबागंज ब्लॉक के टिकरिया बुज़ुर्ग में आवास योजना का सत्यापन कराया गया तो 30 लाभार्थी ऐसे मिले, जिनके नाम पर दस लाख 50 हज़ार रुपये की रकम हड़प ली गई थी. मुज़फ़्फ़रनगर में इस साल केंद्र सरकार ने 3911 लोगों को इंदिरा आवास देने का निर्णय लिया था, लेकिन विभागीय अफसरों ने लक्ष्य कम कराकर 2500 करा लिया है. सहारनपुर के मुजफ्फराबाद ब्लॉक में तो बीपीएल सूची ही बदलने का मामला सामने आ चुका है. आगरा में इंदिरा आवास योजना में मानकों की जमकर अनदेखी हो रही है. 2010-11 में 3268 इंदिरा आवास बनवाए गए, लेकिन उनमें से किसी का सत्यापन नहीं किया गया. अलीगढ़ में इंदिरा आवास योजना के लिए 2002 में हुए सर्वे में 2391 ग़रीब मिले थे. इसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ. हाथरस में आज भी तमाम ग़रीब झोंपड़ी में निवास कर रहे हैं. बरेली में इस बार इंदिरा आवास पाने वाले ग़रीबों की संख्या पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगी. परियोजना निदेशक रामनरेश के मुताबिक़, राज्य सरकार ने अपना अंश जारी कर दिया है, केंद्र का हिस्सा नहीं आया. इसके चलते काम रुका है. कांग्रेस के पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य कहते हैं कि इंदिरा आवासों के प्रति सरकारी उदासीनता ग़रीबों पर भारी पड़ी है. हमारा दल के अध्यक्ष स्वदेश कुमार कहते हैं कि राजनीति और योजनाओं में जब तक अंतर नहीं किया गया जाएगा, तब तक विकास की किरण अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी.

बदायूं में इंदिरा आवास योजना घपले की भेंट चढ़ रही है. 2009-2010 में 8072 और 2010-11 में 5359 लोगों को आवास मिले. विभाग ने 45 हज़ार रुपये की दर से 24 करोड़ रुपये बांट दिए गए, लेकिन कमीशनखोरी की वजह से सभी आवास नहीं बन सके. मुरादाबाद मंडल में बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी चयन में खेल हुआ, जिसके चलते ज़रूरतमंद की जगह अच्छी काश्त (खेती) और ट्रैक्टर जैसे साधन रखने वाले ख़ुद को बीपीएल श्रेणी में गिनाकर लाभ ले रहे हैं. चित्रकूट में 987 में से 485 आवास गैर अनुसूचित जाति के लोगों को देकर लाखों रुपये का घोटाला किया गया. जब फाइलें खंगाली गईं तो पूर्व प्रभारी सीडीओ के कारनामे देखकर विभाग में खलबली मच गई. डीएम ने पूर्व सीडीओ के कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच शुरू करा दी है. चित्रकूट के सेवानिवृत्त परियोजना निदेशक एवं प्रभारी सीडीओ लाखन सिंह ने शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अनुसूचित जाति के ग़रीब पात्र लोगों का हक़ मारकर अपात्रों को इंदिरा आवासों का आवंटन कर दिया. अनुसूचित जाति के लोगों को साठ फ़ीसदी इंदिरा आवास आवंटित होने चाहिए, लेकिन 1645 आवासों में से लाखन सिंह ने सिर्फ़ 502 आवास अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित किए. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशम्भर प्रसाद निषाद कहते हैं कि इंदिरा आवास आवंटन का नियम यह है कि जो ग्राम्यवार स्थायी प्रतीक्षा सूची बनी है, उसके अनुसार क्रम से लाभार्थियों को आवास दिया जाना चाहिए था, लेकिन नियमों को दरकिनार करके 606 आवास उन्हें दे दिए गए, जिनका प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं है. बिजनौर में इंदिरा आवास पात्रता सूची में नाम होने का झांसा देकर चार ब्लॉकों की कई ग्राम पंचायतों में महिला-पुरुषों से वसूली का मामला उजागर हुआ. ऐसे कई लाभार्थी ब्लॉक कार्यालय आए और बताया कि आठ माह पूर्व उनसे तीन-तीन हज़ार रुपये वसूल किए गए, लेकिन आवास बनाने के लिए सरकारी सहायता उन्हें अभी तक नहीं मिली.

योजना क्या है

वर्ष 1985-86 में शुरू हुई इंदिरा आवास योजना के संबंध में ग्राम्य विकास विभाग के एक अपर आयुक्त बताते हैं कि 20 वर्गमीटर क्षेत्रफल में धूम्ररहित चूल्हा, एक कमरा, बरामदा एवं शौचालय बनाने के लिए लाभार्थी को 45 हज़ार रुपये का अनुदान मिलता है. पहली किस्त 33,500 रुपये की होती है और शेष राशि दूसरी किस्त के तौर पर दी जाती है. पूर्व में यह योजना केवल अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए थी, लेकिन वर्ष 1994-95 से इसमें ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले अन्य वर्गों को भी शामिल कर लिया गया. पिछले कुछ वर्षों में भवन निर्माण सामग्री के दामों में हुई बढ़ोत्तरी ने इंदिरा आवास के निर्माण में दिक्कतें पैदा कर दी हैं. लाभार्थी को मकान बनाने के लिए अव्वल ईंट 12 हज़ार रुपये प्रति तीन हज़ार की दर से दी जाती है. दस गुणे 12 फीट का कमरा और बरामदा बनाने के लिए 92 सौ ईंटों की ज़रूरत पड़ती है. 36 हज़ार से अधिक रुपये केवल ईंटों पर ख़र्च हो जाते हैं. सीमेंट, मौरंग और मज़दूरी आदि के लिए नौ हज़ार रुपये से भी कम राशि बचती है, जो नाकाफी है.

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच ने आदिवासी एवं दलित महिलाओं की अगुवाई में व्यवसायिक वृक्षारोपण का बहिष्कार करके उन पेड़ों को लगाने की मुहिम शुरू की है, जो समाज के काम आते हैं.

वनाधिकार क़ानून और महिलाएं

रोमा

देश को आज़ादी मिलने के साठ साल बाद 2006 में वनाश्रित समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने के लिए एक क़ानून पारित किया गया, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत निवासी (वनाधिकारों को मान्यता) क़ानून. यह क़ानून बेहद है. यह केवल वनाश्रित समुदाय के अधिकारों को ही मान्यता देने का नहीं, बल्कि देश के जंगलों एवं पर्यावरण को बचाने के लिए वनाश्रित समुदाय के योगदान को भी मान्यता देने का क़ानून है. इसमें वनभूमि एवं वनों पर महिलाओं के समान अधिकार को मान्यता देने की बात कही गई है. हालांकि क़ानून के अंदर अभी भी काफी कमियां हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस क़ानून ने समुदाय के वनों के अंदर सामुदायिक अधिकार, जैसे लघु वनोपज एवं अन्य अधिकारों को मान्यता दी है.

आधुनिकता के इस दौर में हम चाहे जितना महिला-पुरुष में ग़ैर बराबरी ख़त्म हो जाने की बात करते रहें, लेकिन आम समाज की तरह इस रोग के जीवाणु देश में जल, जंगल और ज़मीन पर लोगों के अधिकारों के संदर्भ में बने क़ानूनों में भी मौजूद हैं. वनाधिकार क़ानून आने से पहले जो क़ानून प्रचलित थे, जब उनमें संबंधित समुदायों को ही उपेक्षित रखा गया तो ऐसे में महिलाओं को अधिकार देने की बात ही बेमानी है. संविधान के अनुच्छेद 14 में महिला और पुरुष के बराबरी के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है तथा लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव को ग़ैर संवैधानिक माना गया हैं, लेकिन जब महिलाओं को जल, जंगल और ज़मीन का अधिकार देने की बात आती है तो देखने में आता है कि ऐसे तमाम क़ानूनों में महिलाओं की उपेक्षा ही की गई है. हाल में पारित हुए वनाधिकार क़ानून को छोड़कर किसी भी क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकारों को हमेशा उनकी संपत्ति के सवाल के साथ जोड़कर देखा जाता है. उन्हें सिर्फ़ पारिवारिक विरासत को लेकर बने क़ानूनों के आधार पर सीमित अधिकार दिए जाने की बात की जाती है. लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे मामलों में भी ज़्यादातर उन्हें स्वतंत्र रूप से अधिकार नहीं दिया जाता. कुल मिलाकर जिनसे महिलाओं का सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण हो सकता था और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती थी, उन अधिकारों को मान्यता देने में हमारी संसद और सरकारें नाकाम रही हैं.

वनाधिकार क़ानून में पहली बार वनों पर महिलाओं के मालिकाना हक़ की बात कही गई है और व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों पर भी महिलाओं के मालिकाना हक़ को दर्ज करने के क़ानूनी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वन एवं वन भूमि पर ग़रीब आदिवासियों का नियंत्रण स्थापित हो जाने के डर के चलते वन विभाग, प्रशासन, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने इन समुदायों को मालिकाना हक़ देने के लिए अभी तक कोई इच्छा नहीं दिखाई है. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शिवालिक जंगलों में घाड़ क्षेत्र की रहने वाली खेतिहर मज़दूर महिला सोना खिन्न होकर कहती है कि सरकार तो हमें चाहती ही नहीं. यह बयान पिछड़े इलाक़े में रहने वाली शिक्षा से वंचित एक आम औरत का है, लेकिन यह बयान एक बहुत बड़ी राजनीतिक सच्चाई की मुखर अभिव्यक्ति है. सरकार इन्हें इसलिए नहीं चाहती, क्योंकि वनाधिकार क़ानून की मंशा के अनुसार जब जंगल महिलाओं और वंचित समुदायों के मालिकाना हक़ में आ जाएंगे तो वह बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को बड़े पैमाने पर न तो कौड़ियों के दाम वन भूमि उपलब्ध करा पाएगी, न प्राकृतिक संसाधनों का कोई सौदा होगा और न वन विभाग, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों एवं माफ़ियाओं-दलालों आदि को जंगल से किसी तरह की अवैध कमाई हो सकेगी. ख़ास तौर पर वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बड़े पैमाने पर होने वाली इस अवैध कमाई से सूदखोरी का काम नहीं कर पाएंगे. आज़ादी से लेकर अब तक वन विभाग ने महिलाओं एवं समुदाय विशेष का वनों से अलगाव पैदा करने के लिए कोई कोर कसर बाक़ी नहीं छोड़ी. इसलिए ऐसा कोई भी क़ानून, जो वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों पर महिलाओं और समुदाय विशेष के नियंत्रण की बात करता हो, उसे वन विभाग किसी भी क़ीमत पर लागू नहीं होने देना चाहता. मालूम हो कि वनाधिकार क़ानून वनों में रहने वाले आदिवासी समुदायों द्वारा पिछले 250 वर्ष से तिलका माझी, सिदहू कान्हू एवं बिरसा मुंडा आदि के नेतृत्व में लगातार किए जा रहे संघर्षों का ही नतीजा है. अंततः संसद को वनाश्रित समुदाय के लिए यह क़ानून पारित करना पड़ा. यह संघर्ष अब वन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की अगुवाई में और भी तीखा हो गया है. वनों के इतिहास में और आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाओं के व्यक्तिगत भूमि के अधिकार सहित सामुदायिक और प्रबंधन के अधिकार को भी मान्यता दी गई है. इस मुद्दे पर देश के कई महिला संगठनों ने इस संदर्भ में बनी संयुक्त संसदीय समिति को भी प्रस्ताव दिए थे. हालांकि पूरी तरह से अभी भी इन अधिकारों को महिलाओं को केंद्र में रखकर दर्ज नहीं किया गया है, जो नितांत ज़रूरी था. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में प्रकृति के कहीं ज़्यादा नज़दीक होती हैं और उनमें सामुदायिकता का भाव भी अधिक होता है. यही कारण है कि वनाधिकार क़ानून में महिलाओं के जिन अधिकारों को मान्यता दी गई है, उनका अपना एक महत्व है. अब वनों से संबंधित किसी भी मामले पर केवल पुरुषों का ही एकाधिकार नहीं होगा, बल्कि ये अधिकार किसी पुरुष को तभी मिलेंगे, जब उसके साथ परिवार की महिला का अधिकार भी दर्ज होगा. अगर कहीं पर एकल महिला है या परिवार की मुखिया महिला है तो भी यह अधिकार उसी के नाम से दर्ज होगा. खीरी (उत्तर प्रदेश) में पति के मना करने के बावजूद एक परिवार की महिला मुखिया ने दावा भरा, जिसे ग्राम वनाधिकार समिति ने स्वीकार किया. इसी तरह त्रिपुरा में भी कई परिवारों की महिला मुखिया को भूमि पर मालिकाना हक़ की पासबुक मिली है. लेकिन ऐसा तभी होगा, जब महिलाएं जागरूक होंगी. इससे पहले इस तरह का अधिकार आज तक हमारे देश की महिलाओं को वन भूमि पर कभी नहीं मिला और न जंगल पर. अधिकारों की बात तो दूर, महिलाओं द्वारा कृषि कार्यों में 90 प्रतिशत से अधिक योगदान करने के बावजूद आज तक उन्हें किसान होने की मान्यता तक नहीं दी गई. देश में आज तक जितने भी भूमि संबंधी क़ानून बने हैं, उनके अनुसार घर के पुरुष मुखिया का देहांत हो जाने पर बेटे अथवा परिवार के अन्य पुरुषों को वंशज होने के नाते संपत्ति का अधिकार मिल जाता है. वनाधिकार क़ानून से पहले बने अन्य भूमि संबंधी क़ानूनों के आधार पर महिलाएं भूमि पर बराबर और सीधा मालिकाना हक़ प्राप्त नहीं कर सकती थीं, इसलिए वनों से जुड़ी महिलाओं के लिए वनाधिकार क़ानून बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें भले ही अधिकार आंशिक रूप से मिले हों, लेकिन जितने भी हैं, उनके सहारे वे अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था और किसी हद तक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा भी हासिल कर सकती हैं.

वनाधिकार क़ानून के अध्याय 3 में 13 अधिकारों का उल्लेख है, जिनमें तीन अधिकार व्यक्तिगत हैं और शेष सामुदायिक मामलों से जुड़े हैं. इनमें एक महत्वपूर्ण अधिकार लघु वनोपज से संबंधित है, जो वनाश्रित समुदाय के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत है, लेकिन क़ानून पारित होने के चार वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक लघु वनोपज पर पात्रों को मालिकाना हक़ नहीं मिल सका है. यह लघु वनोपज अभी पूर्ण रूप से वन विभाग के नियंत्रण में है, जो इनसे सालाना करोड़ों रुपये की कमाई करता है. आंकड़े बताते हैं कि तेंदु पत्ता, लासा, बांस, शहद, मोम, महुआ एवं विभिन्न तरह की घासों-पत्तों से पैदा होने वाला धन वन विभाग द्वारा लूटा जा रहा है. अगर यहीं धन वनाश्रित समुदायों के पास उपलब्ध हो तो न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि वे लघु वनोपज की सुरक्षा करेंगे, इस तरह के पेड़ों को लगाएंगे और वनों की सुरक्षा भी करेंगे. यही एक ऐसी जगह है, जहां महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है. पर्यावरण मंत्रालय वन भूमि को अपने नियंत्रण में रखने के लिए वृक्षारोपण और उद्योगों के नाम पर विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनापति प्रमाणपत्र ज़ारी कर रहा है. वृक्षारोपण के तहत वन विभाग द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है. वनाधिकार क़ानून के तहत वनाधिकार समितियों का गठन करके समुदाय की सलाह के अनुसार वृक्षारोपण होना चाहिए, लेकिन संयुक्त प्रबंधन समितियों का गठन करके संसद द्वारा बनाए गए क़ानून को विफल करने की कोशिश की जा रही है. ये संयुक्त प्रबंधन समितियां दबंगों-सामंतों द्वारा बनाई जा रही हैं. इसी वजह से वनाश्रित समुदाय के साथ इनका टकराव बढ़ता जा रहा है और कई जगह हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं.

उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच ने आदिवासी एवं दलित महिलाओं की अगुवाई में व्यवसायिक वृक्षारोपण का बहिष्कार करके उन पेड़ों को लगाने की मुहिम शुरू की है, जो समाज के काम आते हैं. ये फलदार, चारा पत्ती एवं पर्यावरण को स्वच्छ करने वाले पेड़ हैं. झारखंड़ में तोड़न ट्रस्ट द्वारा लघु वनोपज को लेकर महिलाओं की सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं, ताकि उनके जीवकोपार्जन का जरिया तैयार हो और उनका बाज़ार के साथ सीधा जुड़ाव हो सके. यह तभी हो पाएगा, जब वनाधिकार क़ानून प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा. महिला वनाधिकार एक्शन कमेटी का भी गठन किया गया है, जो वन विभाग के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलकर वनों पर महिलाओं के अधिकार की आवाज बुलंद कर रही है. महिलाएं वन स्वशासन की मांग को लेकर आगामी 14-15 सितंबर को रांची में अपनी आवाज़ बुलंद करने वाली हैं. महिलाएं बिचौलियों को हटाने की मांग कर रही हैं, ताकि वे वनोपज का लाभ सीधे-सीधे उठा सकें. अगर वनाधिकार क़ानून की मंशा के अनुरूप महिलाएं अपना अधिकार पाने में सफल हो जाती हैं तो वनों में रहने वाली महिलाओं को उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य आसानी से हाथ पकड़ कर घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे. झारखंड महिला आयोग की सदस्य एवं पत्रकार वासवी कीरो द्वारा किए गए अध्ययन में यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि जहां-जहां घने वन हैं, वहां महिलाओं का अनुपात पुरुषों के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा है. यह अनुपात कई वन क्षेत्रों में 1000 पुरुषों के मुक़ाबले 1100 तक है. जबकि दिल्ली जैसे शहर में 1000 पुरुषों के मुकाबले केवल 733 महिलाएं हैं. मैदानी इलाक़ों में महिलाएं भरण-पोषण के लिए परिवार पर निर्भर रहती हैं और निजी संपत्ति के चलते गर्भवस्था में ही लड़कियों की हत्या कर दी जाती है. महिलाओं के भूमि एवं वन संबंधी अधिकारों को पहली बार स्वीकार करने वाले वनाधिकार क़ानून ने वनाश्रित समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के मद्देनजर उनके कई अधिकारों को मान्यता दी है. इन अधिकारों में महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है. महिलाओं को अपने हक़ के लिए जागरूक होना होगा, वनाधिकार क़ानून को समझना होगा और आम नागरिक समाज को भी उनके समर्थन में आगे आना होगा.

(लेखिका राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच एवं महिला वनाधिकार एक्शन कमेटी की सदस्य हैं)

feedback@chauthiduniya.com

शिक्षा के लिए एक नियम लागू किया गया है, शिक्षकों के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है.

कैबिनेट की बैठक में जब अन्ना हज़ारे के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाए, इस बारे में बात हो रही थी तो देश के गृहमंत्री ने कहा कि अन्ना के बुलाने पर ढाई हज़ार लोग भी नहीं आएंगे.

कर्म, अकर्म और दुष्कर्म

महावीर प्रसाद आर मोरारका

धनिक या समृद्ध व्यक्ति क्या निठल्ला रहता है या आलस्य में कुछ काम करता ही नहीं? अगर वह मेहनत करता है, काम करता है तो फिर धनिक या समृद्ध होने से आप उसे बुरा क्यों कहते हैं? काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बुरा कहने का अधिकार किसी को नहीं है, बशर्ते कि वह काम करता हो देश के लिए, समाज के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ भी उपार्जन करने वाले कामों को ही हम काम कहेंगे. ज़्यादा खाने से बदहजमी हो गई, उसको दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर ने रोजाना 4 मील घूमना बतलाया. अब सुबह-शाम 4 मील घूम रहे हैं, बड़ा परिश्रम हो रहा है, टेनिस खेलने गए, घुड़दौड़ देखने गए, सिनेमा, नाटक देखने गए. कहां तक गिनाएं, इन धनिकों को दिन-रात 24 घंटों में अवकाश का तो एक क्षण भी नहीं मिलता. दिन-रात परिश्रम करते रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, ज़रा भी तो फुर्सत नहीं. पर तो भी, चूंकि वे कुछ उपार्जन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह सब काम नहीं कहा जाएगा.

कर्म की व्याख्या का भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अच्छी तरह प्रतिपादन किया है. जिस कर्म के करने से किसी को कुछ फल प्राप्त न हो या जो कुछ भी अर्जन या हासिल न कर सके, उसको अकर्म कहते हैं. कर्म के बाद दुष्कर्म भी कुछ मायने में ग्रहण किया जाता है. दुष्कर्म से किन्हीं थोड़े आदमियों को लाभ पहुंचता है, ज़्यादा व्यक्तियों को नुक़सान पहुंचता है. पर अकर्म तो निष्क्रियवाद का ही प्रतीक है. धनिकों या श्रेष्ठि के ये काम करने के हौसले, जिनको करके वे स्वयं अपनी शारीरिक स्थिति को कुछ न करने के लिए फिट रखने में इस्तेमाल करते हैं, अजीब है. यह दोष धनिकों या समृद्धों को ही क्यों दिया जाए, क्या दूसरे आम आदमी इस तरह आलस्य में दिन नहीं बिताते? बिताते हैं. कभी-कभी तो मध्यम वर्ग या ग़रीब वर्ग के व्यक्ति इतने आलसी हो जाते हैं कि उनसे दिन-रात सोने या खाने के सिवाय कुछ करते नहीं बन पड़ता. पर यह दोष उसी व्यवस्था का है. समान वित्त वितरण के साथ समान श्रम वितरण भी तो बंधा हुआ है.

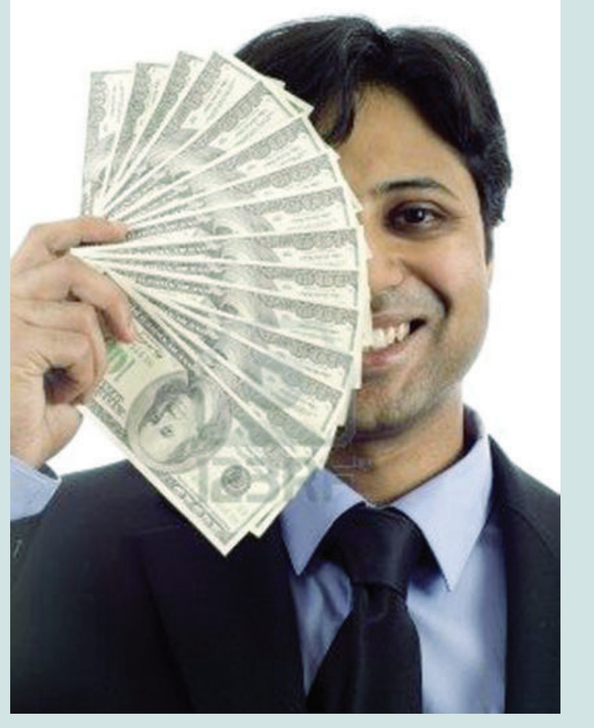

अनाचार और अविद्या का ज़हर

स्कूलों को लीजिए, शिक्षा के लिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं. जो शिक्षा उन्हें वहां प्राप्त होती है, क्या वह ठीक है? क्या आपने कभी विचार किया कि जिन अध्यापकों के मस्तिष्क में भूख की वजह से, दरिद्रता की वजह से ज्ञान राशियां पनपने नहीं पाई हैं, वे कैसे बालकों को उचित कर्तव्य की शिक्षा दे पाएंगे? स्कूल अधिकतर या तो नगरपालिका द्वारा संचालित हैं या सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जाती हैं. बहुत से स्कूल धनिकों द्वारा किए गए चंदे से बनाए हुए हैं या उन्हीं द्वारा संचालित हैं. उन स्कूलों के अध्यापक बच्चों को समान अधिकार या समान वित्त वितरण की शिक्षा का पाठ पढ़ाना तो दूर रहा, उसका जिक्र भी नहीं कर सकते. बहुधा वे धनी या समृद्ध पुरुष उपास्य बन जाते हैं और भारत के आदर्श महानुभावों के रूप में बतलाए जाते हैं. अध्यापकों को मुश्किल से अपना गुजारा चलाने जितना वेतन मिलता है. हर वक़्त उन्हें भय रहता है कि कहीं नौकरी न छूट जाए. उनकी योग्यता का मापदंड परीक्षाफलों से माना जाता है. इसलिए अध्यापक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग दोनों की तमन्ना एकमात्र यही रहती है कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पास हो जाएं.

परीक्षा के जो कुछ भी स्तर हैं, उनको जाने दीजिए, जो भी हैं. उन्हें भी सही-सही तरीक़ों से प्राप्त करने में बालक सफल नहीं होते. अत: प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह परीक्षा के परचे बनाने वाले अध्यापकों का पता लगाकर उनसे पहले ही परचे प्राप्त कर लें या जब परीक्षण के लिए उनके पास कापियां गई होती हैं तो किसी तरह पता लगाकर उन पर प्रभाव डालकर ज़्यादा नंबर ले लें, जिससे पास हो जाएं. जहां परीक्षाफल निकला, अध्यापक समझ लेते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया. विद्यार्थी समझते हैं कि वे अब शिक्षित नागरिक बन गए. शिक्षा के रूप में अनाचार का, अविद्या का या गुलामी का मीठा ज़हर जो अपने बच्चों को पीना पड़ रहा है, उसका फल क्या होगा? इसका निर्णय आप स्वयं कर लें.

आज भी इतिहास के पृष्ठों से भूतकाल में किए गए त्याग का गौरव गाया जाता है. सेवक स्वामी का इस हद तक नमक हलाल होता था कि अपना सर्वस्व देकर या खोकर भी स्वामी के पसीने की जगह अपना ख़ून बहाने को तैयार रहता था. उनकी गौरव गाथा बड़े प्रेम और उत्साह से पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, मनन की जाती है. आज भी स्कूलों में हमें यही बताया जाता है कि धनिक होना या निर्धन होना भगवान की मर्जी की बात है, आदमी का चारा ही क्या है? 400 वर्ष पहले उस समय में प्रचलित किंवदंतियों के आधार पर बनी कहावतों को वेद वाक्य या ईश वाक्य मान लिया जाता है. जब धनिकों या समृद्धों की श्रेष्ठता इस तरह बचपन से ही सिखाई जाती है तो आगे चलकर यही बच्चे हीनभावना अनुभव करने लगते हैं और निर्विवाद मान लेते हैं कि धनिक वर्ग उनसे श्रेष्ठ है.

स्कूलों में आज अब यह शिक्षा भी दी जाने लगी है कि भारत का हर बच्चा समान अधिकार रखता है और ये आर्थिक व्यवस्थाएं भगवान की बनाई हुई नहीं हैं, अपनी निज की ही बनाई हुई हैं. इस व्यवस्था को चाहे जब बदला जा सकता है. ऐसा कहने वाले अध्यापक को वह प्रभावशाली धनिक वर्ग यथाशीघ्र स्कूल से अलग कर देगा. निश्चय ही आपने देखा होगा कि स्कूलों में बहुधा धनिकों के बालकों के प्रति पक्षपात होता है. कुछ पाठशालाओं को छोड़ दीजिए, पर बहुसंख्यक पाठशालाएं आज भी किसी धनिक बालक पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सकतीं, जबकि उसी अपराध पर साधारण आदमी का बालक स्कूल से निकाल दिया जाता है या अन्य रूप से दंडित होता है. परीक्षा के परचे बनाने वाले अध्यापक भी बहुधा प्रलोभन से ही परचे पहले दे देते हैं और अधिकतर ये प्रलोभन देने वाले या दे सकने वाले बालक उन धनिकों के ही होते हैं. इसी तरह से पास होने के लिए नंबर बढ़ा लेने का प्रयत्न करने में भी ज़्यादातर उसी वर्ग के बालक देखे जाते हैं. जहां मैं धनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहां उसी सिलसिले में आपको खाता-पीता समृद्ध आदमी समझ लेना चाहिए.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

सुलगता लंदन और पुलिस की भूमिका

मेघनाद देसाई

ब्रिटेन की राजधानी लंदन के कई शहरों में पिछले दिनों हुए दंगे बेहद दुखद नज़ारे बयां कर रहे थे. आश्चर्य की बात यह है कि मैंने दो हफ्ते पहले ही लंदन छोड़ दिया था. भीषण गर्मी से बचने के लिए हम सभी लंदन में शानदार मौसम का लुत्फ़ ले रहे थे. लंदन में हिंसा उस समय भड़की है, जब वहां ओलंपिक शुरू होने में महज एक साल का वक्त रह गया है. हालांकि लंदन पुलिस पर आरोप है कि उसकी गोलीबारी में मार्क दुग्गन नामक एक ब्रिटिश युवक की मौत हो गई. इस घटना के बाद टोटेनहैम में भड़की हिंसा देखते ही देखते ब्रिटेन के कई शहरों में फैल गई. लंदन के कई हिस्सों से आगजनी के बाद धुएं का गुबार उठता देख शांति प्रिय लोगों के मन में ख़ौफ़ पैदा हो गया. नकाबपोश दंगाइयों ने सड़कों पर जिस तरह तोड़फोड़ की और गाड़ियों एवं घरों में आग लगा दी, उसे देखकर ऐसा लगा कि इंसान को शैतान बनते ज़्यादा देर नहीं लगती. वैसे लंदन की इस हिंसा के लिए वहां की पुलिस को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है. इस घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग भी बनाया गया है, ताकि ब्रिटिश युवक मार्क दुग्गन की मौत और उसमें लंदन पुलिस की भूमिका पर निष्पक्ष पड़ताल हो सके.

कैसा अजीब मंजर था कि लंदन में गर्मी की छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद थे. वहां पढ़ने वाले किशोर युवा जो अब तक मस्ती में डूबे थे, वे सभी लोग देखते ही देखते उस अराजनैतिक गिरोह का हिस्सा बन गए, जिसने लंदन के कई शहरों में न सिर्फ़ हिंसात्मक आचरण का परिचय दिया, बल्कि वहां जमकर लूटपाट की. हैरत की बात यह रही कि ये सभी युवा अत्याधुनिक 3-जी मोबाइल फोन से लैस थे. इतना ही नहीं, फेसबुक और यू-ट्यूब के जरिए भी वे अपनी बातों का आदान-प्रदान कर रहे हैं. ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल वे अपने साथियों की मदद और पुलिस को चकमा देने में कर रहे हैं. वहां की पुलिस यह महसूस करती है कि उसने डेस्क पर बहुत ज़्यादा काम किया है. पिछले कुछ वर्षों में ऐसे गिरोह पुनर्गठित होकर सड़कों पर उतर रहे हैं. अब तक उसका ध्यान काउंटर आतंकवाद पर रहा. उसने इस्लामिक आतंकवाद और साइबर आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अपने देश में अपने लोगों से निपटने में उसने अपनी पुरानी कार्यशैली का परिचय दिया.

एक शहर में दंगे की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते अन्य शहरों में फैल गया. ये वे शहर हैं, जहां अश्वेत ग़रीब और गोरे लोगों की आबादी में एक उच्च अनुपात है. यहां अमूमन पारिवारिक संरचनाओं और उनकी स्थिरता में कमी देखी जाती है. दरअसल ब्रिटिश राज्य कल्याण के नियमों में भी काफी विसंगतियां मौजूद हैं. यहां न तो शादी और न मज़बूत घरों पर जोर दिया जाता है. बेहतर जन सुविधाओं एवं समाज में उचित भागीदारी की कमी और अन्य राज्यजनित सुविधाओं से वंचित होना ब्रिटेन के उस तबके के अंदर आक्रोश पैदा करता है, क्योंकि अन्य वर्गों के मुक़ाबले अश्वेत बेरोज़गारी का सर्वाधिक सामना कर रहे हैं.

अश्वेत समुदाय के युवा जो इस हिंसक भीड़ का हिस्सा हैं, उनके माता-पिता का कहना है कि शिक्षा और अवसरों की कमी ने उनके अंदर एक असंतोष को जन्म दिया है. वे मानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में वहां की प्रगतिशील सरकारें, खासकर लेबर पार्टी ने पात्रता के नियमों को और अधिक उदार बना दिया है. लिहाजा हम लोगों को अपनी बातें रखने की बड़ी स्वतंत्रता मिली है. हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार कल्याणकारी राज्य में और अधिक सुधार की ज़रूरत स्वीकार करती है. मौजूदा सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अब तक प्रोत्साहन के नाम पर कुछ खास नहीं किया गया. नौकरी देना और उनकी हिफाजत करना एक बड़ी बात है.

शिक्षा के लिए एक नियम लागू किया गया है, शिक्षकों के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है. उदार नियमों की आड़ में शिक्षकों को धिक्कारना, छात्रों के साथ बुरा बर्ताव पूरी तरह मानवाधिकारों के विपरीत है. दंगा प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल और पब्लिक स्कूल बंद रहे. जब उन स्कूलों का दौरा किया गया तो अभिभावक अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए तैयार नहीं हुए. इन सबके बावजूद आज देश में व्याप्त गहरी समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत सही नहीं है. ब्रिटिश संसद में बजट घाटे के मसले पर चर्चा हुई, एक अमेरिकी शैली डाउनग्रेड की तर्ज पर. लेकिन एक लोक कल्याणकारी सरकार को आम आदमी की समस्याओं के समाधान पर भी जोर देना चाहिए. सबसे पहले लंदन की प्रतिष्ठा की बहाली पर प्राथमिकता तय हो, क्योंकि सभी को पता है कि लंदन में ओलंपिक शुरू होने में महज कुछ ही महीने शेष रह गए हैं.

feedback@chauthiduniya.com

नक़ाबपोश दंगाइयों ने सड़कों पर जिस तरह तोड़फोड़ की और गाड़ियों एवं घरों में आग लगा दी, उसे देखकर ऐसा लगा कि इंसान को शैतान बनते ज़्यादा देर नहीं लगती. वैसे लंदन की इस हिंसा के लिए वहां की पुलिस को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है. इस घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग भी बनाया गया है, ताकि ब्रिटिश युवक मार्क दुग्गन की मौत और उसमें लंदन पुलिस की भूमिका पर निष्पक्ष पड़ताल हो सके.

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

ग़रीबों की ज़ुबान चौथी दुनिया

अर्से बाद पूना में चौथी दुनिया देखा. ऐसा लगा कि जैसे कोई बिछड़ा साथी मिला हो. अभी भी चौथी दुनिया में वही ताज़गी, तेवर और कलेवर है. आय का समान वितरण है समाजवाद, आलेख आंखें खोल देने वाला है. आज होटल में 70 रुपये की थाली आ रही है. साधारण आय वाला व्यक्ति तो एक समय खाना भी नहीं खा सकता. देश के दस लोगों के नाम विश्व के धनी लोगों की सूची में आ जाना संपूर्ण भारत के विकास का मापदंड नहीं हो सकता. ऐसा विकास जो लोगों को दो निवाले न दे सके, उससे क्या फ़ायदा? आय के असमान वितरण के कारण देश में मारधाड़, लूटखसोट और नक्सलवाद पनप रहा है. दूसरों की रोटी का बुनियादी हक़ भी हम छीन लेंगे तो वे ग़लत काम की ओर ही उन्मुख होंगे. ऐसी सामग्री, जो चिंतन के लिए बाध्य करे, उसे प्राथमिकता दें. अच्छा है, आप ग़रीबों की ज़ुबान बन रहे हैं, इस आवाज को और भी बुलंद करना है.

- अनुपमा गुजराती, मुंबई, महाराष्ट्र.

कन्या भ्रूण हत्या शर्मनाक

यह चिंता का विषय है कि आधी आबादी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार मां की कोख से ही शुरू हो जाता है. कमोबेश उसे जीवन भर भेदभाव से गुज़रना पड़ता है. आश्चर्यजनक है कि धार्मिक कहलाने और चींटी की भी हत्या से कांपने वाला समाज आंख मूंदकर भ्रूण हत्या कैसे करता है? देवी स्वरूप और सभी सुख-सुविधाओं का बलिदान करने वाली मां अपनी कोख में पलती बच्ची के जीने का नैसर्गिक अधिकार कैसे छीन लेती है? वह क्यों नहीं सोचती कि उसे भी कभी किसी मां ने ही समाज से लड़कर जन्मा. विडंबना देखिए कि देश के 640 ज़िलों में से सिर्फ़ 102 ज़िलों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है. क्या भ्रष्टाचार और लोकपाल बिल का मुद्दा वास्तव में महिला भ्रूण हत्या से ज़्यादा ग्लैमरस है कि इसे लेकर कोई अनशन नहीं करता? लड़कियों के प्रति ऐसा व्यवहार शर्मनाक और चिंतनीय है.

-डॉ. नीता सिन्हा, पटना, बिहार.

ढाक के तीन पात

भुखमरी, ग़रीबी, बीमारी, बेकारी और अशिक्षा देश की मुख्य समस्याएं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, नशा, आतंकवाद और बढ़ती जनसंख्या जैसे अवरोधों के विद्यमान रहते इनसे छुटकारा पाना कैसे संभव होगा? देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबकी स्थिति एक जैसी है. नेता अपनी भावी सात पीढ़ियों की व्यवस्था करने में जुटे हैं. जनता सत्ता परिवर्तन करती है तो भी उसका प्रयास ढाक के तीन पात ही साबित होता है. जब तक सत्ता की बागडोर ईमानदार लोगों के हाथ में नहीं आ जाती, तब तक देश की स्थिति सुधरने वाली नहीं है.

-रामावतार, रायपुर, छत्तीसगढ़.

चौथी दुनिया

चौथी दुनिया सात दिन में
एक बार ही आता है,
बड़े, बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान
सभी के मन को भाता है,
सच्चाई और निष्पक्षता
हर पाठक इसमें पाता है,
किसी एक प्रांत में नहीं
सारे भारत में पढ़ा जाता है,
ज्ञान-विज्ञान, फिल्मी, क़ानूनी
सारी ख़बर यह लाता है,
कहें अक्षर कविराय
अब तो अपना भी जुड़ा नाता है.

-केसर सिंह गोहिल, राजस्थान.

भ्रष्टाचार और हम

देश में भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन चल रहा है. हर कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लंबी-लंबी बातें कर रहा है. अगर ईमानदारी से देखा जाए तो भ्रष्टाचार हमारी घुट्टी में ही मिल चुका है. बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने से लेकर नौकरी दिलाने तक हर जगह भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है. ग़रीब आदमी क्या करे, अगर वह रिश्वत न दे तो उसका कोई काम ही न हो. ऐसी हालत में रिश्वत देना उसकी मजबूरी बन जाती है. हम किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? उस भ्रष्टाचार की, जो बड़े-बड़े घोटाले कराता है या उस भ्रष्टाचार की, जो लगता तो छोटा है, लेकिन बड़े-बड़े घोटालों से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है.

-असलम ख़ान, दिल्ली.

लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-लोकपाल बिल जनता के साथ धोखा है, पढ़ा. लोकपाल बिल कितना सच है और कितना झूठ, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा. देश की जनता आज़ादी के बाद से लगातार धोखा ही खा रही है. इसलिए एक बार फिर आज़ादी के आंदोलन की ज़रूरत से इंकार नहीं किया जा सकता. पुलिस दमन करेगी उसे सहना होगा, क्योंकि यह पुलिस हमारी नहीं, अंग्रेजों की कोख से उपजी है. देखते हैं कि लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार कम होता है या नहीं?

-गिरीश पंकज, ई-मेल से.

प्रधानमंत्री जवाब दें

मुख्य आलेख-षड्यंत्र के साए में इंडियन आर्मी: प्रधानमंत्री ख़ामोश क्यों हैं, पढ़ा. यहां पर समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं है. हर कोई भ्रष्टाचार का हिस्सा बन चुका है, चाहे वह नेता हो, मीडिया हो, मंत्री हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, बस उसे मौक़ा मिल भर जाए. प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए भी ख़ामोश रहते हैं. इस ख़ामोशी का जवाब वह ख़ुद दे सकते हैं. यह एक गंभीर समस्या है, जिस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था. चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी.

-नेम सिंह, ई-मेल से.

पेड न्यूज और मीडिया

बाबा रामदेव के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए हथकंडे को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं. जिस निर्लज्जता से देश के बेईमान और भ्रष्ट मीडिया ने झूठ का सहारा लेकर इस आंदोलन को असफल करने की कोशिश की, वह निश्चय ही निंदनीय है. पैसा बनाने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. एक नया कॉन्सेप्ट रचा गया है पैसा बनाने का और वह है पेड न्यूज़, पेड ब्लॉग्स, पेड कॉलम, पेड कमेंट्स, पेड आर्टिकल्स, पेड एडिटोरियल आदि. देश और देशवासियों से द्रोह करके मीडिया चांदी कूट रहा है.

-कुलदीप सचदेव, ई-मेल से.

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह पूरे देश का आंदोलन है

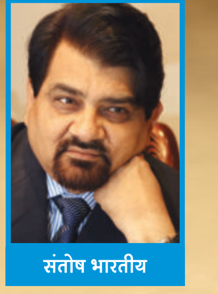

संतोष भारतीय

अन्ना हज़ारे इतिहास में सुनहरा पन्ना बनकर जुड़ गए हैं. आज़ादी के बाद कई नेताओं ने आंदोलन किए, लोग उनके साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बातें भी मनवाईं. अनशन हुए, आमरण अनशन हुए, उनमें लोग शहीद भी हुए, लेकिन अन्ना का क़िस्सा इन सबसे अलग है. एक ऐसा आदमी, जो देश में कहीं घूमा नहीं, जिसने राज्यों में सभाएं नहीं कीं, लोगों को तैयार नहीं किया, उनके पास अपना मुद्दा नहीं पहुंचाया, कोई संगठन नहीं बनाया, उसके साथ आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जनसैलाब खड़ा है. कल क्या होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन आज सारा हिंदुस्तान अन्ना हजारे के साथ खड़ा है. पिछले 15 सालों में हिंदुस्तान में जनता की नब्ज़ पहचानने वाले लोग बिछुड़ गए, प्रकृति ने उन्हें हमसे छीन लिया, लेकिन इन 15 वर्षों में हिंदुस्तान की समस्याएं भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ीं. नई आर्थिक नीतियां लागू हुईं, साल भर के भीतर ही उनका परिणाम आना शुरू हुआ. पहला घोटाला पांच हजार करोड़ रुपये का हुआ, जिसमें विदेशी बैंक शामिल थे. उन्होंने हिंदुस्तान का पैसा, रिजर्व बैंक के आकलन के हिसाब से पांच हज़ार करोड़ रुपया देश के बाहर भेज दिया. उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसका परिणाम यह निकला कि 2005 से 2011 के बीच देश में घोटालों की बाढ़ आ गई.

इन आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप एक तरफ़ जहां भ्रष्टाचार गांव-गांव पहुंच गया, पंचायतें भी उसमें शामिल हो गईं, वहीं दूसरी तरफ़ एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया, जिसे भारत के महालेखा नियंत्रक ने पकड़ा 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में. इसके बाद इससे बड़ा कोयला घोटाला हुआ और उससे भी बड़ा घोटाला हुआ जिसकी कोई राशि सीएजी की समझ में ही नहीं आई, केजी बेसिन घोटाला. इन सारी स्थितियों ने संकेत दिए कि देश पूरे तौर पर भ्रष्टाचार के ऐसे शिकंजे में फंस गया है, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है. दूसरी तरफ़ देश का आम आदमी, जिसमें 60 प्रतिशत लोग सीधे-सीधे आते हैं, लेकिन हम 70 या 75 प्रतिशत मान लें, ये सारे लोग भ्रष्टाचार से पूरी तरह पीड़ित थे. भ्रष्टाचार के साथ की बीमारी जिसका नाम महंगाई है, जिसका नाम बेकारी है, जिनके परिणास्वरूप भूख से मौतें होती हैं, देश में विकास नहीं होता और पैसा नीचे तक नहीं पहुंचता, ये सारी चीजें 2011 तक लोगों की ज़िंदगी में घुस गईं. लोग मन ही मन तड़प रहे थे, मन मसोस रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि पूरा राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है, जिसमें किसी दल के पास जाना अंधे के आगे रोने जैसा है, क्योंकि जनता को सारे राजनीतिक दल एक ही चरित्र के दिखाई देने लगे. ऐसा कोई भी नेता उन्हें नहीं दिखाई दिया, जो अलग हो. हर किसी के साथ कोई न कोई स्कैंडल, किसी न किसी पूंजीपति का चेहरा, कोई न कोई विदेशी ताकत. लोगों को लगा कि सारा राजनीतिक तंत्र भ्रष्ट हो चुका है.

भारत की लोकसभा लोकतंत्र का चेहरा है, लेकिन लोकतंत्र का यह चेहरा भी लोगों को डराने लगा. उन्हें लगने लगा कि उनकी किसी भी समस्या का समाधान लोकसभा नहीं दे पाएगी और इसलिए अब उन्होंने अपनी समस्याओं के लिए लोकसभा के दरवाज़े पर आकर उसे खटखटाना बंद कर दिया है. लोग आते थे, यह सौ करोड़ से ज़्यादा लोगों का मुल्क है. संगठन लोगों को लेकर आते थे, वे रस्मी विरोध जंतर-मंतर पर दर्ज करके चले जाते थे. जनता नहीं आती थी, वह किसी राजनीतिक दल के पास नहीं जाती थी, पर उसके अंदर पनप रही घोर निराशा ने गुस्से का स्वरूप लेना शुरू किया. अन्ना जब दिल्ली आए और उन्होंने उपवास किया तो लोगों को लगा कि हां, एक शख्स है, जिसका कोई स्वार्थ इस अनशन में नहीं है, वह हिंदुस्तान में व्याप्त चारों-पांचों महामारियों के ख़िलाफ़ संघर्ष करना चाहता है और अगर संघर्ष न कर पाया तो अपनी जान दे देना चाहता है. उसके साथ लोगों का मन मिल गया, लोग जुड़ने लगे. एक तरफ़ लोग उनसे जुड़ रहे थे और दूसरी तरफ़ राजनीतिक पार्टियां और सत्तापक्ष यानी कांग्रेस पार्टी इस आदमी के प्रति लोगों में भ्रम फैलाने में अपनी ताकत लगाने लगीं. जब राजनीतिक पार्टियों ने, जिनमें सत्ता पक्ष सबसे आगे था, अपनी सारी ताकत लगा ली और देखा कि कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो उन्होंने मीडिया का सहारा लिया. मीडिया ने भी अन्ना के ख़िलाफ़ कई तरह के भ्रम फैलाए, पर लोगों को लगा कि यह सब निहित स्वार्थवश और अन्ना के ख़िलाफ़ एक सोची-समझी साज़िश है. इसलिए जब अन्ना ने जन लोकपाल की बात की और कहा कि इससे भ्रष्टाचार मिटेगा तो देश की भोली-भाली जनता ने सोचा कि ऐसा हो सकता है और एक नि:स्वार्थ व्यक्ति यह बात कह रहा है, इसलिए उसका साथ देना चाहिए. नतीजे के तौर पर सारा देश अन्ना के साथ खड़ा हो गया.

यह बहस का विषय है कि जन लोकपाल भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगाएगा, लेकिन यह भ्रष्टाचार से लड़ने की दिशा में एक क़दम साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं. जनता ने भी यही सोचकर अन्ना का साथ दिया. लेकिन सरकार, जिसके पास इतनी बड़ी मशीनरी है, कर्मचारी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, हर विभाग की अपनी ख़ुफ़िया इकाई है, किसी ने यह ख़बर सरकार को नहीं दी कि अन्ना के पक्ष में देश का मानस कितना तैयार हो रहा है. परिणाम जो निकलना था, वही निकला. सरकार मुग़ालते में रही और लोग अन्ना के साथ खड़े हो गए. इस सरकार की महान बुद्धिमानी, जिसे दूसरे शब्दों में महान मूर्खता कह सकते हैं, का उदाहरण अगर लेना हो तो 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का समय सबसे उपयुक्त है. 12,13,14 और 15 अगस्त को सरकार के जो तेवर थे, मंत्रियों के जो तेवर थे, सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस और एमसीडी के जो तेवर थे, वे ऐसे थे, जैसे तानाशाह के तेवर हों. कोई भी मंत्री लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसलिए 17 अगस्त की सुबह तक सरकार को लगा कि अगर उसने तत्काल अपना फैसला नहीं बदला तो हो सकता है कि देश में ऐसे हालात हो जाएं, जो उसके क़ाबू में न रहें और सरकार ने यू-टर्न ले लिया.

कैबिनेट की बैठक में जब अन्ना हज़ारे के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इस बारे में बात हो रही थी तो देश के गृहमंत्री ने कहा कि अन्ना के बुलाने पर ढाई हज़ार लोग भी नहीं आएंगे. आप यह कैसे कह सकते हैं, कैबिनेट के एक मंत्री ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इंटेलिजेंस है, मुझे पता है. तब दूसरे मंत्री ने कहा कि आपने यही बात बाबा रामदेव के अनशन के समय कही थी कि उनके यहां 500 से 1000 लोग आएंगे, लेकिन आ गए 25,000 लोग. दरअसल दो वकीलों ने इस सरकार को डुबोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. इनके दफ्तर अभी भी काम करते हैं, इनके परिवार के लोग अभी भी वकालत में हैं. ये ऐसे वकील थे, जो सरकार बनने से पहले जब अदालत में जाते थे तो एक पेशी के पांच लाख रुपये लेते थे अपने क्लाइंट से. अदालत भले ही तारीख़ दे दे, लेकिन इन्हें पांच लाख रुपये चाहिए, वरना ये हिलकर सुप्रीम कोर्ट में जज के चेंबर की तरफ़ जाते भी नहीं थे. इनका रिश्ता हिंदुस्तान के आम आदमी से कभी रहा ही नहीं. इनका रिश्ता उन लोगों से रहा, जो एक घंटे की सुनवाई के लिए 5 लाख रुपये दे सकते हैं. वे कौन लोग हैं? वे देश के 50 बड़े घराने हैं, जिनके मुक़दमे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं. 50 बड़े अपराधी हैं, जिनके मुक़दमे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वही 5 लाख रुपये एक पेशी का दे सकते हैं. इन मंत्रियों के पास कार्यकर्ताओं से मिलने का वक़्त नहीं है. कार्यकर्ताओं की बिसात क्या, इनके पास सांसदों से मिलने का वक़्त नहीं है. मैं गवाह हूं, संसद के सेंट्रल हॉल में मुझसे कांग्रेस के बीसियों सांसदों ने कहा कि ये दोनों मिलकर पार्टी को डुबो देंगे. मनमोहन सिंह को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. जब कांग्रेस के सांसद ऐसी बात कहें तो मान लेना चाहिए कि यह सरकार कैसी चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह सरकार कुछ न कुछ कमाल अभी और करेगी, जिससे देश के लोगों को लगेगा कि यह किसी भी तरह से उनकी सरकार नहीं है और विपक्षी दल कुछ न कुछ ऐसा नाटक ज़रूर करेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये जितने लोग राजनीति में नेता बनने का दावा करते हैं, उस दावे के लायक़ हैं नहीं, क्योंकि जनता की आकांक्षा कुछ है और ये कुछ और करना चाहते हैं.

हो सकता है, देश के सारे लोग अन्ना हजारे के समर्थन में दिल्ली की तरफ कूच कर दें. कितना रोकेंगी राज्य सरकारें, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया है कि जो जन उभार दिल्ली में दिखाई दिया, वही उनकी राजधानी में भी दिखाई दे सकता है. इसलिए कोई भी हाथ सेंकते हुए अपने हाथ जलाना नहीं चाहेगा. अगर सारे देश के लोग दिल्ली की तरफ़ कूच कर जाएं, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अन्ना की मुहिम में साथ देने की शपथ खाने लगें तो क्या स्थिति होगी? अगर यही बात देश के क़स्बों-गांवों तक पहुंच जाए. बहुत सारे क़स्बों और गांवों में अन्ना को लेकर ख़ासी उत्सुकता है. शायद वहां भी यह मुद्दा पहुंच चुका है. लेकिन अभी भी वे लोग, जो जनता के उभार के ख़िलाफ़ हैं और वे टेलीविज़न चैनल, जो जनता की आकांक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं, एक नई बहस शुरू करना चाहते हैं. उनके अनुसार, इस आंदोलन में दलित नहीं हैं, अल्पसंख्यक नहीं हैं. यहां सवाल यह है कि उन्हें कैसे पता चला कि इसमें दलित नहीं हैं, अल्पसंख्यक नहीं हैं. क्या वे यह चाहते हैं कि दलित उसी रूप में सामने आएं, फटे कपड़े-फटे जूते पहन कर और भूखा पेट लेकर, तभी वे मानेंगे कि आंदोलन में दलित शामिल हुआ. या फिर अल्पसंख्यक, जिनमें मुसलमान सबसे प्रमुख है, वह इस रूप में सामने आए कि लंबी दाढ़ी, ऊंचा पायजामा, लंबा कुर्ता, तभी वे मानेंगे कि मुसलमान इसमें शामिल है. यह देश को भटकाने की उनकी साजिश का एक हिस्सा है. इस आंदोलन में नौजवान शामिल है. नौजवान ने पहली बार देश में खड़े होकर यह बताया कि वह क्या चाहता है. वह भ्रष्टाचार से मुक्ति और नया हिंदुस्तान चाहता है. इन नौजवानों में दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े भी हैं और अगड़े भी हैं यानी कुल मिलाकर पूरा देश शामिल है.

यह मध्य वर्ग का आंदोलन नहीं है. हम अपने साथियों को चुनौती देते हैं कि वे हमें सबूत दें कि यह मध्य वर्ग का आंदोलन है. हम उन्हें सबूत देते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ सबूत देते हैं कि यह मध्य वर्ग का आंदोलन नहीं है, देश का आंदोलन है. सेना जब लड़ाई लड़ती है तो कुछ टुकड़ियां आगे होती हैं और कुछ पीछे. महान बुद्धिमानों को, जो इतिहास में नकटे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, उनसे हम यह कहना चाहेंगे कि लड़ाई में हरेक का रोल होता है. सीमा पर जो बंदूक़ चलाता है, वह बंदूक़ नहीं चला सकता, अगर उसे गोलियों की सप्लाई न हो. गोलियों की सप्लाई करने वाली अलग यूनिट होती है. वह गोली नहीं चला सकता, अगर उसके पास खाना बनकर न आए और उसके पेट में खाना न जाए. वह गोली नहीं चला सकता, अगर उसके कपड़े साफ न हों, क्योंकि एक तरफ़ वह निशाना लगाता है दुश्मनों पर, अगर उसके कपड़े गंदे हों, उनमें कीड़े हो गए हों तो उसका निशाना चूक सकता है. हरेक का रोल है. धोबी, मोची, डाकिया जो संदेश लाता है ले जाता है और वायरलेस ऑपरेटर, इन सबका लड़ाई में रोल होता है. उसी तरीके से इस नई लड़ाई में, जिसे अन्ना आज़ादी की दूसरी लड़ाई कहते हैं, सबका रोल है और सब अपना-अपना रोल निभा रहे हैं. इस जन उभार को समझना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए और देश बदलने की आशा लिए लोगों द्वारा देखे जाने वाले सपने को हम सबको सलाम करना चाहिए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

अन्ना जब दिल्ली आए और उन्होंने उपवास किया तो लोगों को लगा कि हां, एक शख्स है, जिसका कोई स्वार्थ इस अनशन में नहीं है, वह हिंदुस्तान में व्याप्त चारों-पांचों महामारियों के ख़िलाफ़ संघर्ष करना चाहता है और अगर संघर्ष न कर पाया तो अपनी जान दे देना चाहता है. उसके साथ लोगों का मन मिल गया, लोग जुड़ने लगे. एक तरफ़ लोग उनसे जुड़ रहे थे और दूसरी तरफ़ राजनीतिक पार्टियां और सत्तापक्ष यानी कांग्रेस पार्टी इस आदमी के प्रति लोगों में भ्रम फैलाने में अपनी ताक़त लगाने लगीं. जब राजनीतिक पार्टियों ने, जिनमें सत्ता पक्ष सबसे आगे था, अपनी सारी ताक़त लगा ली और देखा कि कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो उन्होंने मीडिया का सहारा लिया. मीडिया ने भी अन्ना के ख़िलाफ़ कई तरह के भ्रम फैलाए, पर लोगों को लगा कि यह सब निहित स्वार्थवश और अन्ना के ख़िलाफ़ एक सोची-समझी साज़िश है. इसलिए जब अन्ना ने जन लोकपाल की बात की और कहा कि इससे भ्रष्टाचार मिटेगा तो देश की भोली-भाली जनता ने सोचा कि ऐसा हो सकता है और एक नि:स्वार्थ व्यक्ति यह बात कह रहा है, इसलिए उसका साथ देना चाहिए.

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

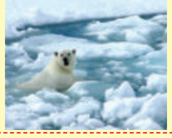
मूंगा दुनिया भर में क़रीब पांच सौ करोड़ लोगों के भोजन और आय का प्रमुख स्रोत होने के साथ-साथ समुद्र तट की सुरक्षा का भी प्रमुख साधन है.

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

सूचना क़ानून और शुल्क

पिछले कुछ अंकों में हमने आपको सूचना शुल्क के बारे में बताया था. इस अंक में हम आपको ऐसे ही कुछ उदाहरणों के बारे में बता रहे हैं. साथ ही यह भी कि सूचना शुल्क के बारे में सूचना अधिकार क़ानून क्या कहता है. कई बार सूचना उपलब्ध कराने के एवज में आवेदक को भारी-भरकम राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है. जैसे दिल्ली पुलिस से चोरी हुए मोबाइलों के बारे में सूचना मांगने पर सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जैन से 13,949 रुपये जमा कराने के लिए कहा गया. सुबोध ने दिल्ली पुलिस से 10 ज़िलों से चोरी हुए मोबाइल, प्राप्त हुए मोबाइलों के बारे में जानकारी मांगी थी. पुलिस का कहना था कि इन सूचनाओं को एकत्र करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर को दो दिनों तक लगाया जाएगा, जिसका मेहनताना 1546 रुपया आंका गया. साथ ही बताया गया कि इस काम के लिए दो हेड कांस्टेबलों को तीन दिनों तक और 13 कांस्टेबलों को दो दिनों तक लगाया जाएगा. हेड कांस्टेबलों के लिए 1353 और कांस्टेबलों के लिए 11,050 रुपये जमा कराने को कहा गया.

भोजपुर ज़िले के गुप्तेश्वर सिंह से वहां के ज़िला आपूर्ति अधिकारी ने उनके आवेदन में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए 78 लाख 21 हज़ार 252 रुपये जमा कराने को कहा, वह भी सूचना उपलब्ध कराने की 30 दिनों की समय सीमा निकल जाने के बाद. हालांकि बाद में सूचना आयोग में अपील करने पर उक्त सूचनाएं बिना शुल्क उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए. अहमदाबाद के हुसैन अरब द्वारा दायर आरटीआई आवेदन का जवाब देने के लिए राज्य के वक्फ बोर्ड ने 4,74,690 रुपये की मांग की. हुसैन अरब ने 6 फरवरी, 2007 को आवेदन दाख़िल करके बोर्ड पर लगे प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों का ब्योरा और गुजरात चैरिटी कमिश्नर द्वारा 2001 में पारित योजना लागू न करने का कारण जानना चाहा था. हुसैन ने एक अन्य आवेदन दाख़िल करके जब बोर्ड के दस्तावेज़ों के निरीक्षण की मांग की तो उनका आवेदन ही खारिज कर दिया गया. एक और दिलचस्प मामला है सुल्तानपुर का, जहां ज़िला कार्यक्रम कार्यालय ने सूचना के बदले 70 लाख रुपये की मांग कर डाली. सुल्तानपुर के आइमा गांव निवासी रमाकांत पांडे को सूचना तो नहीं मिली, उल्टे 70 लाख रुपये जमा कराने का पत्र ज़रूर मिल गया. रमाकांत ने ज़िला कार्यक्रम अधिकारी एम जेड खान के पूरे कार्यकाल के आवागमन (भ्रमण पंजिका), जनपद में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची के अलावा कई और जानकारियां मांगी थीं. निर्धारित 30 दिन बीत जाने के बाद प्रथम अपील दाख़िल की गई. जवाब में अपर निदेशक दया शंकर श्रीवास्तव ने लिखा कि ज़िला कार्यक्रम अधिकारी ने अवगत कराया था कि सूचना के लिए निर्धारित शुल्क जमा करा दिया जाए. इसके बाद 70 लाख रुपये जमा कराने की जानकारी देने वाला पत्र देखकर रमाकांत हक्के-बक्के रह गए.

धारा 7 (1) क्या कहती है

सूचना अधिकार क़ानून की धारा 7 में सूचना मांगने के लिए शुल्क की व्यवस्था बताई गई है, लेकिन धारा 7 की उपधारा 1 में लिखा गया है कि यह शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा. इस व्यवस्था के तहत सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने विभिन्न विभागों में सूचना अधिकार क़ानून के तहत अदा किए जाने वाले शुल्क आदि तय करेंगी. केंद्र और राज्य सरकारों ने इस अधिकार के तहत अपने-अपने यहां शुल्क नियमावली बनाई है और उसमें स्पष्ट किया है कि आवेदन करने से लेकर फोटोकॉपी आदि के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा. धारा 7 की उपधारा 3 में लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी बताई गई है कि वह सरकार द्वारा तय किए गए शुल्क के आधार पर गणना करके आवेदक को बताएगा कि उसे सूचना पाने के लिए कितना शुल्क देना होगा. उपधारा 3 में लिखा गया है कि यह शुल्क वही होगा, जो उपधारा 1 में सरकार द्वारा तय किया गया होगा.

देश की सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने शुल्क नियमावली बनाई है. आवेदन के लिए कहीं 10 रुपये तो कहीं 50 रुपये शुल्क रखा गया. इसी तरह दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी लेने के लिए 2 से 5 रुपये तक शुल्क का प्रावधान अलग-अलग राज्यों में मिलता है. दस्तावेज़ों एवं काम के निरीक्षण, सीडी, फ्लॉपी पर सूचना लेने के लिए भी शुल्क इन नियमावलियों में बताया गया है. धारा 7 की उपधारा 3 कहती है कि लोक सूचना अधिकारी यह गणना करेगा कि आवेदक ने जो सूचना मांगी है, वह कितने पृष्ठों में है या कितनी सीडी-फ्लॉपी आदि में है. वह सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली में बताई गई दर से यह गणना करेगा कि आवेदक को सूचना लेने के लिए कुल कितनी राशि जमा करानी होगी. लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार कतई नहीं दिया गया है कि वह मनमाने तरीक़े से शुल्क की गणना करे और आवेदक पर मोटी रकम जमा कराने के लिए दबाव डाले. अगर कोई लोक सूचना अधिकारी मनमाने तरीक़े से, सरकार द्वारा तय शुल्क से ज़्यादा पैसा मांगता है तो उसका यह कार्य ग़ैरक़ानूनी है. साथ ही क़ानून का यह प्रावधान ध्यान में रखना होगा कि अगर लोक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना तय समय समय के अंदर (30 दिन या जो भी अन्य समय सीमा हो) उपलब्ध नहीं कराता है तो वह सूचना देने के लिए आवेदक से कोई शुल्क नहीं मांग सकता. आवेदक को जब भी सूचना दी जाएगी, वह बिना कोई शुल्क लिए दी जाएगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

सेक्सी लुक का राज गाजर!

सब्जियों और सलाद के रूप में प्रयोग होने वाली गाजर के बारे में क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि वह कितने काम की चीज है. आपको जानकर हैरत होगी कि अगर आप गाजर का सेवन रोज करने लगें तो आपको किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. गाजर में पाए जाते हैं विटामिन, जो आंखों के लिए काफी फ़ायदेमंद होते हैं. गाजर चेहरे की झुर्रियों को दूर करती है. गाजर खाने से आंखों के नीचे के काले धब्बे दूर होते हैं. गाजर बालों को टूटने से रोकती है. गाजर आपकी हड्डियों और दांतों को मज़बूत बनाती है. गाजर खाने से सेक्स पावर बढ़ता है. अगर गर्भवती महिला गाजर खाती है तो उसके गर्भ में पलने वाले बच्चा काफी स्वस्थ पैदा होता है, उसे आंखों और त्वचा से संबंधित रोग नहीं होते. यही नहीं, महिलाओं को प्रसव के दौरान तकलीफ भी कम होती है. गाजर दिल का भी हिसाब-किताब ठीक से रखती है. अगर आप गाजर को हलवा और सब्जी के रूप में नहीं खा पा रहे हैं तो सुबह के नाश्ते में गाजर अच्छी तरह धोकर नमक के साथ खाइए. रोजाना गाजर सेवन करने से आपके चेहरे पर निखार आएगा, साथ ही यह आपको सेक्सी लुक भी प्रदान करेगी. यक़ीन न हो तो आजमा कर देखें, फ़र्क़ आप ख़ुद महसूस करेंगे.

जलवायु परिवर्तन और मूंगा

दुनिया में मूंगा चट्टानों को बचाने की कोशिशें इतनी धूमिल पड़ गई हैं कि अब यह योजना बनाई जा रही है कि भविष्य में इन्हें संरक्षित करने के लिए नमूनों को फ्रीज़ (जमा कर) करके रखा जाए. डेनमार्क में हुई एक बैठक में शोधकर्ताओं के उन साक्ष्यों पर चर्चा हुई कि मूंगे की बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं, जिनका बचना मुश्किल है. शोध के अनुसार, अगर हरित गैसों के उत्सर्जन पर कठोर नियमों का पालन किया जाए तो भी मूंगे की कुछ प्रजातियां नहीं बचेंगी. इसीलिए वैज्ञानिकों ने मूंगे की कुछ प्रजातियों के नमूनों को द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित करने का सुझाव दिया है. ऐसा करने से इन प्रजातियों को वैश्विक तापमान स्थिर रहने की स्थिति में भविष्य में दोबारा समुद्र में छोड़ा जा सकता है. लंदन की ज़ूलोजिकल सोसाइटी के वैज्ञानिक साइमन हार्डिंग ने कहा, यह जैव विविधता को बचाने का बेहतर तरीक़ा है और इस तरह की कोशिशों से मूंगों को दोबारा तैयार किया जा सकता है. डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगेन में इस समय जलवायु परिवर्तन को लेकर सोलह बड़े देशों के सांसदों की बैठक चल रही है. बैठक का आयोजन ग्लोबल लेजिस्लेटर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए बैलेंस्ड एनवॉयरनमेंट यानी ग्लोब ने किया है. इस बैठक में जिन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उनमें एक यह भी है कि मूंगा चट्टानों को बचाने के लिए क्या करना है. मूंगा दुनिया भर में क़रीब पांच सौ करोड़ लोगों के भोजन और आय का प्रमुख स्रोत होने के साथ-साथ समुद्र तट की सुरक्षा का भी प्रमुख साधन है. बैठक में नेताओं और वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि दुनिया भर में कार्बनडाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन इस क़दर बढ़ रहा है कि मूंगे को बचाने की लड़ाई हम हार रहे हैं. आधुनिक शोध के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशिया स्थित मूंगा त्रिकोण, जो दुनिया भर में मूंगा चट्टानों का सबसे घना क्षेत्र है, जलवायु परिवर्तन की वजह से इस शताब्दी के अंत तक नष्ट हो सकता है और खाद्य सुरक्षा एवं लोगों के जीवनयापन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह किसी ज्ञात या अज्ञात कारण से आप पर व्यय का बोझ आने वाला है. इसके लिए आपको धैर्य के साथ परिस्थितियों से जूझना होगा. अपनी सूझबूझ और चालाकी के चलते आप इन सब मामलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
आपकी ग्रह दशा क्लेश और झगड़े से दूर रहने का संकेत दे रही है. कोई विवाद पैदा हो सकता है. बाद में सुलह-शांति हो जाएगी, लेकिन मानसिक तनाव और कई प्रकार की आशंकाएं आपको बेचैन रखेंगी. किसी से अपनी बात कहकर मन का बोझ हल्का कर सकते हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
ग्रहदशा आपके हर काम में यथासंभव मददगार साबित हो रही है. लगातार मिलने वाली सफलता से आपका आत्मविश्वास मज़बूत होगा. संपर्क सूत्र और शुभचिंतक आपके लिए नए व्यापार या कारोबार के द्वार खोल सकते हैं. हो सकता है, आप कुछ दिनों तक काफी व्यस्त रहें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
अपने कामकाज और व्यापार को सुधारने के लिए आप कोई नई पहल करेंगे. यदि आप कोई काम करने के लिए तत्पर रहेंगे तो दूसरे भी आपका अनुसरण कर सकते हैं. यदि परिणाम अनुकूल हो जाते हैं तो इस सबका क्रेडिट आपको ही मिलेगा. आपकी सलाह और नेतृत्व करने की क्षमता सभी के लिए एक आदर्श बन सकती है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
व्यक्तिगत या कार्य क्षेत्र से संबंधित संवेदनशील मामले हल करने की इच्छा रहेगी. आपको दूसरों की बातों पर भी ध्यान देना होगा और जो लोग आपको नई तरकीब और रास्ता बता रहे हैं, उनके लिए भी मार्ग तय करना होगा. जहां तक आर्थिक प्रबंधन का सवाल है, अभी ऐसी कोई भारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आ रही है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
यदि आप अपनी समस्याओं पर लोगों की राय मांगेंगे तो सभी आपके सामने अपनी प्रतिक्रिया ख़ुशी से ज़ाहिर करेंगे. नौकरी और घरेलू योजनाएं सफलता की ओर बढ़ सकती हैं. हो सकता है, ख़रीददारी का मूड भी बन जाए. घर से बाहर निकलना लाभप्रद रहेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
कारोबार के आर्थिक मामलों को निपटाने के लिए जमा पूंजी और बजट पर गंभीरता से विचार करना होगा. यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी ऐसे ज़रूरी निवेश या धन लाभ से वंचित हो जाएंगे, जो आगे चलकर एक फ़ायदे का सौदा बन सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
ख़र्च में कटौती करना आजकल आपके लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है. ज़रूरी और महत्वपूर्ण कार्य बार-बार आपके धनकोष और जेब पर भारी पड़ते जा रहे हैं. वैसे कुछ दिनों में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
कई मोर्चे पर आपको बार-बार सोच-विचार करना पड़ रहा है और यह सब आज की ज़रूरत के हिसाब से ही चल रहा है. यदि आप किसी कारोबार या व्यापार से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका पीछा कर रहे हैं. कुछ समय देकर उनसे मिलना भी आवश्यक होगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाबी हासिल होगी. नौकरी या व्यापार में बहुत बड़े स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे आपके व्यक्तित्व के अनुसार ठीक हो रहे हैं. कुल मिलाकर आपको अपने व्यय पर अंकुश लगाना होगा और अपनी आदतें सुधारनी होंगी.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह आपका ध्यान भोजन, फैशन और धन अर्जित करने में लगा रहेगा. किसी अच्छे व्यापार स्थल या शॉपिंग मॉल्स में जाकर कोई बहुमूल्य चीज ख़रीदने की योजना बनेगी. हो सकता है, किसी सभा-समारोह या पार्टी में आपको बुलाया जाए, लेकिन यह सब आप अपने अनुसार पूरा करेंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
नई साझेदारी या कारोबार करने के लिए अच्छे प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं. जीवनसाथी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना जरूरी होगा. अगर आप कुछ मामलों में जीवनसाथी से बेहतर सोच पैदा कर सकें तो उत्तम होगा. कोई ऐसा भी है, जो लंबे समय से आपको याद कर रहा है, वह अचानक कहीं पर आपको मिल सकता है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

आईडीबीआई बैंक इस सार्थक पहल में अपनी भागीदारी निभा रहा है. मौजूदा समय में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011 के माध्यम से अपनी वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया है.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

वित्तीय समावेशन की अनोखी पहल

पिछले दशक के दौरान भारत ने दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ख़ुद को स्थापित किया है. ऐसे ही समय में वहां उच्च विकास दर की स्थिरता के बारे में एक नई बहस की शुरुआत भी हुई है. इस बहस में अमीरों और ग़रीबों के बीच बढ़ती खाई के बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की गई है. दरअसल, विकास के मामले में भारत नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है. देश हर क्षेत्र में आशातीत लक्ष्य हासिल कर रहा है. वित्तीय क्षेत्र में तो भारत दुनिया के तमाम विकसित देशों के मुक़ाबले बेहतर स्थिति में है. हालांकि विकास की यह गुणवत्ता सही मायनों में अगर समावेशी नहीं है तो विकास की गति में स्थायित्व संभव नहीं है. नीति के नज़रिए से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. सरकार ने सतत विकास के साथ-साथ सतत विकास दर हासिल करने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है. हाल के वर्षों में सरकार ने वित्तीय समावेशन की एक ऐसी पहल की है, जिसके तहत जनता को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिल सके. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्रों का विस्तार बड़े पैमाने पर किया गया है, जिससे ग्रामीण आबादी सीधे तौर पर बैंकिंग से जुड़ सके. इस संदर्भ में वित्तीय समावेशन समान विकास को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त बन गया है.

आईडीबीआई बैंक इस सार्थक पहल में अपनी भागीदारी निभा रहा है. मौजूदा समय में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011 के माध्यम से अपनी वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के तहत बैंक ने 2000 की आबादी वाले 119 गांवों का चयन किया है और वहां वित्तीय वर्ष 2012 योजना के मुताबिक़ पहुंच बनाई जा रही है. इसी तरह 2000 से लेकर 5000 की आबादी वाले गांवों में आईडीबीआई बैंक अपनी स्वर्णिम योजना वित्तीय वर्ष 2013 के तहत वित्तीय समावेशन शुरू करेगा. इस पूरी प्रक्रिया में बैंक द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की आधुनिक तकनीक पर आधारित स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के कार्य किए जा रहे हैं. आईडीबीआई बैंक प्रबंधन की मानें तो इस योजना को गांवों में चरणबद्ध तरीक़े से लागू किया जा रहा है. आईडीबीआई बैंक प्रबंधन के मुताबिक़, अन्य विनिर्देशी कार्यक्रमों के लिए भी एक बॉयोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जा रहा है. इन कार्यक्रमों के लागू होने के बाद देश के गांव भी सीधे तौर पर अत्याधुनिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ सकेंगे. इन गांवों के बैंकिंग ग्राहकों को काफी फ़ायदा मिलेगा. एक लिहाज़ से देखें तो यह उनके लिए एक मंच जैसा ही होगा.

आईडीबीआई बैंक ने मुंबई के 46 ग़ैर बैंकिंग गांवों में ग़रीबों के लिए वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत अपने बैंकिंग कार्यान्वयन की औपचारिक शुरुआत की. इन गांवों में संबंधित लाभकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इन योजनाओं की डीएमडी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी समीक्षा की गई. प्रारंभिक चरण में जमा, नगदी और बैंकिंग सेवाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है. अगले वित्तीय वर्ष में बैंक के माध्यम से ऋण, बीमा मूल्य का भुगतान, सूक्ष्म बीमा एवं प्रीमियम जैसे अन्य बैंकिंग कार्यक्रमों के ज़रिए ग्राहकों को सेवा प्रदान करके उन्हें जोड़ने की पेशकश की गई है. हालांकि इस वित्तीय पहल के लिए साक्षरता और जागरूकता का प्रयास किया जाना बेहद ज़रूरी है. महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले के 137 गांवों में नाबार्ड की मदद से जगह-जगह पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन करके ग्रामीणों को वित्तीय लेनदेन और बैंकिंग प्रणाली के बारे में जागरूक किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास में नाबार्ड लगातार अहम किरदार निभा रहा है, क्योंकि गांवों के विकास में उसकी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं. ग्रामीण विकास, किसानों का उत्थान, कृषि उत्पादन में वृद्धि और महिला सशक्तिकरण सहित तमाम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संस्था का उदय हुआ. यह आज देश की अस्सी प्रतिशत ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचा रही है. इस मुहिम में आईडीबीआई बैंक ने भी अहम भूमिका निभाई है.

महाराष्ट्र के ही सतारा ज़िले के कई गांवों में ग्रामीणों के बीच स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसके तहत लोगों को नए स्वयं सहायता समूह खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इन गांवों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया. प्रशिक्षण कार्यशाला में ग्रामीणों में बचत की भावना विकसित करने, जन भागीदारी से विकास कार्य कराने, स्वरोज़गार की स्थापना, बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया और उत्थान संबंधी कई अत्याधुनिक तरीक़े सुझाए गए. स्वयं सहायता समूह को पंजीकृत संस्थान के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसा करने के बाद समूह अपने सदस्यों के अलावा अन्य लोगों को भी ऋण मुहैय्या करा सकेगा, इससे समूह को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा. अन्य लोग भी समूह की बचत राशि से ऋण लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे. आईडीबीआई बैंक प्रबंधन की मानें तो ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोज़गार करने की ठान लें तो उनके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस उन्हें शुरुआती मार्गदर्शन एवं सहयोग की ज़रूरत है. ग़ौरतलब है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से ग़रीबों को स्वरोज़गार उपलब्ध कराने के लिए की गई थी. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग़रीबों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से रोज़गार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा मदद की जाती है. प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य शामिल हो सकते हैं. प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को अपने ब्लॉक में 4-5 महत्वपूर्ण गतिविधियों का चयन करना होता है. इन चुनी गई गतिविधियों से समूह को कम से कम 2000 रुपये मासिक आय अवश्य होनी चाहिए.

इन गतिविधियों के चयन में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मदद ली जा सकती है. स्वयं सहायता समूहों को अनुदान दिया जाता है और तकनीकी प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. साथ ही विपणन (मार्केटिंग) संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है. उन्हें एनजीओ, समुदाय आधारित संगठनों, बैंकों, पंचायती राज संस्थाओं एवं ज़िला ग्रामीण विकास संस्थाओं से संबंधित ग़रीबी उन्मूलन के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया जाता है. आईडीबीआई बैंक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित गांवों और शहरी ग़रीबों के लिए निर्माण, निवेश एवं बचत जैसे कार्यक्रमों के अवसर प्रदान कर रहा है, ताकि आने वाले दिनों में गांवों और शहरों के बीच दूरियां कम हो सकें.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र के ही सतारा ज़िले के कई गांवों में ग्रामीणों के बीच स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसके तहत लोगों को नए स्वयं सहायता समूह खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इन गांवों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया. प्रशिक्षण कार्यशाला में ग्रामीणों में बचत की भावना विकसित करने, जन भागीदारी से विकास कार्य कराने, स्वरोज़गार की स्थापना, बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया और उत्थान संबंधी कई अत्याधुनिक तरीक़े सुझाए गए.

e देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

एक दिन बाबा ने राधाकृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा. एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके कहे अनुसार वामन गोंदकर के घर पर उसे लगाया.

बाबा के उपदेश

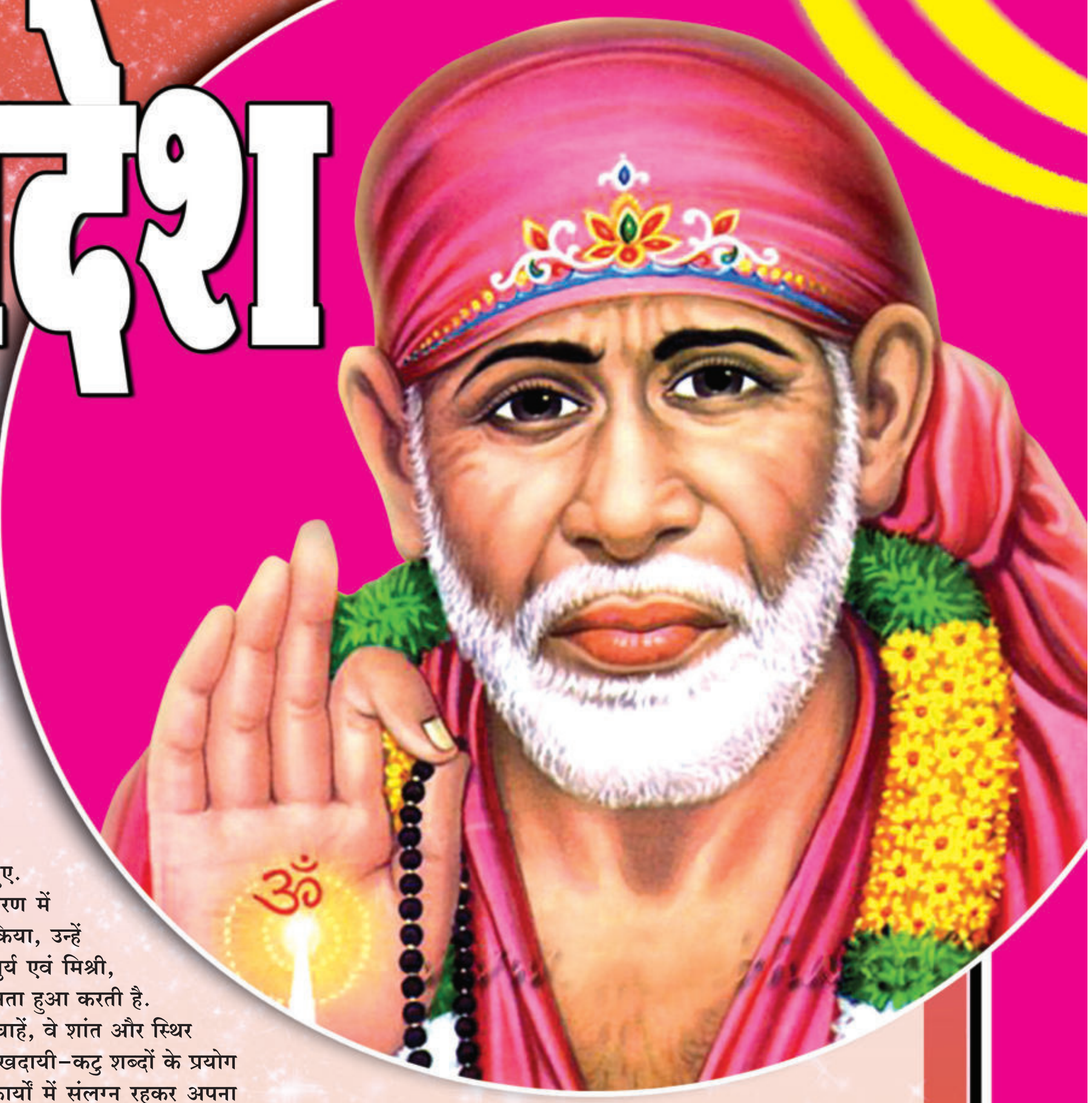

बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूं. केवल उनके भ्रम निवारणार्थ, जिनकी दृष्टि में वह साढ़े तीन हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए. इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और जिन्होंने दिन-रात उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई. जिस प्रकार माधुर्य एवं मिश्री, लहर एवं समुद्र और नेत्र एवं कांति में अभिन्नता हुआ करती है. जो लोग आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहें, वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें.

उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न करके बाबा यथायोग्य समय पर स्वतंत्रतापूर्वक उपदेश दिया करते थे. एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे. गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के प्रति दोषारोपण में इतने कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी. बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करके विवाद उत्पन्न करते हैं. संत तो परदोषों को दूसरी दृष्टि से देखा करते हैं. उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की युक्ति भिन्न होती है. वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिव्हा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा करके उनका उपकार ही करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं. निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साई बाबा की पद्धति सर्वथा भिन्न थी. वह तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उस निंदक के कार्य को समझ गए. जब लेंडी के समीप उससे भेंट हुई, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो, वह कितने प्रेमपूर्वक विष्ठा खा रहा है. तुम भी जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है. अनेक शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ और यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी क्या सहायता कर सकेगी. कहने का तात्पर्य केवल यह है कि भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वह वहां से चला गया. इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वह उपदेश दिया करते थे. यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर न होगा.

एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्रीहरि होगा तो वह मुझे चारपाई पर बैठे-बैठे ही भोजन पहुंचाएगा. यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति नहीं कर सकेगा, उलटे पतन के घोर अंधकार में गुम हो जाएगा. इसलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए सबको अनवरत परिश्रम करना चाहिए. बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूं. केवल उनके भ्रम निवारणार्थ, जिनकी दृष्टि में वह साढ़े तीन हाथ के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए. इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और जिन्होंने दिन-रात उनका ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई. जिस प्रकार माधुर्य एवं मिश्री, लहर एवं समुद्र और नेत्र एवं कांति में अभिन्नता हुआ करती है. जो लोग आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहें, वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें. दु:खदायी-कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दु:खी न करके सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भयरहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए. जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निस्संदेह आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी. उन्होंने अनेक लोगों से नाम का जपकर अपनी शरण में आने को कहा. जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूं. बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण-मनन करने का परामर्श दिया. किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद पूजन तो किसी को अध्यात्म रामायण, ज्ञानेश्वरी एवं धार्मिक ग्रंथों का पठन-अध्ययन करने को कहा. कई लोगों को उन्होंने अपने चरणों के समीप रखा, बहुतों को खंडोबा मंदिर भेजा और कई लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का जप और छांदोग्य उपनिषद एवं गीता का अध्ययन करने को कहा. उनके उपदेशों की कोई सीमा नहीं थी. उन्होंने किसी को प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए. एक बार वह एक मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रगट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब उसने मद्यपान त्यागने की शपथ खाई, तभी उसे छोड़ा. किसी-किसी को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु आदि का अर्थ स्वप्न में समझाया और कुछ हठयोगियों को हठयोग छोड़ने की राय देकर चुपचाप बैठकर धैर्य रखने को कहा. उनके सुगम पथ और विधि का वर्णन असंभव है.

साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए. एक दिन बाबा ने राधाकृष्ण माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा. एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके कहे अनुसार वामन गोंदकर के घर पर उसे लगाया. वह उनके घर पर चढ़ गए और राधाकृष्ण माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए. इसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया. राधाकृष्ण माई उस समय ज्वर से कांप रही थीं. इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया हो. नीचे उतरने के बाद शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को दो रुपये पारिश्रमिक स्वरूप दिए. तब एक ने साहस करके उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है. उन्होंने कहा कि बिना परिश्रम का मूल्य चुकाए किसी से कार्य नहीं कराना चाहिए और कार्य करने वाले को उदार हृदय से मज़दूरी देनी चाहिए. यदि बाबा के इस नियम का पालन किया जाए यानी मज़दूरी का भुगतान शीघ्र और संतोषप्रद हो तो मज़दूर अधिक उत्तम कार्य करेंगे, लगन से कार्य करेंगे. फिर कार्य छोड़ने एवं हड़ताल जैसी कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी और न मालिक और मज़दूरों के बीच वैमनस्य पैदा होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साई महाराज के चरण कमल

अपने भक्तों को किसी आसन, प्राणायाम अथवा उपासना का आदेश नहीं दिया और न उनके कानों में कोई मंत्र फूंका. उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साई-साई स्मरण करो. इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी. मन का कार्य विचार करना है. बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता.

शिरडी में नानावल्ली नामक एक विचित्र व्यक्ति था. वह बाबा के सारे कामकाज की देखभाल करता था. एक दिन जब बाबा गादी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा. वह स्वयं गादी पर बैठना चाहता था. उसने बाबा को वहां से हटने को कहा. बाबा ने तुरंत गादी छोड़ दी और नानावल्ली वहां विराजमान हो गया. थोड़े ही समय वहां बैठकर वह उठा और उसने बाबा से अपना स्थान ग्रहण करने को कहा. बाबा पुन: आसन पर बैठ गए. यह देखकर नानावल्ली उनके चरणों में गिर पड़ा और फिर भाग गया. इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में रंचमात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी. यद्यपि बाह्य दृष्टि से श्री साई बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदृश था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट प्रतीत होती थी. उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निमित्त होते थे. उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन, प्राणायाम अथवा उपासना का आदेश नहीं दिया और न उनके कानों में कोई मंत्र फूंका. उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साई-साई स्मरण करो. इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी. मन का कार्य विचार करना है. बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता. यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा और यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा.

यह स्वाभाविक स्मरण और पूजन ही साई का कीर्तन है. संतों की कथा का स्मरण उतना कठिन नहीं, जितना अन्य साधनाओं का, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है. ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती हैं, इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा इन्हें आचरण में भी लाओ. सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रहो. यह निश्चित है कि वह कृपा अवश्य करेंगे. यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि हर कोई इसका अनुसरण नहीं करता. कारण केवल यह है कि ईश कृपा के अभाव के चलते लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती. ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुंदर ढंग से चलता है. संतों की कथा का श्रवण ही संत समागम सदृश है. संतों के सानिध्य का अपना महत्व है. उससे दैहिक बुद्धि अहंकार और जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है. हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो कि चैतन्यघन स्वरूप है. विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है और दु:खों एवं सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है. यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति आदि नहीं करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ तो वे तुम्हें आसानी से भवसागर के उस पार उतार देंगे. इसी कार्य के निमित्त संत विश्व में प्रगट होते हैं. पवित्र नदियां यानी गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी आदि, जो संसार के समस्त पापों को धो देती हैं, वे भी सदैव इच्छा करती हैं कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से उन्हें पावन करे. ऐसा संतों का प्रभाव है. गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरुप ही श्री साई चरणों की प्राप्ति संभव है. उनका स्वरूप सुंदर और मनोहर है. वह इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते थे. ऐसे सच्चिदानंद श्री साई महाराज के चरणों में मेरा बार-बार नमस्कार.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप,
परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप,
परम पुरूष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं,
उनको बार बार नमस्कार.

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं.

स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

अनंत विजय

अन्ना हजारे, भ्रष्टाचार और नैतिकता

आज देश भर में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जिस तरह का माहौल बना है, उसमें मैंने भी तय किया कि साहित्य पर न लिखकर इस बार अपने स्तंभ में भ्रष्टाचार पर लिखूं. अन्ना हजारे के समर्थन में जिस तरह पूरे देश में लोग उठ खड़े हुए हैं, वह सरकार के लिए चिंता की बात है. आज़ादी के 64 वर्षों बाद भी आज देश की जनता को अपनी आज़ादी को लेकर एक संदेह, एक आशंका सी पैदा हो गई है. इस संदेह की वजह यह है कि पूरे देश में इस वक़्त भ्रष्टाचार का बोलबाला है. समाज के सबसे निचले स्तर से लेकर देश के शीर्ष स्तर को भ्रष्टाचार की विषबेल ने जकड़ लिया है. चाहे वह पौने दो लाख करोड़ का टेलीकॉम घोटाला हो, सत्तर हज़ार करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो, हज़ारों करोड़ का अंतरिक्ष घोटाला हो, शहीदों के परिवारों को मिलने वाले घरों का आदर्श घोटाला हो या फिर आईपीएल घोटाला. आज जिधर नज़र दौड़ाइए, घोटाले उधर ही मुंह बाए खड़े हैं. सारे घोटालों के केंद्र में या कहें कि हर भ्रष्टाचार की धुरी या तो कोई कांग्रेसी नेता है या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार को समर्थन दे रही पार्टी का नेता. हर घोटाले के बाद कांग्रेस पार्टी यह दलील देती नज़र आती है कि अमुक घोटाले के लिए फलां नेता और मंत्री ज़िम्मेदार है, लेकिन इस बात को लेकर कभी कोई सवाल नहीं उठता कि जिस मंत्रिमंडल के सदस्य घोटाले कर रहे हैं, उसके मुखिया की भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है या नहीं. हर कोई इस बात की दुहाई देता नज़र आता है कि देश के प्रधानमंत्री बहुत साफ–सुथरी छवि के हैं. उनके दामन पर दाग़ नहीं है. अरे भाई, उस साफ– सुथरी छवि को लेकर देश की जनता क्या करे. देश छवि से नहीं चलता. देश चलाने के लिए कड़े फ़ैसले लेने होते हैं. उस भले और ईमानदार आदमी का हम क्या करें, जिसकी नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं, लेकिन वह और उनके कारिंदें कहते हैं कि ये सब उनकी जानकारी में नहीं हुआ. क्या हम यह मान लें कि आज़ादी के लगभग साढ़े छह दशक बाद प्रधानमंत्री नाम की संस्था को गठबंधन की राजनीति ने कमज़ोर कर दिया है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार हैं, होंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ़ से आंखें मूंद ली है, उससे एक संदेह का वातावरण तो उनके इर्द–गिर्द भी बन ही जाता है. आप लाख ईमानदार हों, लेकिन आपके सहयोगी भ्रष्टाचारी हैं तो उसके छींटे तो आपके दामन पर भी पड़ेंगे ही. अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, अ मैन इज नोन बाइ हिज कंपनी, ही कीप्स.

ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी और उसके नेता ही भ्रष्ट हैं. देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में भी येदुरप्पा जैसे लोग हैं, जिनका दामन दागदार है. येदुरप्पा पर ज़मीन घोटाले के आरोप लगे, लेकिन भाजपा को उन पर कार्रवाई करने के लिए लोकायुक्त की रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ा. सार्वजनिक जीवन में शुचिता और उच्च सामाजिक मानदंडों की वकालत करने वाली पार्टी भाजपा झारखंड में शिबू सोरेन के साथ मिलकर सरकार चला रही है. शिबू सोरेन पर पहले भी भ्रष्टाचार समेत हत्या और हत्या की साजिश रचने के संगीन इल्ज़ाम लग चुके हैं. उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार के खिलाफ भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समेत कई सरकारी योजनाओं में घपले–घोटाले

की जांच चल रही है. मायावती पर आय से अधिक संपत्ति का मुक़दमा विचाराधीन है. उत्तर प्रदेश सरकार पर कैग की ताजा रिपोर्ट में बेहद गंभीर आरोप लगे हैं. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर भी भ्रष्टाचार का मुक़दमा चल रहा है.

समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और हरियाणा के चौटाला पिता–पुत्र के ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा जारी है. लालू यादव और कई सूबों के अन्य नेताओं के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है, यह सूची बहुत लंबी है. अभी–अभी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी की संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं. यह अकारण नहीं है कि देश के तीस मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्तियां क़रीब ढाई सौ करोड़ रुपये की हैं. इस अनुमान के मुताबिक़, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति आठ करोड़ रुपये है, लेकिन अगर उसमें से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री (अब पूर्व) करुणानिधि की संपत्ति हटा दी जाए तो देश के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति घटकर क़रीब चार करोड़ रुपये रह जाएगी. तक़रीबन 87 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और दलित नेता मायावती देश की सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं. दो हज़ार दस में मायावती ने बताया था कि उनकी संपत्ति तीन साल में 35 करोड़ रुपये बढ़ गई है यानी तीन साल में बावन करोड़ से बढ़कर सत्तासी करोड़, तक़रीबन सड़सठ फ़ीसदी का इज़ाफ़ा. केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट पर भी अगर नज़र डालेंगे तो यह अमीरी नज़र आएगी. कहां से आ रहे हैं ये पैसे, ये तो घोषित संपत्ति है. क्या कोई अघोषित संपत्ति भी है? इस तरह के सवाल पूरे देश को मथ रहे हैं.

कोई कहता है कि उसके समर्थक चंदा देते हैं तो कोई अपने कारोबार के बूते करोड़पति बनने की बात कर रहा है. नतीजा यह हो रहा है कि पूरे देश में इस वक़्त पॉलिटिकल क्लास को लेकर जनता के मन में एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है. आज़ादी के तक़रीबन चौंसठ साल बाद भी आज देश की जनता अपने चुने हुए नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रही है तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद ख़तरनाक बात है. यह पॉलिटिकल क्लास के लोगों के लिए आत्ममंथन का भी वक़्त है. इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ काम करने वाली संस्थाओं पर ही हमले करने लगी है. जब सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ आती है तो कांग्रेस के प्रवक्ता उस संस्था को ही सवालों के घेरे में ले लेते हैं. उसके पहले टेलीकॉम घोटाले में कैग की रिपोर्ट की जांच कर रही संसद की लोकलेखा समिति पर भी कांग्रेस के लोगों ने इसी तरह से सवाल खड़े कर दिए थे. भ्रष्टाचारियों को बचाने या फिर उनके समर्थन के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर हमलों से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भ्रष्ट लोगों की ज़्यादा चिंता है, बजाय संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा की. जिस तरह उन्नीस सौ पचास में सीएजी का गठन करके उसे संवैधानिक आज़ादी दी गई और जिसे जवाहर लाल नेहरू ने अपने शासनकाल में मज़बूती दी, आज उस पर ही इस वक़्त के कांग्रेसी उंगली उठा रहे हैं.

दरअसल आज कांग्रेस के पास आज़ादी के आंदोलन से तपकर निकले जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एस राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता नहीं हैं, जो एक नैतिक उदाहरण पेश कर सकें. अन्ना ने ईमानदारी की जो नैतिक चुनौती सरकार को दी है, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है. कपिल सिब्बल हों या फिर चिदंबरम या फिर विवादित बयानों के लिए चर्चित दिग्विजय सिंह, इन सबमें वह नैतिक ताक़त नहीं है, जो अन्ना हजारे का मुक़ाबला कर सके. उससे भी चिंता की बात यह है कि देश में इन भ्रष्ट नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई न होते देख जनता क्षुब्ध होने लगी है, उसका धैर्य जवाब देने लगा है. आज पॉलिटिकल क्लास को जनता की इस नाराज़गी का संज्ञान लेना चाहिए.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

साहित्य जगत में तकनीकी क्रांति

सोनिका गुप्ता

वर्तमान समय तकनीक का युग हो गया है. इससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है. भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में दुनिया बहुत तेज़ी से सिकुड़ती और नज़दीक आती जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हैं, जहां कथा साहित्य बहुतायत में उपलब्ध हो सकता है. हर क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. यही हमें साहित्य में भी देखने को मिल रहा है. पहले काम घंटों में भी पूरे नहीं होते थे, लेकिन अब मिनटों, सेकंडों में पूरे हो जाते हैं और यह केवल संभव हुआ इंटरनेट की दुनिया से. पुराने समय में गंभीर पाठक किताबों और लाइब्रेरी पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा. अब इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया ने इस क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति की है. अब पाठक लाइब्रेरियों में समय न नष्ट करके घर पर बैठकर इंटरनेट पर साहित्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. यह एक विरोधाभास है कि जिस इंटरनेट पर हम गंभीर पठन–पाठन का विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, वही इंटरनेट आज हिंदी साहित्य के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इंटरनेट ने हिंदी साहित्य को आज चर्चा का व्यापक दायरा दिया है.

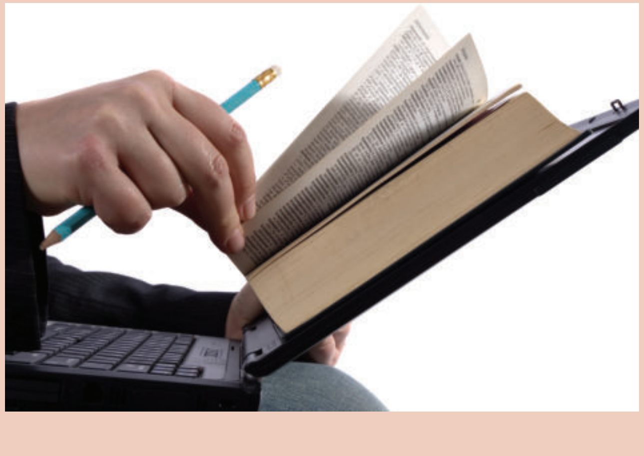

ऐसे समय में जब बदलाव की आहट आपकी हर धड़कन में शामिल होती जा रही है, साहित्य का परंपरागत चेहरा भी बदलाव के रंगों से रंगता नज़र आ रहा है. अकाल मृत्यु की तमाम घोषणाओं के बीच हिंदी साहित्य न सिर्फ़ चुपचाप नई ज़मीन पर उग रहा है, बल्कि अपने पंख भी पसार रहा है. साहित्य अब किताबों–पत्रिकाओं के ठोस पन्नों के साथ इंटरनेट के व्यापक दायरे में समा चुका है. लोग फ़ेसबुक के अपने वॉल पर फ़ैज की नज़्मों को, सर्वेश्वर, शमशेर और मुक्तिबोध की कविताओं को शेयर कर रहे हैं, जी–मेल के स्टेटस मैसेज में किसी कविता के अंश को चस्पा कर रहे हैं. साहित्य को समर्पित ऐसी कई वेबसाइट्स, ब्लॉग और हैं, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हैं. इंटरनेट कविता, कहानी और साहित्य केंद्रित बहसों के साथ ही साहित्यिक गॉसिपों के भी जीवंत माध्यम के रूप में उभरा है. आज कई साहित्यकार अपने ब्लॉगों के सहारे सक्रिय होते जा रहे हैं. कुमार अंबुज, उदय प्रकाश, गीत चतुर्वेदी, प्रभात रंजन जैसे साहित्यकार ब्लॉग के सहारे अपने पाठकों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं. आज से दस वर्ष पहले तक साहित्यिक बहसों का मुख्य माध्यम लघु पत्रिकाएं हुआ करती थीं. अब यही काम वेबसाइटों और ब्लॉगों द्वारा किया जा रहा है. साहित्य को हर किसी के लिए सुलभ बनाने में वेबसाइटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसमें कविता कोश की भूमिका खास तौर पर ग़ौर करने लायक़ है. क़रीब पांच साल पहले शुरू किए गए इस वेब कविता इंसाइक्लोपीडिया ने कविता पढ़ने का पुराना तरीक़ा ही बदल दिया है.

इस पर आज हिंदी के अलावा अन्य देशी–विदेशी भाषाओं में अनुवाद की गईं 42 हज़ार से ज़्यादा कविताएं हैं. तक़रीबन 1500 कवियों के पेज हैं. दिलचस्प यह है कि हिंदी कविताओं के इस वेब संकलन को तैयार करने का काम किसी साहित्यकार ने नहीं किया और न साहित्य को बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी निभाने वाली संस्थाओं ने किया. कविता कोश की शुरुआत करने वाले ललित कुमार पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं. विदेशों में रहे ललित ने कभी अपने शौक के कारण इंटरनेट पर बिखरी कविताओं को निजी साइट पर संकलित करना शुरू किया था. ललित बताते हैं, मुझे कविताएं पढ़ने का काफ़ी शौक है. जब मैं इंटरनेट पर किसी कविता को खोजता था, तब कई बार मुझे वे मिल भी जाती थीं, कई बार मुझे निराशा का सामना करना पड़ता था. कई बार ऐसा भी हुआ कि जो कविता मैं खोजकर थक चुका होता था, वह अचानक मेरे सामने हाज़िर हो जाती थी. तब मैंने नेट पर उपलब्ध कविताओं का संकलन करना शुरू किया. यह सब निजी शौक की तरह चलता रहा. इस तरह ललित के निजी प्रयासों से नेट पर उपलब्ध कविताओं को पहली बार एक छतरी के नीचे लाया गया. जब काफ़ी कविताएं इकट्ठा हो गईं, तब कहीं जाकर हिंदी कविताओं के व्यापक वेब संकलन को तैयार करने का विचार आया.

साहित्य को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने का ऐसा ही गंभीर प्रयास वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की तरफ़ से किया जा रहा है. सांस्थानिक सहयोग मिलने के कारण काफ़ी कम समय में विश्वविद्यालय की साइट हिंदी समय डॉट कॉम पर आज कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध, आलोचना और पत्र जैसी विधाओं की सामग्री का अच्छा–खासा संकलन तैयार हो गया है. इस साइट पर केदारनाथ अग्रवाल के सभी कविता संग्रह, अज्ञेय रचना संचयन, कबीर ग्रंथावली, मोहन राकेश संचयन, हरिऔध समग्र, प्रेमचंद समग्र, भारतेंदु समग्र, रामचंद्र शुक्ल समग्र जैसे रचना संचयन एक जगह मौजूद हैं. यहां विभाजन पर लिखी गई चुनिंदा कहानियों को पढ़ना भी एक सुखद एहसास हो सकता है. पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित 1950 से लेकर 2010 तक की चर्चित कहानियों का दशकवार संकलन भी इस साइट पर मौजूद है. इस पर आप कई ई–पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं. कविताकोश डॉट ऑर्ग और हिंदीसमय डॉट कॉम के अलावा कई ब्लॉग और वेबसाइट हिंदी साहित्य को आम पाठक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. अगर आपको अच्छा लिखने–पढ़ने का शौक है तो इंटरनेट पर बीसियों ऐसे ठिकाने हैं, जो आपके लिए सुकून भरे आरामगाह साबित हो सकते हैं. इन ठिकानों में एक बार घुस जाने के बाद समय के सारे बंधन आपके लिए टूट सकते हैं. कुछ अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने की आदम जिजीविषा को निश्चित ही इंटरनेट ने नया रूप दे दिया है. इंटरनेट पर साहित्य होने से बच्चों को कविता दिखाकर सिखाना सरल हो गया है. आप अपने किसी मनपसंद कवि की कविता सुन और देख सकते हैं. क्या आप आज तक इस दुनिया से दूर हैं? देर मत कीजिए, ऊपर दिए गए किसी भी वेब पते पर जाइए और साहित्य की इस नई दुनिया में शामिल हो जाइए.

sonika@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
बच्चों के श्रेष्ठ सामाजिक नाटक

लेखक
प्रकाश मनु

प्रकाशक
डायमंड बुक्स

मूल्य
125 रुपये

यह किताब बच्चों के नाटकों का एक अच्छा संग्रह है, जिसमें सोलह नाटक शामिल हैं.

ये कीबोर्ड म्यूज़िक सीखने वाले शुरुआती छात्रों के लिए उपयोगी हैं. इनमें साउंड क्वालिटी पहले के कीबोर्ड्स की तुलना में कहीं बेहतर है.

बीएमडब्ल्यू की नई कार

लग्जरी कारों के सबसे विख्यात और लग्जरी ब्रांड में से एक बावेरियन मोटर वर्क्स (बीएमडब्ल्यू) की आई 3 और आई 8 कॉन्सेप्ट कार का अनावरण किया गया. बरबस ही अपनी ओर खींचने वाली इस बेहद ख़ूबसूरत कार में कई विशेषताएं हैं. अपने नाम को सार्थक करती बीएमडब्ल्यू का विजन इफिशिएंट डायनॉमिक्स कॉन्सेप्ट कार पूरी तरह आने वाले समय के अनुसार है यानी पर्यावरण के अनुकूल है. इस कार में एक बड़ी, लग्जरी मज़बूत कार की सारी ख़ूबियां तो हैं, पर इसके ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन एक छोटी कार से भी कम है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि एक्टिव हाईब्रिड तकनीक पर आधारित विजन इफिशिएंट डायनॉमिक्स से सुसज्जित यह कार 0 से 100 किमी/प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ़ 4.8 सेकेंड में पकड़ सकती है. इतनी रफ्तार के बावजूद इसका कार्बन उत्सर्जन मात्र 99 ग्राम प्रति किलोमीटर है, जबकि इलेक्ट्रिक मॉडल में तो यह और भी कम 50 ग्राम प्रति किमी है. एक लीटर में 26.5 किमी का माइलेज देने वाली इस विजन कॉन्सेप्ट कार में 24 लीटर का डीजल टैंक है, जो कार की रेंज 700 किमी तक पहुंचा देता है. विशेष रूप से डिज़ाइन लिथियम-पॉलिमर रिचार्जेबल बैटरी किसी भी परंपरागत पॉवर सॉकेट से मात्र 2.5 घंटे में चार्ज हो जाती है. एक बार फुल चार्ज करने पर 35 किलोमीटर की ड्राइव देती है. यह कार बीएमडब्ल्यू की नवीनतम एक्टिव हाईब्रिड तकनीक और अत्याधुनिक ड्राइव सिस्टम से सुसज्जित है. 4 सीट वाली इस कार में दो विंग डोर हैं. बेहतरीन एयरोडायनामिक डिज़ाइन इस कार को कम ऊर्जा में अधिक गति प्रदान करता है. भारत में बीएमडब्ल्यू के लिए बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कंपनी ने भारतीय बाज़ार में अपनी नई कॉन्सेप्ट कार को जल्द उतारने का वादा किया है. 26.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने वाली इस कार में स्पोर्ट्स कार की सभी ख़ूबियां भी हैं. ग़ौरतलब है कि वर्ष 2010 में बीएमडब्ल्यू ने भारत में कुल 6426 कारें बेची थीं.

सीगेट मोमेंट्स एक्सटी ड्राइव

यह पारंपरिक 5400 आरपीएम ड्राइव की तुलना में 50 फ़ीसदी तेजी से सिस्टम को बूट करता है और लैपटॉप और गेमिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस में विश्व स्तर के मानकों पर खरा उतरता है.

पिछले साल मोमेंट्स एक्सटी ड्राइव लांच करने के बाद सीगेट एनएएसडीएक्यू-एसटीएक्स ने लैपटॉप पीसी के लिए दस लाखवां सॉलिड स्टेट ड्राइव (एसएसडी) लांच किया है. एलियन वेयर, एएसयूएस, डेल, सोनी और तोशिबा सहित तमाम बड़ी लैपटॉप निर्माता कंपनियां अब 2.5 इंच एसएसडी से लैस लैपटॉप मुहैया करा रही हैं. इनकी बदौलत लैपटॉप की परफॉर्मेंस बेजोड़ बन जाती है और वह भी असीमित क्षमता एवं किफायत के साथ. मोमेंट्स एक्सटी सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव 7200 आरपीएम ड्राइव है. यह 500 जीबी तक की कैपेसिटी के साथ उपलब्ध है. यह पारंपरिक 5400 आरपीएम ड्राइव की तुलना में 50 फ़ीसदी तेजी से सिस्टम को बूट करता है और लैपटॉप और गेमिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस में विश्व स्तर के मानकों पर खरा उतरता है. सीगेट की एडेप्टिव मेमोरी तकनीक ड्राइव की स्पीड के लिए सबसे अहम है. यह 4 जीबी ऑनबोर्ड सॉलिड स्टेट मेमोरी के अधिकतम इस्तेमाल से सिस्टम को तेजी से बूटअप करता है और एप्लीकेशन एक्सेस भी आसान एवं तीव्र बनाता है. आईडीसी के शोध निदेशक जॉन रिडनिंग ने कहा, सीगेट की ओर से दस लाखवें मोमेंट्स एक्सटी ड्राइव की सॉलिड स्टेट हाइब्रिड इसके उज्ज्वल भविष्य की शुरुआत भर है. तेज, अत्यधिक क्षमता वाली, किफायती हाइब्रिड एचडीडी और मोमेंट्स एक्सटी ड्राइव जैसे एनएएनडी फ्लैश स्टोरेज समाधान 2015 तक 25 फ़ीसदी नए कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहे होंगे. आजकल हाई परफॉर्मेंस एसएसडी वाली मोबाइल कंप्यूटिंग इस क्षमता वाले हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में 10 गुना ज़्यादा महंगी होती है. 250 जीबी के एसएसडी की क़ीमत कई लैपटॉप कंप्यूटर से भी ज़्यादा होती है. ज़्यादातर ग्राहक और सिस्टम निर्माता ज़्यादा स्पीड वाले एसएसडी के लिए इतनी क़ीमत नहीं चुकाना चाहते. मोमेंट्स एक्सटी ड्राइव इसकी तुलना में बहुत मामूली ख़र्च में एसएसडी की तरह स्पीड मुहैया कराती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

म्यूजिकल कीबोर्ड का नया अंदाज़

जापान और भारत में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी कैसियो ने नया मिनी कीबोर्ड एसए-78 लांच किया है. कंपनी ने भारतीय टोन और रिदम से लैस मौजूदा मिनी कीबोर्ड की सीरीज एसए-46, एसए-47, एसए-76 और एसए-77 की सीरीज में यह नई पेशकश की है. ये मिनी कीबोर्ड नए डिज़ाइन और ज़्यादा ख़ूबियों के साथ अपग्रेड किए गए हैं. इनमें चार भारतीय टोन (हारमोनियम, संतूर, सितार, शहनाई), पांच भारतीय रिदम, दस गानों का बैंक (इनमें एक भारतीय गाना भी है) और तबले के दो रूप वाले पांच म्यूज़िकल पैड हैं. ये कीबोर्ड म्यूज़िक सीखने वाले शुरुआती छात्रों के लिए उपयोगी हैं. इनमें साउंड क्वालिटी पहले के कीबोर्ड्स की तुलना में कहीं बेहतर है. इनमें 8 नोट पोलीफोनी है, जबकि पुराने मॉडल में ये सिर्फ़ 4 हुआ करते हैं. इतना ही नहीं, इन कीबोर्ड्स में 50 रिदम आते हैं, जबकि पहले के कीबोर्ड्स में केवल 30 आते हैं. कैसियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग प्रमुख के. सेठ ने कहा, बाज़ार का अगुवा होने के नाते हमारा प्रयास हमेशा ग्राहकों को बेहतरीन समाधान देने का रहा है. ग्राहकों से बातचीत कर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ज़्यादातर बच्चे संगीत शिक्षा की शुरुआत भारतीय संगीत से करते हैं. उनके माता-पिता भी यही चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स भारतीय रंग-ढंग में ढले हों. हमने उनकी इस ज़रूरत को समझा और इसीलिए अपग्रेडेड मिनी कीबोर्ड्स पेश किए, जिनमें भारतीय म्यूज़िक सपोर्ट है. मिनी कीबोर्ड्स की यह नई रेंज 2295 से लेकर 2795 रुपये में किसी भी अग्रणी म्यूज़िक, टॉय या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर उपलब्ध है.

हीरो मेस्ट्रो

जापानी कंपनी होंडा मोटर्स से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प ने पहला धमाका किया है, वह भी लंदन में. हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी नई मोटर साइकिल इंपल्स और एक नया गियरलेस स्कूटर मेस्ट्रो पेश किया है. यह मोटर साइकिल 150 सीसी है. हीरो होंडा नाम के बग़ैर बाज़ार में उतारी जाने वाली यह पहली मोटर साइकिल है, जिसे बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने पेश किया. यह बाइक ब्राजील में बिक रही होंडा एनएक्सआर 150 ब्रॉस का नया संस्करण है. इसका अगला और पिछला हिस्सा मॉडर्न स्टाइल का है. इंपल्स के मीटर डिजिटल हैं और यह पूरे भारत में मिलेगी. यह पांच रंगों में उपलब्ध है, लेकिन कंपनी ने इसकी क़ीमत की घोषणा नहीं की है. हीरो के नए स्कूटर मेस्ट्रो को क्रिकेटर इरफान पठान ने लांच किया. यह 100 सीसी का वी मेट्रिक इंजन वाला स्कूटर है.

यह बाइक ब्राजील में बिक रही होंडा एनएक्सआर 150 ब्रॉस का नया संस्करण है. इसका अगला और पिछला हिस्सा मॉर्डन स्टाइल का है.

मुंबई में एसयूवी फोर्स वन के लांच के मौक़े पर शिरकत करते बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन.

जेब्रोनॉक्सि का ख़ास मीडिया प्लेयर

कंप्यूटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार उपकरण मुहैया कराने और जेब्रोनॉक्सि ब्रांड के तहत चलने वाली अग्रणी कंपनी टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स ने जेबमेट सिनेमा 3.0 प्लस के लांच के साथ अपने प्रीमियम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर की शृंखला और समृद्ध कर ली है. यह एक टचस्क्रीन मॉडल है, जो 720 पीएचडी वीडियो को सपोर्ट करता है. जेबमेट सिनेमा 3.0 प्लस काफी छोटा होने के बावजूद बेहतरीन साउंड क्वालिटी की बदौलत जेब्रोनिक्स के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को उच्च गुणवत्ता और कम क़ीमत के नए बाज़ार में नई ऊंचाई पर ले गया. वजन में सिर्फ़ 52 ग्राम और 4 जीबी इन बिल्ट मेमोरी से लैस इस प्लेयर में माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी लगा है, जिसकी मदद से आप मेमोरी को 16 जीबी तक एक्सपैंड कर सकते हैं. इसमें लगी लिथियम पॉलीमर बैट्री 9.5 घंटे तक आराम से ऑडियो प्ले करने की सुविधा देती है. अगर वीडियो साथ में चलता रहे तो बैट्री 2.5 घंटे से भी ज़्यादा साथ देती है. यानी एक पूरी फिल्म बिना ब्रेक के देखी जा सकती है. 3.0 इंच कलर टीएफटी स्क्रीन में 400/240 पिक्सल रिजॉल्यूशन और वीडियो के लिए 720 पी लगा है, जो एकदम स्पष्ट तस्वीर दिखाता है. प्लेयर का सामने का हिस्सा ग्लॉसी-ब्लैक है, जबकि पीछे की ओर शानदार मैटलिक फिनिश है. 11 एमएम लंबा, स्लिम प्लेयर साइज और स्टाइल के मामले में किसी स्टाइलिश सेलफोन जैसा है. जेबमेट सिनेमा 3.0 प्लस ज़्यादातर ऑडियो-वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जैसे एमपीईजी-1 एवं 2, एमपीईजी 4 एक्सवीआईडी, डीआईवीएक्स, एच 263/264, डब्ल्यूएमवी 9/वीसी-1, एमवीबी, एमपी-3, डब्ल्यूएमए, ओजीजी, फलैक, एप, एएसी, एसी-3, एट्रा और डीटीएस. इसके साथ बेहतरीन ईयर फोन भी मिलेगा, जिसे आप स्टैंडर्ड 3.5 एमएम स्टीरियो जैक के ज़रिए प्लेयर से कनेक्ट कर सकते हैं. अपने साइज की कैटेगरी में यह प्लेयर एक और अनूठी सुविधा देता है. इसमें टीवी आउट फंक्शन है 720 वीडियो फॉर्मेट के साथ. इसे आप एलसीडी टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अन्य एसेसरीज में चार्जर, नेक बैंड और कैरीइंग पाउच शामिल हैं. जेबमेट सिनेमा 3.0 प्लस बाज़ार में 2900 रुपये में उपलब्ध है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारतीय टीम ने इंग्लैंड में छह पारियों में एक बार भी अपना स्कोर 300 के पार नहीं किया. इसके अलावा टीम की अधिकतर पारी 90 ओवर से कम में ही सिमट गई.

हार का ठीकरा किसके सिर

जूनियर से सीखें सीनियर

राजेश एस कुमार

अब टीम इंडिया इंग्लैंड के साथ अपने आख़िरी टेस्ट मैच का अंजाम चाहे जो भी देखे, लेकिन 3-0 की हार से हुआ आगाज़ यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय क्रिकेट टीम की न तो लाज बची है और न ताज. ताज तो उसने अपने शर्मनाक प्रर्दशन के साथ ही गंवा दिया था, लेकिन लाज गंवाई उसने हार का ठीकरा बेमतलब की बातों पर फोड़कर. सीधे-सीधे अपने अति आत्मविश्वास और लचर प्रदर्शन को हार का ज़िम्मेदार न मानते हुए धोनी वही पुराने डायलाग्स दोहराते नज़र आए. कभी कहते हैं कि किसी भी टीम के लिए हर मैच जीतना आसान नहीं है और कभी कहते हैं कि हम लोगों ने काफी समय से इतना क्रिकेट खेला है कि आराम करने का मौक़ा ही नहीं मिला. वहीं कुछ लोग टीम की हार का ठीकरा कोच फ्लेचर के सिर फोड़ रहे हैं. ताज्जुब की बात है कि जब टीम कोई बड़ा मैच जीतती है तो कोच को जीत का उतना हिस्सेदार नहीं माना जाता, जितना हार का. ख़ैर, अगर हम धोनी की इन बातों को तार्किक भी ठहराएं तो यह बात समझ के बाहर है कि टीम इंडिया इतने बड़े अंतर से कैसे हार गई. नंबर एक की सीट पर काबिज टीम का प्रदर्शन इतना भी नहीं गिरता कि वह अपना सूपड़ा इस तरीक़े से साफ कराए. आस्ट्रेलिया का ही उदाहरण ले लीजिए. वह विश्व विजेता रह चुकी है और हारती भी है, लेकिन उसकी हार में टीम का ज़बरदस्त संघर्ष दिखाई देता है.

ग़ौर करने वाली बात है कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड में छह पारियों में एक बार भी अपना स्कोर 300 के पार नहीं किया. इसके अलावा टीम की अधिकतर पारी 90 ओवर से कम में ही सिमट गई. मतलब टीम एक पूरे दिन भी मैदान पर टिकने में नाकाम रही. जिस टीम में सचिन, सहवाग, लक्ष्मण और द्रविड़ जैसे सूरमा हैं, वह अपनी बल्लेबाज़ी के लिए परेशान है. यह बात भी गले नहीं उतरती है. टेस्ट मैच में यह ज़रूरी होता है कि आप धैर्य के साथ पिच पर टिकें और कम से कम 90 ओवरों की बल्लेबाज़ी करें. तभी कोई टीम जीत की नींव रख पाती है. बर्मिंघम टेस्ट का ही उदाहरण लें तो एक ओर जहां भारत की पहली पारी 62.2 ओवरों तक टिकी, वहीं दूसरी पारी महज़ 55.3 ओवरों में ही सिमट गई. इसके विपरीत इंग्लैंड ने पहली ही पारी में 188 ओवर खेले. इंग्लैंड के हाथों तीसरे टेस्ट में एक पारी और 242 रनों की करारी हार के बाद भारत ने टेस्ट टीम में नंबर वन की हैसियत खो दी है. इसके साथ ही आईसीसी टेस्ट रैंकिंग शुरू होने के बाद 32 वर्षों में इंग्लैंड पहली बार टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचा है. लगभग 20 महीनों तक नंबर वन की रैंकिंग वाली महेंद्र सिंह धोनी की टीम एजबेस्टन टेस्ट में अपनी दूसरी पारी में भी 242 रनों पर धराशायी हो गई. जबकि खेल का एक दिन बाक़ी था. ज़रा सोचिए कि इंग्लैंड के एक खिलाड़ी कुक ने अकेले ही पूरी भारतीय टीम से ज़्यादा रन जोड़े. इस हार को हम हाल में किसी अन्य देश में भारत की सबसे बुरी हार के तौर पर शुमार कर सकते हैं. अगर क्रिकेट के इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो इससे पहले भारत को सबसे ख़राब हार का सामना वर्ष 1958 में करना पड़ा था, जब कोलकाता में वेस्टइंडीज़ ने उसे एक पारी और 336 रनों से हराया था, लेकिन उस दौरान भारतीय टीम क्रिकेट के खांचे में फिट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज के दौर में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने दुनिया भर में कामयाबी का झंडा लहरा दिया है तो ऐसे में इतनी अपमानजनक हार क्रिकेट प्रेमी पचा नहीं पा रहे हैं.

हाल में बीसीसीआई की कार्यकारी समिति की बैठक में फैसला किया गया कि निवर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर और भावी अध्यक्ष एन श्रीनिवासन हार के कारणों की जांच करेंगे.

मैं समझ सकता हूं कि बीसीसीआई टेस्ट मैचों की शर्मनाक हार के कारणों का पता लगाना चाहता है. यह स्वागत योग्य क़दम है. मुझे उम्मीद है कि यह एकतरफा जांच नहीं होगी
-वसीम अकरम

इस पर वसीम अकरम कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि बीसीसीआई टेस्ट मैचों की शर्मनाक हार के कारणों का पता लगाना चाहता है. यह स्वागत योग्य क़दम है. मुझे उम्मीद है कि यह एकतरफा जांच नहीं होगी. अकरम के मुताबिक़, मुझे एक बात ने चिंतित किया कि क्या भारत के पास तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण और सहवाग जैसे खिलाड़ियों की जगह भरने के लिए कुशल खिलाड़ी हैं? रैना, कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को अभी मीलों दूरी तय करनी है. चयनकर्ताओं के लिए यह बड़ा मुश्किल काम होगा. टीम में लगभग हर क्षेत्र में लापरवाही और कमज़ोरियां देखी गईं. चाहे वह बल्लेबाज़ी हो, क्षेत्ररक्षण, गेंदबाज़ी और मनोबल हो. इन सभी आयामों में टीम इंडिया पूरी तरह से चित्त रही. टीम की इस दुर्दशा के लिए कोच फ्लेचर भी कई मायनों में ज़िम्मेदार हैं. भारतीय क्रिकेट टीम में बतौर कोच जब गैरी क्रिस्टन शामिल थे, तब टीम अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही थी. जबसे कमान फ्लेचर ने संभाली है, टीम इंडिया का लचर प्रदर्शन दिखा है. यह संयोग भी हो सकता है, लेकिन कुछ तर्क ऐसे हैं, जिनके आधार पर फ्लेचर को टीम इंडिया की इस दुर्दशा का ज़िम्मेदार मान सकते हैं. मसलन उनका एक बयान, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया की हार के लिए पिच को ज़िम्मेदार ठहराया. ग़ौरतलब है कि लॉर्ड्स और नॉटिंघम के बाद एजबेस्टन में भी भारतीय बल्लेबाज़ों के फ्लॉप शो के बाद फ्लेचर ने कहा था कि इसके लिए इंग्लैंड की तेज पिचें ज़िम्मेदार हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इस बात से सभी वाक़िफ़ हैं कि फ्लेचर इंग्लैंड टीम के साथ आठ साल गुजार चुके हैं. अब किसी भी देश में इतना वक़्त बिताने के बाद अगर कोई कोच यह कहता है कि हम वहां की पिच और परिस्थितियों से वाक़िफ़ नहीं हैं तो थोड़ा ताज्जुब होता है. ऐसा नहीं था कि टीम ने ऐसी पिचें पहली बार देखी थीं. दक्षिण अफ्रीका में भी टीम को तेज उछाल वाली पिचें मिली थीं, लेकिन तब भारतीय टीम ने अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर सीरीज 1-1 से ड्रा खेली थी. हैरत की बात यह है कि ख़राब पिच की दुहाई वह कोच दे रहा है, जिसने आठ साल उसी देश में गुजारे हैं. फ्लेचर के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है. ऐसे में फ्लेचर का वहां की परिस्थितियों से वाक़िफ़ न होना शक पैदा करता है.

सच तो यह है कि टीम इंडिया पिछले कुछ समय से इस कदर जीतती आ रही है कि उसने कभी अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं समझी. क़िस्मत और कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन साथ रहा तो जीतते गए और अगर उन्होंने साथ छोड़ा तो चारों खाने चित्त. कोच के मसले को दरकिनार करके अब बात करते हैं उस जूनियर चैंपियन टीम की, जो किसी भी बहाने में यक़ीन नहीं करती है. वह तो सिर्फ़ प्रदर्शन करना जानती है. वहीं सीनियर टीम इंडिया कोच, पिच और थकान को अपनी हार में बतौर ढाल इस्तेमाल कर रही है. अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में शिखर धवन की अगुवाई में खेली इंडिया इमर्जिंग प्लेयर्स टीम ने टूर्नामेंट के दोनों फॉर्मेट टी-20 और तीन दिवसीय मैचों में जीत हासिल की. इस टीम ने सीनियर टीम इंडिया में लगातार फ्लॉप हो रहे खिलाड़ियों के लिए एक संकेत दिया है कि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है. अगर वह ऑस्ट्रेलिया जैसे कठिन वेन्यू पर टूर्नामेंट जीतने का माद्दा रख सकती है तो सीनियर टीम इंडिया को उससे सबक लेने की ज़रूरत है.

rajeshy@chauthiduniya.com

फिर डगमगाई साइना

भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फ़ाइनल में चीन की वांग शिन ने हार गईं. विश्व में छठे रैंक की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को विश्व की नंबर तीन खिलाड़ी चीन की वांग शिन ने 21-15, 21-10 से हराया. साइना विश्व चैंपियनशिप के पिछले दो संस्करणों में भी क्वार्टर फ़ाइनल में ही हारी थीं और इस बार भी वह अंतिम आठ से आगे नहीं बढ़ पाईं. मैच केपहले सेट में एक बार तो साइना 4-2 से आगे चल रही थीं, लेकिन वांग शिन ने बाद में अपना खेल सुधारा और स्कोर 9-9 पर बराबर हो गया. इसके बाद साइना की विरोधी अपने खेल को दूसरे ही स्तर पर ले गईं. साइना ने बेसलाइन पर बार-बार ग़लतियां कीं और वह वांग के तेज़ शॉट के सामने चूकती रहीं. दूसरे गेम में तो वांग शिन ने शुरू से ही साइना पर दबाव बनाए रखा और जल्दी ही 4-10 की लीड ले ली. इसके बाद साइना नेहवाल के कोच पुल्लैला गोपीचंद ने उनकी हौसला-अफज़ाई भी की, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच फ़र्क साफ़ नज़र आ रहा था. साइना इससे पहले वांग शिन से तीन बार हार चुकी हैं, लेकिन मई में सुदीरमान कप में उन्होंने इस चीनी खिलाड़ी को हराया था. साइना के अलावा मिश्रित युगल मुक़ाबलों में भारतीय जोड़ी ज्वाला गुटा और वी दिजु भी इंग्लैंड के जोकिम नीलसन और क्रिस्टीना पेडेरसन से तीसरे राउंड में हार गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

जोआ इतनी रोमांटिक क्यों हैं, यह अनुमान लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो प्यार में होता है, वही प्यार को समझ सकता है.

ईशा के बाद अहाना

बॉलीवुड में ऐसे स्टार भाई-बहनों की कमी नहीं है, जो अपने माता-पिता के दम पर इंडस्ट्री में आए हों. ऐसी ही एक स्टार हैं देओल कन्या ईशा, जो दर्शकों को पसंद नहीं आईं. अब इंडस्ट्री में देओल परिवार की दूसरी कन्या क़दम रखने को तैयार हो रही है. सुपर स्टार धर्मेंद्र और ड्रीमगर्ल हेमामालिनी की छोटी बेटी अहाना जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखेंगी. हेमा ने ख़ुद बताया कि उनकी छोटी बेटी अहाना एक्टिंग के लिए तैयार है. जैसे ही उसे कोई अच्छा प्रस्ताव मिलता है, वह उससे जुड़ने को इच्छुक है. 2002 में जब हेमा की बड़ी बेटी ईशा देओल ने बॉलीवुड में क़दम रखा था, तब लोगों को लगा था कि बहुत जल्द उनकी छोटी बेटी अहाना भी बॉलीवुड का रुख़ करेगी, लेकिन अहाना ने यह फ़ैसला लेने में 10 साल लगा दिए. हेमा ने कहा, अहाना की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह एक साथ कई काम करती है. वह फैशन डिज़ाइनर है, पटकथा लिखती है और अब एक्टिंग का विचार है. अहाना कहती हैं कि जब तक उन्हें कोई आकर्षक प्रस्ताव नहीं मिलेगा, तब तक वह फिल्मों में काम नहीं करेंगी. वह नियमित तौर पर बनने वाली फिल्मों में काम नहीं करना चाहतीं. अहाना वैसे तो निर्देशक बनना चाहती हैं, लेकिन घर के फिल्मी माहौल ने उन्हें अभिनय के लिए ज़रूरी नृत्य सीखने पर मजबूर कर दिया. वह इन दिनों अपनी मां और बहन की तरह भरत नाट्यम सीख रही हैं. बाक़ी सब तो ठीक है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि अहाना अपनी मां हेमा की तरह बुलंदियों पर पहुंचती हैं या बहन ईशा की तरह एक बार धूम मचाकर शांत हो जाती हैं.

नए क़िरदार में माही

देव डी की पारो यानी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल माही गिल ने करियर की शुरुआत में ही अपने इरादों से सबको परिचित करा दिया था कि चाहे जितनी भी कोशिश करनी पड़े, लेकिन उन्हें इस इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने हैं. अब उनका इरादा ग्लैमर से सरोकार रखते हुए ख़ुद को बेहतरीन एक्ट्रेस साबित करने का है. हालांकि इंडस्ट्री में आने से पहले माही की तमन्ना थी कि वह सिनेमा में माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की तरह चमकते-दमकते किरदार अदा करें, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद उनका इरादा बदल गया. चंडीगढ़ जैसे शहर में रहकर यश चोपड़ा और सुभाष घई की फिल्में देखते हुए माही सोचती थीं कि अगर वह कभी एक्टिंग करेंगी तो टॉप फाइव में रहेंगी. हिट फार्मूला फिल्में करेंगी, जिसमें ख़ूब नाच-गाना होगा. अब जब ख़ुद फिल्मों में आईं तो अलग ही रास्ता मिल गया. रिया एवं राइमा सेन, नंदिता दास, शबाना आजमी, कोंकणा सेन और कई अभिनेत्रियों ने माही के आइडिया के दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई. दरअसल माही ने ख़ुद को स्थापित करने के लिए तय किया है कि वह अब महिला प्रधान फिल्में करेंगी, ताकि पूरी फिल्म में आकर्षण का केंद्र बनी रहें. यही वजह है कि अब वह साहेब बीवी और गैंगस्टर में लीक से हटकर किरदार निभा रही हैं. साहेब बीवी और गैंगस्टर में वह एक ऐसी औरत का किरदार निभा रही हैं, जो संस्कारी है, लेकिन जब उसके साथ कोई जुल्म होता है तो वह चुप नहीं रहती और अपना विरोध ज़रूर दर्ज कराती है. फिल्म नॉट अ लव स्टोरी में भी उनका रोल काफी चुनौतीपूर्ण है. राम गोपाल वर्मा की यह फिल्म असल में नीरज ग्रोवर हत्याकांड से प्रेरित है. माही का एक और रूप दिखेगा तिग्मांशु धूलिया की फिल्म पान सिंह तोमर में. इसमें माही तीन बच्चों की मां का रोल निभा रही हैं. फिल्म में वह पान सिंह की बीवी बनी हैं, जो बिल्कुल गंवार है. इस फिल्म में उनके 18 से 37 साल तक के जीवन की कहानी है. इसमें वह काफी गुस्सैल मिजाज़ की महिला हैं. लोगों ने अब तक माही को सेक्सी और ब्यूटीफुल फिगर के तौर पर जाना है. देखना है कि उनका यह रंग लोगों को कितना पसंद आएगा.

पापा की बेटी जोआ

जोआ मोरानी के लिए फिल्में कोई नई बात नहीं हैं. तब भी, जबकि वह सिर्फ़ एक फिल्म ऑलवेज कभी कभी ही कर पाई हैं. दरअसल इंडस्ट्री के दूसरे स्टार किड्स की तरह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी फिल्मी है. उनके पिता करीम मोरानी फिल्म प्रोड्यूसर हैं और जोआ ने भी हल्ला बोल और ओम शांति ओम जैसी उम्दा फिल्मों के सेट्स पर बतौर असिस्टेंट काम किया है. हालांकि उन्हें कैमरे के पीछे काम करने का कोई शौक नहीं है, उन्हें तो ऑन स्क्रीन एक्टिंग करने में मज़ा आता है. एक और चीज है. उन्हें शौक है ढेर सारी नॉवेल्स पढ़ने का. जोआ काफी रोमांटिक हैं और दूसरी लड़कियों की तरह उन्हें भी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़कर और रॉम-कॉम फिल्में देखकर सपनों में खो जाने में खुशी मिलती है. उनकी प्रिय रोमांटिक फिल्मों और नॉवेल्स के अलावा पेब्लो नरूडा पोएट्री का कलेक्शन भी उनके पास है. जोआ इतनी रोमांटिक क्यों हैं, यह अनुमान लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो प्यार में होता है, वही प्यार को समझ सकता है. उनके दिल के बेहद क़रीब हैं उनके ब्वॉयफ्रेंड शामिक राजा. शामिक इंडो-कनाडाई मूल के व्यवसायी हैं और दुबई में उनका बंगला शाहरुख ख़ान के ठीक बगल में है. जोआ के दिल में प्यार न केवल लव रिलेशनशिप के लिए है, बल्कि परिवार को भी वह उतना ही प्यार करती हैं और जिम्मेदारी उठाती हैं. हाल में टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में करीम मोरानी पर लगे आरोपों का खंडन करने के लिए वह ख़ुद मीडिया के सामने आईं और अपने फिल्मी करियर की चिंता किए बग़ैर पिता की वकालत करती रहीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बिपाशा की परेशानी

बॉलीवुड की बिल्लो रानी बिपाशा बसु इन दिनों काफी परेशान हैं. वजह वही पुरानी यानी जॉन अब्राहम, जिनके ब्रेकअप की ख़बरें पुरानी होने का नाम नहीं ले रही हैं. बिपाशा इस बात से काफी नाराज़ और परेशान हैं. बिपाशा का कहना है कि लोग क्यों किसी को उसका गम भुलाने नहीं देते. जब दोनों यानी जॉन और बिपाशा ने अलग-अलग रहकर जीना सीख लिया है तो लोग उन्हें क्यों नहीं जीने दे रहे हैं. बिपाशा ने ट्विटर पर लिखा है कि लोगों को किसी के दर्द पर नमक छिड़कने में काफी मज़ा आता है. बिपाशा ने कहा कि लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें. बिप्स ने जॉन से प्रार्थना की कि वह उनके साथ बिताए पलों की बात सार्वजनिक न करें. ग़ौरतलब है कि अर्से तक बॉलीवुड के हॉट कपल कहे जाने वाले बिपाशा और जॉन का ब्रेकअप हो चुका है. यह रिश्ता क्यों टूटा, इस पर आज भी सस्पेंस बरक़रार है, लेकिन लोग चाहते हैं कि दोनों सितारे फिर से एक हो जाएं. इसलिए वे अपनी प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर दे रहे हैं, जो बिप्स को ख़ुश करने के बजाय दु:खी कर रही हैं.

फिल्म प्रीव्यू

बॉडी गार्ड

हिंदी सिनेमा जगत को फिल्म दबंग और रेडी जैसी सुपर हिट फिल्म देने के बाद अभिनेता सलमान ख़ान अब तैयार हैं फिल्म बॉडी गार्ड के साथ. निर्माता अतुल अग्निहोत्री की इस फिल्म में सलमान के साथ करीना कपूर मुख्य भूमिका में नज़र आने वाली हैं. फिल्म में सलमान की खास दोस्त कैटरीना कैफ का भी आइटम नंबर होगा. सलमान करीना के बॉडी गार्ड के तौर पर नज़र आएंगे. फिल्म में सलमान ख़ान एकदम माचो लुक में दिखेंगे. सिर से पैर तक सूटेड-बूटेड, आंखों पर ब्लैक गॉग यानी दबंग के चुलबुल पांडे के कॉप लुक से एकदम अलग. हार्ड एंड हैंडसम. निर्देशक सिद्दीकी के अनुसार, सलमान का लुक एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर भी सलमान अपने लुक से पूरी तरह ख़ुश नहीं थे.

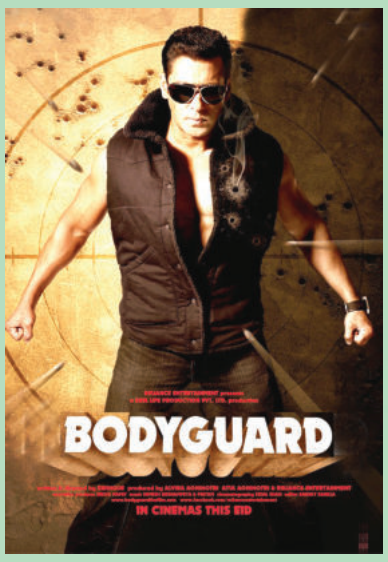

उन्हें लग रहा था कि उनके लुक में कुछ न कुछ मिसिंग है और वह था सलमान का ब्रेसलेट. फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग हो चुकी थी, फिर भी सलमान ने ब्रेसलेट की स्पेशल एंट्री करा दी. फिल्म बॉडी गार्ड कई कारणों से सलमान के दिल के काफी क़रीब है. सलमान इस फिल्म के ज़रिए अपनी बहन अलवीरा और बहनोई अतुल अग्निहोत्री को प्रोड्यूसर के तौर पर स्थापित करने में सहायता कर रहे हैं. फिल्म को समय पर पूरा कराने के लिए सलमान ने 14 से 16 घंटे काम किया. शूटिंग के दौरान वह फिल्मसिटी में ही सेट के एक हिस्से में बने अस्थाई घर में रहे, ताकि रोज बांद्रा स्थित निवास से स्टूडियो आने में समय बर्बाद न हो. गणेश आचार्य ने इस फिल्म के सबसे हिट गाने की कोरियोग्राफी की है. सलमान ख़ान ने अपने निजी बॉडीगार्ड शेरा की सुरक्षा एजेंसी की ही वर्दी फिल्म में अपने लिए चुनी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 29 अगस्त-04 सितंबर 2011

www.chauthiduniya.com

सरकारी गोली के निशाने पर किसान

आलोक मिश्रा

अहिंसा का मंत्र जग को देने वाले देश में हिंसा का तांडव, वह भी सरकारी आदेश में, यह विरोधाभास ही भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है. यहां लोक की आवाज़ दबाने के लिए तंत्र का इस्तेमाल सत्ता प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है. अपने हक़ के लिए अहिंसक आंदोलन करने पर भी यहां लाठियां भांजी जाती हैं. गोलियां बरसाई जाती हैं. लोक को मसल कर सत्ताधीश अपनी मोटी चमड़ी को बचाते नज़र आते हैं. खेतों के लिए पानी मांगो तो गोली, अपने हक़ लिए आंदोलन करो तो लाठी-गोली, सत्ताधीशों के कदाचार के ख़िलाफ़ अहिंसक आंदोलन करो तो भी गोली मिलती है. ऐसा लगता है कि किसी समस्या से निपटने का उपाय सोचने के मामले में सत्ताधीश और अफ़सरशाह दिवालिया हो गए हैं. इसीलिए वे लोक की आवाज़, मांग, बात सुनने की बजाय उसे दबाने के लिए लाठी-गोलियां चलाना ही अपना कर्तव्य समझने लगे हैं. इससे लगता है कि यह बापू का देश नहीं है. बापू ने तो अपने अहिंसक आंदोलनों से अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद कराया था, परंतु आज के सत्ताधीशों की लोक आंदोलनों को लाठी-गोली से कुचलने की प्रवृत्ति को देख कर ऐसा लगता है कि वे अंग्रेजों से अधिक अपने को बर्बर साबित करना चाहते हैं. भारतीय लोकतंत्र का यह विरोधाभास ही सवाल पूछता है कि आख़िर यह कैसा लोक का तंत्र है, जहां लोक की कोई सुनवाई नहीं होती है. दूसरी ओर सत्ताधीश जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज़ पर लोक को हांकने का प्रयास करता है. मुंबई-पुणे हाइवे पर पवना जलवाहिनी परियोजना का विरोध कर अपने हक़ का पानी मांगने वाले किसानों पर हुई गोलीबारी सत्ताधीशों को मिले अंग्रेजी सत्ता के संस्कारों का नतीजा है. पहले गोली बरसाई, फिर मृतकों, घायलों की सुध लेने की बजाय अपनी मोटी खाल बचाने की निर्लज्ज कोशिश करते दिखाई दिए. मावल में किसानों का राज्य के सत्ताधीशों से न्याय मिलने का सपना टूट गया. पवना जलवाहिनी परियोजना का विरोध किसान आज से तो कर नहीं रहे थे. इसका विरोध मावल तहसील के किसान वर्ष 2008 से ही कर रहे थे, लेकिन गुज़रे तीन सालों में कभी हमारे मंत्रियों को इतना समय नहीं मिला कि वे इन किसानों की मांग व बात को धैर्य से सुन सकें. इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या हैं? किसानों की आपत्तियां क्या हैं? क्यों वे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं? इन सब पर कभी विचार करने का समय क्यों नहीं निकाला गया? असल बात यह है कि हमारे यहां परियोजनाएं जनता से पूछ कर बनाई नहीं जाती हैं. सरकार अपनी मर्ज़ी व सुविधा से परियोजनाएं बनाती है और उसे जनता पर थोप देती है. इसके बाद जब जनता उस परियोजना से पैदा होने वाली परेशानियों से शासन-प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास करती है तो संबधित अधिकारियों और मंत्रियों के पास वक़्त ही नहीं रहता है. जब जनता का धैर्य टूट जाता है तो उसे मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ता है. जब वह अपने हक़ की बात को ज़ोरशोर से उठाती है तो सत्ताधीशों को अपनी कुर्सी हिलती दिखाई देती है और दिमाग़ से दिवालिया हमारे मंत्री व अफ़सर उसे दबाने में जुट जाते हैं, मावल के किसानों के साथ यही हुआ. यदि समय रहते हमारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पाटबंधारे मंत्री, गृहमंत्री किसानों की बात सुनते तो उन्हें सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. जब नेताओं का संयम थोड़ी देर में जवाब दे जाता है तो मावल के किसान तीन साल से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे थे. जिस तरह से मावल के किसानों पर गोली बरसाई गई वह तो सरासर किसानों का एनकाउंटर करना ही है. इसलिए विपक्ष की इस मांग में दम है कि दोषियों के ख़िलाफ़ हत्या का मामला दर्ज किया जाए.

यह तथ्य भी ग़ौर करने लायक़ है कि अपने हक़ के लिए संघर्ष करने वाले किसानों, आदिवासियों, ग्रामवासियों या उनके लिए संघर्ष करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के आंदोलनों पर गोलीबारी की घटनाएं अधिक होती हैं. किसी सत्तारूढ़ मंत्री या नेताओं के समर्थकों द्वारा आंदोलन करने पर कभी पुलिस द्वारा गोली बारी नहीं होती है. चाहे वह जितने पत्थर पुलिस पर बरसाये या सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुंचाएं. पुलिस गोलीबारी का निशाना कभी कोई उद्योगपति नहीं होता है, इसके शिकार सिर्फ़ बनते हैं तो किसान, आदिवासी, ग़रीब और उनके समर्थक सामाजिक कार्यकर्ता, क्यों? महाराष्ट्र हो या देश का कोई अन्य राज्य सभी जगह पुलिस गोलीबारी का निशाना आम आदमी बनता है. मावल-जैतापुर हो या भट्टा परसौल या नंदीग्राम के ग्रामीण का अपनी ज़मीन बचाने के लिए किया गया आंदोलन, सभी जगह यही हाल है. महाराष्ट्र में पानी के लिए चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है. किसानों को खेतों के लिए पानी चाहिए, परंतु सरकार की जल नीति दिखावे को तो किसानों के हित में है, पर उसका फ़ायदा उठाते हैं उद्योगपति और पूंजीपति. राज्य में जितनी परियोजनाएं जल प्रबंधन के उद्देश्य से बनी या बनाई जा रही हैं, उनको लेकर किसानों में हमेशा असंतोष देखा गया है. मामला चाहे 25 वर्षों से निर्माणाधीन राष्ट्रीय प्रकल्प गोसीखुर्द का हो या गोंदिया का बाबनथड़ी, यवतमाल ज़िले का बेंबला प्रकल्प, अरुणावती प्रकल्प, पूर्णा प्रकल्प, चारगड़ प्रकल्प, बुलढाणा ज़िले का जिगांव प्रकल्प, पेनटाकली प्रकल्प, मन प्रकल्य अथवा राज्य के किसी और हिस्से का प्रकल्प हो किसानों को न आसानी से पानी मिला और न इन परियोजनाओं से उजड़े लोगों का उचित तरीक़े से पुनर्वास किया गया है. कई तो आज तक मुआवज़े के लिए तरस रहे हैं. पहले लोग संगठित होकर आंदोलन नहीं करते थे इसलिए लोगों पर गोलीबारी की घटनाएं कम होती थीं. समय बदलने के साथ-साथ अब उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागी है. उनमें अपनी ज़रूरतों के प्रति जागरूकता आई है और जैसे-जैसे समाज में जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे वह हर उस मुद्दे पर आंदोलित हो उठता है, जहां उसे लगता है कि उसके हक़ पर डाका डाला जा रहा है. फिर पानी तो जीवन का पर्याय ही है. किसान के लिए जीवन-मरण का तत्व है. पानी बिना खेतों में बीज बोए नहीं जा सकते और बोए बीए उगाये नहीं जा सकते हैं. इतनी सी बात हमारे नेताओं को समझ में नहीं आती. अब सवाल यह उठता है कि मावल के किसान पवना जनवाहिनी परियोजना का विरोध क्यों कर रहे थे? मावल के किसानों का कहना है कि हमारा पिंपरी-चिंचवड वासियों को पानी दिए जाने पर कोई विरोध नहीं था. हम यह चाहते थे कि हमारे खेतों को मिलने वाला पानी बंद नहीं होना चाहिए. पहले खुले रूप से पवना बांध का पानी पिंपरी-चिंचवड को सप्लाई किया जाता था, जिससे हमारे खेतों के आसपास पानी का लेवल अच्छा बना रहता था. लेकिन जब से पिंपरी-चिंचवड के लिए जलवाहिनी का काम शुरू हुआ है तब आगे हमारे खेतों का जलस्तर काफ़ी नीचे जाने का ख़तरा बढ़ जाएगा. किसानों का यह भी कहना था कि कोई बांध या सिंचाई परियोजनाएं बनती तो खेती की हमारी ज़मीन लेकर ही हैं, फिर हमें ही पानी के लिए क्यों तरसाया जाता है? किसानों के इस सवाल का जवाब देना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होगा. विशेषकर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए, क्योंकि वे इस ज़िले के पालकमंत्री हैं. पालकमंत्री होने के बावजूद उन्होंने कभी मावलवासियों के दुख-दर्द को सुनने-समझने का वक़्त नहीं निकाला.

मावल में युवराज

गोलीकांड के मातम में डूबे मावल व उसके आस-पास के गांव में अचानक देश की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के पहुंचने से हलचल हुई. राहुल ने मावल के बाद जो पहली बात कही वह थी कि पुलिस फायरिंग में हुई किसानों की मौत से ऐसा लगता है कि क़ानून को तोड़ा गया है. वीडियो फुटेज में पुलिस की बेरहमी साफ़ दिखाई देती है. उन्होंने मावल गोलीकांड में मारे गए कृषक मोरेश्वर साठे, श्यामराव तुपे और कांताबाई ठाकरे के परिजनों से मुलाक़ात कर उनकी बात ग़ौर से सुनी और चलते बने. मृतकों के परिजनों ने बताया कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया. पुलिस ने बिना चेतावनी के गोली कैसे चलाई. मोरेश्वर साठे की बेटी ने बताया कि उसके पिता को पुलिस ने पकड़ने के बाद गोली मारी. तलेगांव अस्पताल में भर्ती घायलों को आस थी कि राहुल गांधी उनसे मिलने भी आएंगे, पर उन्होंने वहां जाकर घायलों से मिलना मुनासिब नहीं समझा. पत्रकारों से बात करना उचित नहीं समझा. किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया. न्याय की गुहार लगाते लोगों को देश के भावी प्रधानमंत्री के आने से लगा था कि न्याय मिलेगा. मगर यहां राज्य सरकार में ही अपनी खाल बचाने के लिए आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं.

उद्धव ठाकरे अक्सर आरोप लगाते रहते हैं कि राहुल भट्टा-परसौल जाते हैं, पर महाराष्ट्र के किसानों की सुध उन्हें कभी नहीं आती है. यह दौरा उसी का जवाब है. लेकिन राहुल की इस यात्रा से राष्ट्रवादी कांग्रेस ख़ुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गोली चलाने में क़ानून की अनदेखी की गई है और इसकी जांच होनी चाहिए. राज्य के गृहमंत्री आर.आर. पाटिल न्यायिक जांच कराने की घोषणा कर चुके हैं और कांग्रेस भी जांच कराने के पक्ष में हैं, परंतु राज्य के उपमुख्यमंत्री व राकांपा नेता अजीत पवार नहीं चाहते कि मामले की न्यायिक जांच हो. ऊपर से अब राहुल गांधी का बयान कि इस गोलीकांड की जांच हो, से राकांपा दबाव में आ गई. बहरहाल राहुल का गुपचुप मावल दौरा संपन्न हो गया है. पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वह क्या प्रयास करते हैं इस पर सबकी नज़र लगी हुई है.

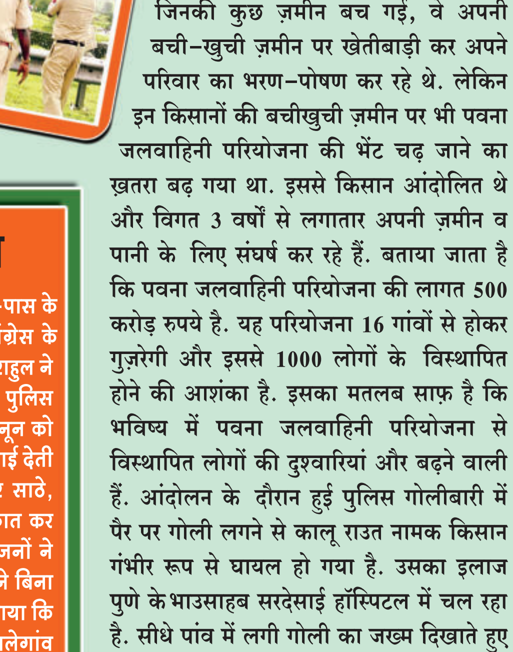

इसकी वजह राजनीतिक बताई जाती है. बताया जाता है कि मावल निर्वाचन क्षेत्र 15 वर्ष से भाजपा विधायक संजय भेंगड़े के क़ब्ज़े में है. यह बात उपमुख्यमंत्री को परेशान करती रहती है और वे किसी भी सूरत में मावल से भाजपा का वर्चस्व ख़त्म करना चाहते हैं. यही कारण है कि वे मावल के किसानों की बात सुनने को कभी तैयार नहीं हुए. यहां के लोगों का यह भी कहना है कि भले ही पिंपरी-चिंचवड के निवासियों को पेयजल आपूर्ति के नाम पर पवना जलवाहिनी परियोजना बनाई गई हो, पर यह परियोजना यहां के इंडस्ट्रियल एरिया को लाभ पहुंचाने के लिहाज़ से बनाई गई है. इसकी वजह यह है कि यहां की इंडस्ट्री से राकांपा को बड़ी मात्रा में फंड मिलता है.

पवना बांध और विस्थापितों का दर्द : मावल के निकट पवना बांध 35 वर्ष पहले 1972 में बना था. उस समय 860 किसान परिवार विस्थापित हुए थे. इन विस्थापित किसानों को अपनी ज़मीन देने पर तत्कालीन राज्य सरकार ने एक-एक एकड़ कृषि योग्य ज़मीन देने का वादा किया था, लेकिन इन परिवारों को अपनी ज़मीन के बदले कुछ नहीं मिला. जिनकी ज़मीन पवना बांध में गई उनमें से कई रोज़गार की तलाश में गांव छोड़ मुंबई-पुणे जैसे शहरों की ओर कूच कर गए. जिनकी कुछ ज़मीन बच गई, वे अपनी बची-खुची ज़मीन पर खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे. लेकिन इन किसानों की बचीखुची ज़मीन पर भी पवना जलवाहिनी परियोजना की भेंट चढ़ जाने का ख़तरा बढ़ गया था. इससे किसान आंदोलित थे और विगत 3 वर्षों से लगातार अपनी ज़मीन व पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बताया जाता है कि पवना जलवाहिनी परियोजना की लागत 500 करोड़ रुपये है. यह परियोजना 16 गांवों से होकर गुज़रेगी और इससे 1000 लोगों के विस्थापित होने की आशंका है. इसका मतलब साफ़ है कि भविष्य में पवना जलवाहिनी परियोजना से विस्थापित लोगों की दुश्वारियां और बढ़ने वाली हैं. आंदोलन के दौरान हुई पुलिस गोलीबारी में पैर पर गोली लगने से कालू राउत नामक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसका इलाज पुणे के भाउसाहब सरदेसाई हॉस्पिटल में चल रहा है. सीधे पांव में लगी गोली का जख्म दिखाते हुए उसने बताया कि उसके गांव की 27 कुंडा ज़मीन पवना जलवाहिनी परियोजना में जाने वाली है. पवना डैम बनने के दौरान पहले ही पूरी खेती डूब चुकी है. उसके बदले अब तक कुछ नहीं मिला है. और अब बची हुई ज़मीन पवना जलवाहिनी परियोजना में जा रही है. इससे मावल सहित आस पास के गांव के सारे किसान परेशान थे. इसीलिए सभी गांव के किसान आंदोलन में शामिल हुए. आख़िर ऐसे भी मरना और ज़मीन छिन जाने पर भी मरना ही है.

पवना डैम से विस्थापित किसानों को मुआवज़ा न मिलने और पुनर्वास न होने पर सरकार का कहना है कि 1972 में जब यह बांध बना तो उस समय मुआवज़ा व पुनर्वास संबंधी कोई क़ानून नहीं था. लेकिन अब सरकार इस मामले पर ग़ौर कर रही है. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर निकालने के लिए सहमत हो गए हैं यानी पहले गोली बरसा कर मौत दी, जख्म दिए और उसके बाद मरहम लगाने का प्रयास सरकार कर रही है.

गोलीबारी का सच : मावल गांव के आंदोलनकारियों पर गोलीबारी करने का आदेश किसके कहने पर दिया गया? यह सवाल यक्ष प्रश्न बनकर राज्य की जनता के सामने खड़ा है. इसकी वजह यह है कि पहले गृहमंत्री ने गोलीबारी की घटना में पुलिस का बचाव करते हुए विधानसभा में बयान दिया कि आंदोलन स्थल पर एक सफ़ेद कार से गोली चलाई गई. लेकिन जैसे-जैसे मीडिया व स्रोतों से तथ्य सामने आ रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं. वीडियो फुटेज व फोटो में पुलिस कर्मियों द्वारा निशाना साध कर गोली चलाने की बात उजागर होने पर सरकार ने अपनी खाल बचाने के उद्देश्य से दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया. मगर विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि पुलिस गोलीबारी होने के पहले पुणे के पुलिस अधीक्षक संदीप कर्णिक ने मुंबई किसी मंत्री से बात की थी. उसके बाद एस.पी. कर्णिक ने ही आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया. इसके लिए उन्होंने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति भी नहीं ली. दूसरी ओर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मोरेश्वर साठे नामक किसान को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, बाद में उसे गोली मार दी. इतना ही नहीं इस गोलीकांड में मारी गई महिला कांताबाई ठाकरे के बेटे नितिन का कहना है कि पुलिस अधीक्षक कर्णिक ने ही उसके सामने गोली चलाने का आदेश दिया और उसकी मां को मार डाला. यह भी कहा जा रहा है कि सरकार पुलिस निरीक्षक और उपनिरीक्षक को निलंबित करके पुलिस अधीक्षक संदीप कणिक को बचा रही है. इसकी वजह यह है कि पुलिस अधीक्षक कर्णिक राज्य के पुलिस महासंचालक के दामाद हैं. अब इस गोलीबारी का सच क्या है? जनता इसकी हक़ीक़त जानना चाहती है और सरकार का कर्तव्य बनता है कि कांड की हक़ीक़त उजागर करे.

उपमुख्यमंत्री न्यायिक जांच नहीं चाहते : मावल गोलीकांड की जांच पर भी राकांपा में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. जहां गृहमंत्री आर. आर. पाटिल विधानसभा में मावल मामले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा कर चुके हैं, वहीं उपमुख्यमंत्री अजीत पवार नहीं चाहते की मामले की न्यायिक जांच हो. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि न्यायिक जांच होती है तो अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पुणे ज़िले में उनके इशारे के बिना कोई भी अधिकारी स्वयं गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता है. अब अजीत पवार नहीं चाहते कि इस मामले में उनका नाम आए. इस संबंध में यह भी पता चला है कि उन्होंने अपना नाम मावल कांड से न जोड़े जाने का कुछ विपक्षी नेताओं को फोन कर मनाने की कोशिश भी की, पर बात बनी नहीं. इसलिए अब उन्होंने विरोधी दल के नेताओं पर पलटवार करना शुरू कर दिया है.

feedback@chauthiduniya.com

नाबार्ड ने किसानों के 3000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित ऋण पर कोई निर्णय नहीं लिया है. इससे राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक ने भी किसानों को ऋण वितरण पर रोक लगा रखी है.

राज्य विधानसभा में लोकलेखा समिति की रिपोर्ट पेश की गई तब पता चला कि राज्य में कारोबार कर रहीं छह बड़ी कंपनियों ने करोड़ों का गोलमाल करके सरकारी ख़ज़ाने को अरबों रुपये का चूना लगाया है.

महाराष्ट्र हलचल

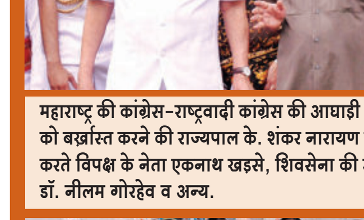

महाराष्ट्र की कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस की आघाड़ी सरकार को बर्ख़ास्त करने की राज्यपाल के. शंकर नारायण से मांग करते विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से, शिवसेना की उपनेता डॉ. नीलम गोरहेव व अन्य.

भाजपा नेता व सांसद गोपीनाथ मुंडे मावल का दौरा कर पवना बांध के पानी की मांग कर रहे किसानो पर हुई गोलीबारी में मृत श्यामराव तुपे के परिजनों व रिश्तेदारों से बात करते हुए.

स्वतंत्रता दिवस की 64वीं वर्षगांठ पर महाराष्ट्र विधानसभा मंत्रालय में ध्वजारोहण करने के पश्चात संबोधित करते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उनके साथ दिखाई दे रहे हैं मुख्यसचिव रत्नाकर गायकवाड़, पुलिस महासंचालक अजीत पारसनीस.

उद्योग मंत्री नारायण राणे से महाराष्ट्र विधान भवन के गलियारों में चर्चा करते विपक्षी दल के विधायक.

अन्ना हज़ारे द्वारा भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे अभियान के समर्थन में सुबह निकाली जानेवाली प्रभातफेरी में अन्ना हज़ारे, भारत माता, महात्मा गांधी का रूप धर कर शामिल बुज़ुर्ग और बच्चे सहित जनसमुदाय.

युवक कांग्रेस के चुनाव के लिए नागपुर स्थित देवड़िया भवन में नामांकन जमा करते युवा उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ.

स्वतंत्रता दिवस के जश्न पर तिरंगा लेकर सड़कों पर भ्रमण करते नागपुर के युवा.

बच्चों की जान से खिलवाड़

सोनू सावजी

मुख्याध्यापक, शिक्षक और अभिभावक परेशान हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ज़रा भी परेशान नहीं हैं. बच्चों की जान जाती है तो जाए. ये तो बस अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं जब चाहे तब काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ऐसा ही रवैया है अकोला ज़िला परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों का. जर्जर हो चुके स्कूलों की मरम्मत के कार्य के लिए अनुरोध पिछले तीन वर्ष से किए जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. दूसरी ओर बच्चों की जान को लेकर चिंतित अभिभावकों ने उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया है. इसके बाद भी ज़िला परिषद प्रशासन की आंख नहीं खुली है. लोग पूछ रहे हैं कि आख़िर ज़िला परिषद के अधिकारी किसके लिए काम करते हैं? जनता उनकी नौकर है या वे जनता के नौकर हैं?

दरअसल आकोट तालुका (तहसील) के नांदखेड गांव में स्थित ज़िला परिषद स्कूल की पहली कक्षा का कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. इस कमरे के कभी भी धराशायी होने की आशंका बनी रहती है. इसके चलते कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिससे वहां पढ़ने आने वाले बच्चों की जान को जोखिम हो सकता है. इस बात को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय शिक्षा समिति व मुख्याध्यापकों ने बार-बार ज़िला परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर और फोटो निकलवा कर स्थिति से अवगत कराया. इसके बावजूद उनके कानों में जूं तक न रेंगी. इससे आक्रोशित गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का निर्णय लिया है. ग्रामवासियों का कहना है कि नांदखेड के ज़िला परिषद स्कूल में

कक्षा 1 से 7 तक के बच्चे पढ़ने आते हैं. स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए पक्के कमरे हैं. मात्र पहली कक्षा का कमरा पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है. इसे हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है. इसकी वजह है क्षतिग्रस्त कमरा और ऊपर से बारिश का मौसम. यदि पढ़ाई के दौरान कमरा धराशायी हो गया तो छोटे-छोटे बच्चों की जान आफ़त में फंस जाएगी. ऐसी स्थिति में वहां आने वाले बच्चों की जान बचाने की गारंटी कौन देगा? उन्होंने बताया कि स्कूल के मुख्याध्यापक व स्थानीय शिक्षा समिति के सदस्य पिछले तीन वर्ष से ज़िला परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिख-लिखकर गांव वालों की चिंता से अवगत करा रहे हैं और नया कमरा बनाने की गुहार लगा रहे हैं. मगर उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है. इस पर गांव के कुछ लोगों ने ज़िला परिषद के अधिकारियों को स्कूल में बच्चों को न भेजने की चेतावनी दी है. इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई. गत 10 अगस्त से गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है. इस तरह ज़िला परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही से बच्चों की पढ़ाई का नुक़सान हो रहा है.

इस संबंध में जब गटशिक्षा अधिकारी वानखड़े से पूछा गया तो उनका कहना था कि 16 जुलाई को क्षतिग्रस्त कमरे को बनाने का प्रस्ताव मंज़ूर कर लिया गया है. इसकी जानकारी सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग को दे दी गई है. अब उनका इंजीनियर क्षतिग्रस्त कमरे का निरीक्षण कर मूल्यांकन करके प्रस्ताव अकोला के शिक्षाधिकारी को भेजेगा. इसका मतलब यह है कि प्रशासनिक मकड़जाल में कमरे का निर्माण कार्य उलझकर रह गया है. प्रशासनिक आवक-जावक का जब तक चक्कर ख़त्म नहीं होता है, तब तक यह मामला लटका ही रहेगा. तब तक पालकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का आह्वान गट शिक्षा अधिकारी ने किया है. मगर यहां सवाल यह उठता है कि इस बीच यदि कमरा धराशायी हो गया और किसी की जान चली गई तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा?

feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

कब तक आबा...

महाराष्ट्र का गृह विभाग कौन चला रहा है, गृहमंत्री या कोई और? जब भी कोई बड़ी वारदात राज्य में होती है तो हमारे प्यारे गृहमंत्री को कुछ पता ही नहीं रहता है. ये अक्सर अपने विभाग के मातहत आने वाले पुलिस प्रशासन का बचाव करते नज़र आते हैं. [illegible]

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

दादा ने विदर्भ को ठेंगा दिखाया

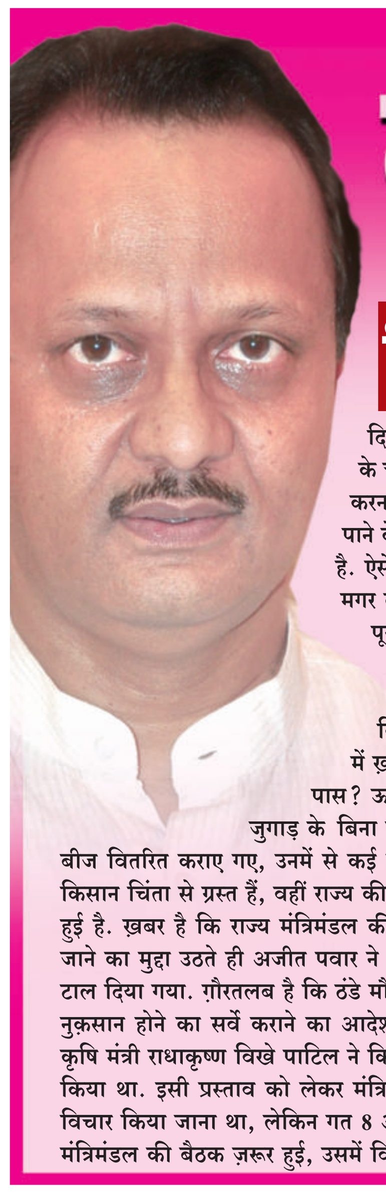

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विदर्भ के किसानों को आर्थिक मदद दिए जाने का मुद्दा उठते ही अजीत पवार ने इसका कड़ा विरोध किया और मामला आगे के लिए टाल दिया गया. ग़ौरतलब है कि ठंडे मौसम की वजह से विदर्भ के कई ज़िलों में फ़सलों को नुकसान होने का सर्वे कराने का आदेश तीन पालक मंत्रियों ने दिया था.

विदर्भ में मानसूनी बारिश की असामनता के चलते कहीं किसान ख़रीफ़ फ़सल के प्रति आशान्वित हैं तो कहीं कम बरसात के कारण उनकी पेशानी पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं. कई जगह तो बारिश की अनिश्चितता के चलते किसानों को दोबारा रोपाई-बोवाई का काम करना पड़ रहा है. इसके साथ ही समय पर क़र्ज़ न मिल पाने के कारण उनकी चिंताओं में और इज़ाफ़ा होना लाज़िमी है. ऐसे में किसानों को राज्य सरकार से मदद की आस है. मगर लगता नहीं कि सरकार उनकी इस आस को समय पर पूरा कर पाएगी. दूसरी ओर नाबार्ड ने किसानों के 3000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित ऋण पर कोई निर्णय नहीं लिया है. इससे राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक ने भी किसानों को ऋण वितरण पर रोक लगा रखी है. ऐसे में ख़रीफ़ फ़सल के इस मौसम में किसान जाएं तो किसके पास? ऊपर से बीज-खाद की समस्या सामने खड़ी है. इनके जुगाड़ के बिना खेती की नहीं जा सकती है. साथ ही शासन द्वारा जो बीज वितरित कराए गए, उनमें से कई बेहद घटिया दर्जे के निकले हैं. इन स्थितियों में जहां किसान चिंता से ग्रस्त हैं, वहीं राज्य की लोकशाही आघाड़ी सरकार राजनीति करने में उलझी हुई है. ख़बर है कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विदर्भ के किसानों को आर्थिक मदद दिए जाने का मुद्दा उठते ही अजीत पवार ने इसका कड़ा विरोध किया और मामला आगे के लिए टाल दिया गया. ग़ौरतलब है कि ठंडे मौसम की वजह से विदर्भ के कई ज़िलों में फ़सलों को नुक़सान होने का सर्वे कराने का आदेश तीन पालक मंत्रियों ने दिया था. इसलिए राज्य के कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने किसानों की मदद के लिए 132 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया था. इसी प्रस्ताव को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को मदद किए जाने पर विचार किया जाना था, लेकिन गत 8 अगस्त को विधानसभा का कामकाज निपटने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक ज़रूर हुई, उसमें विदर्भ के किसानों को आर्थिक मदद दिए जाने पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका. विदर्भ के किसानों की मदद का विषय बैठक के एजेंडे में शामिल था, परंतु जैसे ही कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने किसानों को मदद करने का प्रस्ताव रखा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का पारा चढ़ गया. ध्यान रखने वाली बात यह है कि अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय भी है. उनकी सहमति के बिना किसानों की मदद के लिए राशि आवंटित नहीं की जा सकती है. बैठक में कांग्रेस के मंत्रियों ने जहां विदर्भ के किसानों को आर्थिक मदद देने की पुरज़ोर सिफ़ारिश की. उन्होंने यह भी तथ्य रखा कि विदर्भ के तीन-तीन पालकमंत्रियों ने ठंड के मौसम में फ़सलों को हुए नुक़सान का सर्वे करने का आदेश दिया था. सर्वे से किसानों को भारी नुक़सान होने की बात सामने आई है. इसलिए सरकार द्वारा विदर्भ के किसानों को आर्थिक मदद दिया जाना अतिआवश्यक है. इस पर उपमुख्यमंत्री ने विदर्भ के किसानों को आर्थिक मदद दिए जाने का सख्त विरोध किया. उन्होंने सवाल किया कि पालकमंत्रियों को इस तरह के आदेश देने की ज़रूरत क्या थी?

सूत्रों के अनुसार अजीत पवार के आक्रामक अंदाज़ को देखने के बाद भी कृषि मंत्री विखे पाटिल ने बैठक में किसानों को आर्थिक मदद दिए जाने को जायज़ ठहराते हुए कहा कि मैंने ख़ुद अपनी आंखों से विदर्भ के किसानों की दुर्दशा व परेशानी देखी है. पहले ही वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है. मौसम की मार पड़ने के साथ ही उनकी हालत बद से बदतर हो गई है. इसी को मद्देनज़र रखते हुए कृषि मंत्रालय ने विदर्भ के किसानों की आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से 132 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है. इस पर वित्त मंत्रालय की सहमति ज़रूरी है. इसके बावजूद उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया.

उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए अंततः आर.आर. पाटिल ने सुझाव दिया कि विदर्भ के किसानों को आर्थिक मदद दिए जाने का फ़ैसला अब मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पर छोड़ दिया जाना चाहिए. इस तरह विदर्भ के किसानों को मदद पहुंचाने में राजनीति आड़े आ गई. मामला आगे के लिए टाल दिया गया. किसानों को सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद की आस अधर में लटक गई. यह भी बता दें कि मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में विदर्भ के मंत्रियों ने किसानों को आर्थिक मदद की मांग आक्रामक तरीक़े से की थी. तब नितिन राऊत, शिवाजीराव मोघे और मनोहर नाईक ने ज़ोरशोर से यह मुद्दा उठाया था. उस बैठक में अजीत पवार नहीं थे. मगर 8 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में विदर्भ के मंत्रियों के आक्रामक तेवर ग़ायब थे. मनोहर नाईक और नितिन राऊत, शिवाजीराव मोघे शांत ही बैठे रहे. ऐसा लगता है कि राऊत 250 करोड़ के घपले, शिवाजीराव मोघे का भ्रष्टाचार में नाम आने के बाद सहम से गए हैं और मनोहर नाईक को हाईकमान का डर. राष्ट्रवादी के दादा, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के सामने पता नहीं किन वजहों से तीनों चुप रहे. अन्य कांग्रेसी मंत्रियों ने आक्रामक रुख़ अपनाया ज़रूर, पर दादा के सामने वे भी फीके पड़ गए.

इससे यह तो साफ़ हो गया कि विदर्भ के किसानों को आर्थिक मदद दिए जाने को लेकर सरकार कितनी संवेदशील है. विदर्भ में बदहाल किसानों को आज जब सबसे अधिक आर्थिक मदद की ज़रूरत है तब राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के दो मुख्य घटक राजनीति करने में उलझे हुए हैं. दूसरी ओर विदर्भ में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है. कम से कम बदहाल किसानों को मदद देने में ख़रीफ़ की फ़सल के मौक़े पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए था. यह किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है. यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है. इसलिए इस मुद्दे को राकांपा-कांग्रेस के आपसी द्वंद्व व अहंकार का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए. अब जबकि इस मामले पर फ़ैसला लेने का दारोमदार मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया गया है तो दोनों इस मुद्दे पर सहानुभूति के साथ विचार करें और जल्द से जल्द निर्णय लें, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके. आशा है कि उपमुख्यमंत्री पवार इस बात पर ग़ौर करेंगे कि इस तरह की ठेंगा दिखाने की राजनीति राकांपा के लिए आत्मघाती भी सिद्ध हो सकती है. वह भी तब जब उनके नेतृत्व में राकांपा अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सरकारी आश्रमशाला रामभरोसे

आश्रमशालाएं राज्य के दुर्गम-पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज में शिक्षा की ज्योति फैलाने का कार्य करती हैं. इन आश्रमशालाओं में आदिवासियों-दलितों के बच्चे छात्रावास में रहकर अभ्यास करते हैं. यहां पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ भोजन, कपड़ों व अन्य दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं. मगर राज्य की सरकारी आश्रमशालाओं में शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की कमी से वहां व्याप्त अव्यवस्था कई सवाल खड़े करती हैं. यहां व्याप्त अव्यवस्था से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि शिक्षकों को अध्यापन कार्य छोड़कर अन्य कार्यों को करना पड़ता है. वैसे भी सरकारी आश्रमशालाओं में शिक्षकों व अन्य शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भारी कमी है. इसके बाद भी सरकार आश्रमशालाओं में शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने पर ध्यान नहीं दे रही है. इसके चलते कई जगह शिक्षिकाओं को ही हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की देखरेख के लिए अधीक्षिका की भूमिका निभानी पड़ रही है. दो कक्षाओं को एक साथ, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने का दृश्य पूरे राज्य में देखा जा सकता है. इसके अलावा दुर्गम क्षेत्र के इन बच्चों की पढ़ाई में सबसे अधिक बाधा बिजली की आंख मिचौली पहुंचाती है.

उल्लेखनीय है कि आदिवासी विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव उत्तम खोब्रागड़े ने आदिवासी आश्रमशालाओं का आकस्मिक निरीक्षण करने का अभियान चलाया था और वहां व्याप्त कुव्यवस्था की तस्वीर पेश की थी. कई आश्रमशालाओं को नोटिस देकर पूछा गया था कि पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण क्यों न उनको बंद कर दिया जाए. उन्होंने तब यह भी कहा था कि आश्रमशालाएं नेताओं के लिए दुधारू गाय हैं और मोटी कमाई का ज़रिया हैं. उनके इस अभियान से एक साल पहले निजी आश्रमशाला संचालकों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि उस अभियान के निशाने पर तब निजी आश्रमशालाएं ही थीं. उस वक़्त तो खोब्राकड़े आदिवासी समाज विकास मंत्री को भी नहीं बख्शा था. नतीजतन राजनीतिक दबाव के चलते उनका स्थानांतरण अन्य मंत्रालय में कर दिया गया था. मगर तब उत्तम खोब्रागड़े ने निजी आदिवासी आश्रमशालाओं के साथ सरकारी आश्रमशालाओं में शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्या की ओर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा था. आदिवासी विकास विभाग के आंकड़ों पर भरोसा करें तो राज्य की सरकारी आश्रमशालाओं व (वस्तीगृहों) छात्रावासों में शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के 1321 पद रिक्त हैं. आदिवासी विभाग में व्याप्त लालफीताशाही का आलम यह है कि आदिवासी लड़कियों के कई वसतीगृह में अधीक्षिका का पद कई वर्षों से नहीं भरा गया. इसके परिणामस्वरूप शिक्षिकाओं को ही अधीक्षिका की भूमिका निभानी पड़ रही है. कई जगह शिक्षिका न होने पर क्लास-4 की महिला कर्मचारी को अधीक्षिका का कार्यभार संभालने को कहा जाता है.

पूरे राज्य में 552 सरकारी आश्रमशालाएं हैं. इनमें से 424 माध्यमिक और 128 प्राथमिक आश्रमशालाएं हैं. उसमें भी 67 आश्रमशालाओं के साथ ही कनिष्ठ महाविद्यालय जुड़े हुए हैं. इन आश्रमशालाओं में तक़रीबन सवा दो लाख आदिवासी समाज के विद्यार्थी रहकर पढ़ाई करते हैं. वहीं 275 छात्रावासों में अब तक सरकार सिर्फ़ 40 हज़ार छात्र-छात्राओं के ही रहने की व्यवस्था कर पाई है. शिक्षकों की कमी दूर कर ही शिक्षा के स्तर में सुधार किया जा सकता है, इसलिए सरकारी आश्रमशालाओं में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग कई शिक्षक संगठन कर रहे हैं, परंतु इस मांग को सरकार ने अब तक गंभीरता से नहीं लिया है. आदिवासी विभाग के सूत्रों के अनुसार नासिक, कलवण, नंदुरबार, नागपुर, अमरावती व अन्य कई जगहों में शिक्षकों का दो माह पहले स्थानांतरण किया गया. ख़बर यह है कि नासिक विभाग में क़रीब 100 शिक्षकों ने असुविधाजनक स्थानों में तबादला होने के चलते नौकरी से इस्तीफ़ा देना उचित समझा. एक ओर शिक्षकों की पहले से कमी है, ऊपर से शिक्षकों द्वारा असुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरण किए जाने पर नौकरी छोड़कर जाने से समस्या और जटिल हो गई है. लिहाज़ा, यह स्थिति बन गई है कि एक कमरे में दो कक्षाओं के बच्चों को एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकारी आश्रमशालाओं में किस स्तर की शिक्षा आदिवासी समाज के बच्चों को दी जा रही है.

अधिकारियों की कमी

आदिवासी विकास विभाग भी अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है. यहां भी शिक्षकों की तरह कमी रहने के कारण एक-एक अधिकारी पर कई-कई जगहों के कामकाज का भार रहता है. इससे हर मामले में निर्णय लेने में अधिकारियों को समय लगता है. इससे आदिवासी विकास विभाग का हाल भी बेहाल नज़र आता है. इस विभाग में एक अपर आयुक्त, दो सहआयुक्त, पांच उपायुक्त, पांच योजना अधिकारी, दो सहायक आयुक्त के पद रिक्त पड़े हुए हैं. इसके अलावा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के वर्ग-1 व वर्ग-2 के 48 पदों में से 22 पद रिक्त पड़े हुए हैं. इन अधिकारियों की कमी से आदिवासी विकास विभाग पूरी तरह ढीला पड़ा हुआ है. इन पदों को तभी भरा जाएगा, जब सरकार को इस विभाग पर विचार करने का समय मिलेगा.

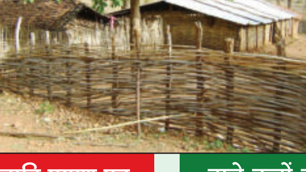

अनुदान का मनमाना ऑडिट

सरकार द्वारा आश्रमशालाओं को दिया जाने वाला अनुदान आदिवासी छात्र-छात्राओं तक कितना पहुंचता है? उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? इन आश्रमशालाओं को सरकार द्वारा अनुदान मिलने पर आदिवासी समाज के कितने बच्चे पढ़ सके? पढ़ कर आगे क्या कर रहे हैं? इन सवालों का उठना लाज़िमी इसलिए है, क्योंकि कहा जाता है कि निजी आश्रमशालाओं को मिलने वाले अनुदान का 50 प्रतिशत संचालक पचा लेते हैं. इन शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को न सरकार द्वारा तय मेन्यू के अनुसार भोजन दिया जाता है और न दैनिक क्रियाओं के लिए शौचालय, स्नानघर, पीने के पानी की व्यवस्था होती है. शालाओं को मिलने वाले अनुदान की हर वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट यदि सही तरीक़े से की जाए तो सारी सच्चाई सामने आ सकती है, सिर्फ़ खिला-पिलाकर ऑडिट नहीं होना चाहिए.

वैसे भी सरकारी आश्रमशालाओं के हेडमास्टर व अन्य शिक्षक अपनी-अपनी सुविधाओं के अनुसार ही ड्यूटी करते हैं. जब चाहे गए, जब चाहे आए. बस अधिकारियों के दौरे के समय सब ठीक होना चाहिए, बाक़ी समय नो टेंशन का माहौल रहता है.

बताया जाता है कि नासिक के अपर आयुक्त कार्यालय के स्तर पर दो वर्ष पूर्व 680 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू थी और लिखित परीक्षा भी हुई थी, परंतु सरकार ने दो वर्ष पूर्व रोक लगा दी थी, जिसे अब तक नहीं हटाया गया है. 680 शिक्षकों की प्रक्रिया किन कारणों से रोकी गई? लिखित परीक्षा का परिणाम क्या रहा? उस पर से कब रोक हटेगी? इन सवालों का जवाब न आदिवासी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी देने को तैयार हैं और न सरकार के पास इसके लिए समय है. दूसरी ओर परीक्षा देने वाले उम्मीदवार परिणाम आने की राह तक रहे हैं. पूर्व परीक्षा के परिणाम जारी नहीं किए गए हैं, जबकि अब 388 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है. इन 388 में से 310 प्राथमिक, 60 माध्यमिक और मात्र 18 शिक्षक कनिष्ठ महाविद्यालय के लिए चुने जाएंगे. दूसरी ओर निजी आश्रमशालाओं को खोलने की अनुमति दी जा रही है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि निजी आश्रमशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी आश्रमशालाओं की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा हो. इसकी वजह यह है कि निजी आश्रमशालाओं को सरकारी नियमों के तहत एक कक्षा में कम से कम 40 बच्चों का होना ज़रूरी है. शिक्षा सत्र के प्रारंभ में निजी आश्रमशालाओं के शिक्षक स्कूल प्रबंधन के दबाव में दूरदराज़ के गांव-गांव जाकर बच्चों को ढूंढते हैं. यहां यह तथ्य ध्यान रखना ज़रूरी है कि अधिकांश निजी आश्रमशालाएं नेताओं या उनके नज़दीकी लोगों की होती हैं. कुछ शिक्षाविद् यह भी मानते हैं कि यदि प्रशासन सरकारी आश्रमशालाओं में पर्याप्त शिक्षक, कर्मचारियों के साथ ही छात्र-छात्राओं के रहने की समुचित व्यवस्था करे तो कई निजी आश्रमशाला के बंद होने से शासन द्वारा दिया जाने वाला अनुदान बच सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कंपनियों का गोलमाल
नेता-अफ़सर मालामाल

राजेश नामदेव

महाकवि तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है, समरथ को नहीं दोष गोसाईं. इसका मतलब है समर्थवान को कोई दोषी नहीं कहता है. उसके दोष को ही गुण या विशेषता मान कर नज़रअंदाज़ कर देते हैं. किसी आम आदमी पर शासन का दो-चार हज़ार भी बक़ाया रहता है तो सारा अमला उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लेता है. यहां तक कि नीलामी के आदेश तक जारी कर दिए जाते हैं. बिजली या पानी का बिल बक़ाया रह गया तो तुरंत संबंधित विभाग का कर्मचारी उसका कनेक्शन काटने पहुंच जाता है. किसी सरकारी ज़मीन पर ग़रीब झोपड़ी बनाकर रहने लगता है उसे अतिक्रमण क़रार देकर उजाड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाई जाती है. मगर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों पर लाखों का बिल बक़ाया रहने पर भी उनके ख़िलाफ़ तब तक कार्रवाई नहीं होती है जब तक कोई अड़ियल ईमानदार अधिकारी अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर कार्रवाई न करे या कोई अदालत की शरण में जाकर मामला न उठाए. इसी तरह राज्य की कई बड़ी कंपनियों ने सरकार की नाक के नीचे करोड़ों का गोलमाल करके अरबों का चूना लगाया, पर किसी ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की. अधिकारियों ने इन कंपनियों के कारनामों को नज़रअंदाज़ करना ही उचित समझा. शायद संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को कंपनियों द्वारा नज़राने दे दिए गए होंगे.

दरअसल पिछले माह जब राज्य विधानसभा में लोकलेखा समिति की रिपोर्ट पेश की गई तब पता चला कि राज्य में कारोबार कर रही छह बड़ी कंपनियों ने करोड़ों का गोलमाल करके सरकारी ख़ज़ाने को अरबों रुपये का चूना लगाया है. इन कंपनियों ने तो सरकारी ज़मीन का हस्तांतरण भी सरकार की अनुमति के बग़ैर कर करोड़ों के वारे-न्यारे कर डाले. सवाल यह उठता है कि आम आदमी से दो-चार हज़ार वसूलने में सरकारी अमला तो तुरंत सक्रिय हो जाता है फिर करोड़ों की इस हेराफेरी पर वह आंखें क्यों बंद किए रहा? मतलब साफ़ है कि इस गोलमाल में शासन-प्रशासन के कुछ लोग भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं. तभी तो इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की. कंपनियां अपनी मनमानी करती रहीं और संबंधित अफ़सर उनके इशारे पर अपने पॉवर का उपयोग करते रहे हैं. लोकलेखा समिति की रिपोर्ट के अनुसार पहले मामले में मेसर्स मॉडर्न फूड इंडस्ट्रियल (इंडिया) लिमिटेड और मेसर्स मॉडर्न न्यूट्रीशियन इंडस्ट्रीज कंपनियों का विलय हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में उच्च न्यायालय के आदेश पर किया गया. मॉडर्न कंपनी की जो ज़मीन मुंबई के गोरेगांव में है, उस पर हक़ सरकार का है. ज़मीन दिए जाने के लिए हुए क़रार की शर्तों के अनुसार हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को ज़मीन की क़ीमत के 27 करोड़ 25 लाख रुपये सरकारी ख़ज़ाने में जमा करना आवश्यक था, लेकिन कंपनी ने सरकार को एक पैसा देना भी ज़रूरी नहीं समझा. मज़ेदार बात यह है कि सरकार ने मॉडर्न कंपनी को अपनी ज़मीन दी थी, पर ज़मीन का हस्तांतरण करते समय उसने सरकार की अनुमति के बिना ही यह सौदा कर डाला. इस पर लोकलेखा समिति का मत है कि ऐसी स्थिति में रक़म संबंधित कंपनी से वसूल करने का अधिकार महसूल विभाग को है. लोकलेखा समिति की रिपोर्ट में सरकार से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जब तक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी 27 करोड़ 25 लाख रुपये की रक़म ब्याज़ सहित राजस्व विभाग को भुगतान नहीं करती है, तब तक उक्त ज़मीन को कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता है. साथ ही इस गोलमाल में भूमिका निभाने वाले संबंधित अधिकारियों की जांच कर आगे की कार्रवाई करने की सिफ़ारिश की है.

समिति में दूसरा मामला पुणे के मुंढवा इलाक़े में मेसर्स कल्याणी कारपेंटर्स को सरकारी ज़मीन देने का है. इस कंपनी को सरकार ने अपनी बहुमूल्य ज़मीन तो दे दी, लेकिन कल्याणी कारपेंटर्स ने क़रार के समय तय ज़मीन की क़ीमत 34 करोड़ 60 लाख रुपये देने की ग़र्ज़ अब तक नहीं समझी है. ग़रीबों को सरकारी ज़मीन से हटाने में ज़रा भी देर न करने वाले हमारे संबंधित अधिकारी पता नहीं क्यों इस कंपनी से इतनी बड़ी रक़म वसूल करने में सुस्त क्यों हैं? लोकलेखा समिति ने इस पर भी कल्याणी कारपेंटर्स से वर्तमान बाज़ार भाव से ज़मीन की क़ीमत वसूलने की सरकार को सलाह दी है. इस तरह सरकार ने 113 एकड़ ज़मीन मेसर्स भारत फोर्ज नामक कंपनी को औद्योगिक कार्य के लिए दी है. उसमें से 25 एकड़ ज़मीन पहले ही कल्याणी स्टील्स लिमिटेड को 18 वर्ष के लिए किराये पर दी है. किराया क़रार करने के बाद मेसर्स कल्याणी कारपेंटर्स स्पेशल स्टील कंपनी के नाम पर कारोबार करने लगी. तीसरा मामला है मेसर्स आईपीसीएल कंपनी (रायगढ़) व मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बीच हुए विलय का. इन दो कंपनियों के बीच हुए विलय के दौरान जो ज़मीन हस्तांतरित हुई, उससे संबंधित स्टांप ड्यूटी व अन्य संबंधित करों का भुगतान नहीं किया गया है. इसके अलावा होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निजी जगह के साथ ही होटल सेंटार के पास शासन से किराये पर प्राप्त ज़मीन भी बिना सरकारी अनुमति के टुलिप हॉस्पिटलिटी सर्विसेस को बेच दी गई. इस सौदे से अब तक अप्राप्त 4 करोड़ 48 लाख रुपये वसूल करने का नोटिस राजस्व विभाग ने संबंधित कंपनी को जारी किया है. इस पर लोकलेखा समिति का कहना है कि महसूल विभाग ने होटल सेंटार पर जो रक़म निर्धारित की है वह बाज़ार भाव से बहुत ही कम है. इस तरह शासन-प्रशासन के सोने से या जानबूझकर मामलों को नज़रअंदाज़ करने से सरकारी ख़ज़ाने को 200 से 300 करोड़ रुपये का नुक़सान होने का अनुमान राज्य की लोकलेखा समिति ने व्यक्त किया है.

आश्चर्य की बात यह है कि हर छोटे-बड़े मामले में हल्ला मचाने वाले विपक्षी दल के नेता भी इस मामले में चुप ही रहे, क्यों? यह शोध का विषय है. मगर इतना ज़ाहिर है कि सरकार बड़ी-बड़ी कंपनियों के मामले में हमेशा ढिलाई बरतती है. इसकी वजह यह है कि इन कंपनियों से राजनीतिक दल चुनावी फंड के नाम पर करोड़ों रुपये वसूल करते हैं. इन कंपनियों के साथ नेताओं के आपसी हित भी जुड़े रहते हैं. इन कंपनियों में यदि आगे चल कर किसी नेता द्वारा पूंजी निवेश करने की बात उजागर हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए. हो सकता है किसी मंत्री या अफ़सरशाह के बेटे-बेटियां डायरेक्टर हो सकते हैं या उनके कर्ताधर्ताओं से घनिष्ठ संबंध हो सकता है. संभवतः इसी के चलते इन कंपनियों के कई ग़ैरक़ानूनी कारनामों को हमारे मंत्री व संतरी नज़रअंदाज़ करना ही उचित समझते हैं. दूसरी ओर आम आदमी की ज़रा-सी चूक पर पूरा प्रशासनिक तंत्र उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है. झोपड़पट्टी वासियों पर गरमी हो या सर्दी अतिक्रमण हटाओ, मुहिम के नाम पर उन्हें खुले आसमान के नीचे भटकने को मजबूर कर दिया जाता है. स्टांप ड्यूटी न भरने पर तहसील कार्यालय हो या जिलाधिकारी का कार्यालय आम आदमी को दुत्कार दिया जाता है. अपमानित तक किया जाता है, परंतु करोड़ों की स्टांप ड्यूटी चुराने वाली रिलायंस कंपनी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. करोड़ों की ज़मीन अपने नाम करने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के अवैध क़ब्ज़े को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. यह है हमारे राज्य की लोकशाही आघाड़ी सरकार का जनहितैषी चेहरा. कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ की यह है असलियत. इससे यही लगता है कि राकांपा का ग़रीबों के प्रति मोह मात्र दिखावा है. भाजपा-शिवसेना सिर्फ़ बयानबाज़ी कर जनता का समर्थन पाना चाहती हैं. इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि किसी भी राजनीतिक दल को आम आदमी की चिंता नहीं है. सब को तिजोरियां भरने की और उसके दम पर वोट जुटाकर सत्ता हासिल करने की लालसा है.

feedback@chauthiduniya.com

मुंबई में ढांचागत सुविधाओं को विकसित कर शंघाई या हांगकांग के समान दर्जा दिलाया जाना चाहिए, यह जनता की चाहत है, पर मुख्यमंत्री को सड़कों के गड्ढों की परेशानी खाए जा रही है.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

फोटो-प्रभात पाण्डेय

महाराष्ट्र के गड्ढे और गुजरात की प्रगति

महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर.आर. पाटिल कहते हैं कि मुंबई शहर में बेशुमार भीड़ बढ़ गई है. शहर में हर दिन 150 झोपड़ियां बसती हैं यानी महीने में चार हज़ार पांच सौ झोपड़ियां बसती हैं. हर झोपड़ी में अगर चार लोग होंगे तो उन्नीस हज़ार दो सौ लोगों की एक नई बस्ती हर माह तैयार होती है. आतंकी मुंबई में बढ़ रही भीड़ का लाभ उठाते हैं. पहली बार आर.आर. पाटिल ने यह बात स्वीकार की है. इससे एक पल को ऐसा लगा कि गृहमंत्री आर.आर. पाटिल ने पार्टी बदल ली है क्या! वह मनसे या शिवसेना की ओर से यह प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं क्या? जैसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ़ से आर.आर. पाटिल को झोपड़ियों की भीड़ बढ़ जाने का परवाना मिला हो, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं.

युधिष्ठिर जोशी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ गुजरात के दौरे पर हैं. पाठकों के हाथ में जब यह समाचार पत्र होगा, तब तक राज ठाकरे गुजरात के दौरे से लौट चुके होंगे. राज ठाकरे ने अहमदाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मुंबई लौटने के बाद महाराष्ट्र सरकार की झड़ती लेने वाला हूं. पिछले आठ-दस साल में गुजरात सरकार ने जो प्रगति की है वह तारीफ़ के क़ाबिल है. दलीय राजनीति के चलते गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी तारीफ़ नहीं करता है. अरे कांग्रेस को छोड़ो, पर भाजपा के मित्र दल जनता दल (यू) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मोदी के बारे में दो शब्द बोलते हैं क्या? राजनीति में एक ही ख़ून के भाई भी दुश्मन बन जाते हैं. यह महाभारत का इतिहास कहता है.

राज ठाकरे ने गुजरात के टाटा के नैनो कार के कारख़ाने का दौरा किया और वह अचंभित रह गए. नैनो गुजरात को गई, यह अच्छा हुआ. उद्योगपति टाटा का भला हुआ. अगर उन्होंने महाराष्ट्र में कारख़ाना चालू किया होता तो अभी तक उनके कारख़ाने से नैनो का उत्पादन शुरू नहीं हुआ होता. इसके विपरीत महाराष्ट्र के अधिकारिओं ने उनकी आधी लागत हड़प कर ली होती. राज ठाकरे के पास तो सिर्फ़ नैनो कार के कारख़ाने की स्टोरी है, लेकिन जब एक विख्यात फोर्ड मोटर कंपनी भारत में कार का उत्पादन करना चाहती थी, करोड़ों रुपये का निवेश करके अपना कारख़ाना स्थापित करना चाहती थी, जिससे 4000 लोगों को रोज़गार मिलता. कारख़ाने की स्थापना की जगह को लेकर फोर्ड कार कंपनी के चार विशेषज्ञ चार राज्यों में घूम कर आए. इन चार राज्यों में से महाराष्ट्र एक था, जहां फोर्ड कार कंपनी अपना कारख़ाना चालू करना चाहती थी, लेकिन सारी चीज़ों का मुआयना करने के बाद उन्होंने गुजरात को कारख़ाने के लिए चुना. तब महाराष्ट्र सरकार को इस बात पर शर्म महसूस हुई होगी और अपने आपसे यह सवाल किया होगा कि कोई भी यहां आने से क्यों कतराता है? हर तीन साल में मुंबई और राज्य में बम विस्फोट होते हैं तो नए कारख़ाने कहां से आएंगे? बीती जुलाई में हुए बम विस्फोट से मुंबई पूरी तरह हिल गई. उस पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर.आर. पाटिल ने पिछले हफ्ते विधानसभा में निवेदन पेश किया. आर.आर. पाटिल यानी राष्ट्रवादी पार्टी की आघाड़ी के राजनेता पार्टी से अधिक शरद पवार के विश्वसनीय सहकारी हैं, लेकिन आर.आर. पाटिल ने निवेदन किया तो ऐसा महसूस हुआ कि सेना या भाजपा के नेता ने किया हो. गृहमंत्री आर.आर. पाटिल कहते हैं कि मुंबई शहर में बेशुमार भीड़ बढ़ गई है. शहर में हर दिन 150 झोपड़ियां बसती हैं यानी महीने में चार हज़ार पांच सौ झोपड़ियां बसती हैं. हर झोपड़ी में अगर चार लोग होंगे तो उन्नीस हज़ार दो सौ लोगों की एक नई बस्ती हर माह तैयार होती है. आतंकी मुंबई में बढ़ रही भीड़ का लाभ उठाते हैं. पहली बार आर.आर. पाटिल ने यह बात स्वीकार की है. इससे एक पल को ऐसा लगा कि गृहमंत्री आर.आर. पाटिल ने पार्टी बदल ली है क्या! वह मनसे या शिवसेना की ओर से यह प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं क्या? जैसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ़ से आर.आर. पाटिल को झोपड़ियों की भीड़ बढ़ जाने का परवाना मिला हो, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं. मुंबई में झोपड़ियों की भीड़ बढ़ रही है, हर रोज़ लोगों की भीड़ इतनी बढ़ रही है. सेना-भाजपा गठबंधन का पांच साल राज्य था. पिछले बारह-तेरह साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार है. आबा पाटिल तो कुछ महीने छोड़ के पूरे समय मंत्री रहे हैं, फिर वह कारण क्यों बता रहे हैं. झोपड़ियों की बढ़ती भीड़ क्यों नहीं रोकी गई. पर प्रांतों से आने वालों को रोको मत, ऐसा किसी ने कहा था क्या? इस महानगर को अनुशासित नहीं करो, ऐसा आबा पाटिल को किसी ने कहा था क्या? जिन्हें काम करना होता है, वह ख़ामोश नहीं बैठते हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने कहा कि काम करो? ऐसा नहीं हुआ. पार्टी हाईकमान की राह नहीं देखी. वह झट से काम को अंजाम देने में लग गए. गृहमंत्री आबा पाटिल अभी तक पुलिस विभाग की समस्याओं का समाधान नहीं कर सके हैं. सिर्फ़ तत्व ज्ञान से आम जनता की मुश्किलें दूर नहीं होती हैं, आबा पाटिल को यह बात कब समझ आएगी.

महाराष्ट्र के उच्च विद्या विभूषित प्रधानमंत्री कार्यालय का अनुभव होने पर भी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण राज्य की सड़कों के गड्ढों से परेशान हैं. एक विशालकाय प्रगतिशील राज्य का मुख्यमंत्री सड़कों के गड्ढों से दुखी है. यह आश्चर्य की बात नहीं है क्या? मुख्यमंत्री चव्हाण अपने सामने राज्य भर की अनेक समस्याएं मौजूद रहने के बावजूद गड्ढों के लिए परेशान हैं. यह आश्चर्य और शर्मनाक स्थिति नहीं है क्या? टाटा नैनो मोटर कंपनी का कारख़ाना महाराष्ट्र में क्यों नहीं, फोर्ड कंपनी ने मोटर कारख़ाने के लिए महाराष्ट्र में जगह क्यों नहीं चुनी? अगर इसे लेकर मुख्यमंत्री परेशान हों तो कोई बात समझ में आती है. मुंबई में ढांचागत सुविधाओं को विकसित कर शंघाई या हांगकांग के समान दर्जा दिलाया जाना चाहिए, यह आम जनता की चाहत है. यह सब रह गया और मुख्यमंत्री को सड़कों के गड्ढों की परेशानी खाए जा रही है. यह अचंभित करने वाली बात है.

मुंबई के गड्ढों के लिए महानगर पालिका और एम.एम.आर.डी. तो राज्यभर के गड्ढों के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की जवाबदेही होने के बावजूद मुख्यमंत्री को चिंता करनी पड़ती है. इससे पता चलता है कि राज्य प्रशासन कैसा और कितना भ्रष्ट है. यह इस बात का प्रमाण है.

सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग मंत्री हैं छगन भुजबल. वह उपमुख्यमंत्री का पद अजित पवार के पास जाने से बहुत ज़्यादा व्यथित हुए हैं. वित्तमंत्री पद पवार के पास ही है. ये दोनों राष्ट्रवादी पार्टी के होने के बाद भी दोनों में आपसी रंजिश जगज़ाहिर है. इस साल के बजट में सार्वजनिक बांधकाम विभाग को बहुत कम राशि आवंटित होने से भुजबल साहब गुस्से में हैं. पिछले माह में संपन्न हुए विधानमंडल के मानसून अधिवेशन में पूरक अनुदान को मंज़ूरी दी गई. भुजबल साहब के विभाग को लगभग साढ़े चार हज़ार करोड़ रुपये मिले, लेकिन राज्य की सड़कों की मरम्मत करने के लिए 26 प्रतिशत रक़म ख़र्च करनी है. यह रक़म बहुत कम है. इसी वजह से रास्तों की मरम्मत नहीं हो रही है. निधि कम है, यह कहकर छगन भुजबल ने विधानसभा में अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं. सार्वजनिक बांधकाम विभाग के निवेदन को लेकर यदि पार्टी में व्याप्त द्वेष-भाव नज़र आ रहा है, शायद इसीलिए मुख्यमंत्री के नाते चव्हाण अपना धर्म निभा रहे हैं. आम जनता गई सड़कों के गड्ढों में.

शिवसेना-भाजपा के हाथों में महानगर पालिका की बागडोर होने के बाद भी उन्हें रास्तों में बढ़ रहे गड्ढों का भान नहीं है. महानगर पालिका के सरकारी आयुक्त भी राजनीति के चलते नेताओं के समान मोटी खाल के हो गए हैं. महाराष्ट्र को दोहरे जमाव की आदत लग गई है. नेताओं को आने वाले चुनाव और आगे के भविष्य के लिए धन चाहिए, तो सरकारी नौकरशाहों को भावी पीढ़ी के लिए जमा पूंजी चाहिए. इसीलिए जहां से भी मिलता है, वहीं से खाने का दोहरा प्रयास करते हैं.

धारवी के पास (मुंबई की एक बड़ी झोपड़पट्टी) एक ट्रक और टैंपो पुलिया से नाले में जा गिरे, पर वहां कोई प्राण हानि नहीं हुई. उस रास्ते से हर 30-40 सेकेंड में बेस्ट की बसें निकलती हैं. अगर कोई बस पुलिया से नीचे गिरती है तो इससे जान माल का नुक़सान हो सकता है. मुंबई शहर में हर दिन रास्तों के गड्ढों में गिरकर लोग घायल होते हैं. हाथ, पैर टूट जाते हैं. पैदल चलने वालों में ज़्यादातर मज़दूर, ग़रीब, झोपड़पट्टी में रहने वाले या वन रूम किचन के घर में रहने वाले मध्यम वर्गीय होते हैं. उनकी शिकायत सुनने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है. सरकार ही क्यों, यातायात पुलिस, पद का दर्जा कुछ भी हो, किसी के पास आम जनता के लिए टाइम कैसे होगा? आम आदमी के पास से पुलिस को 10 रुपये भी नहीं मिल सकते. महानगर में चलने वाली मोटर, टैक्सी की तरफ़ से झट से सौ-दो सौ रुपये मिल जाते हैं और ऐसे पैसे वसूल करना उन्हें पसंद है. ग़रीब क्या देगा? वे गये गड्ढों में. इन गड्ढों से वाहनों को नुक़सान होता है वह अलग. अब इन गड्ढों के बारे में मीडिया ने आवाज़ उठाई तो मुख्यमंत्री चव्हाण को आदेश जारी करना पड़ा. कॉन्ट्रेक्टर पर कार्रवाई करेंगे, सख्ती बरती जाएगी वग़ैरह-वग़ैरह. कौन-सी सख्ती करेंगे? कॉन्ट्रेक्टर को बचाने के लिए सरकारी बाबू और राजनेताओं की फौज़ होने के बावजूद मुख्यमंत्री कौन-सा चमत्कार करने वाले हैं? उनकी कड़ी चेतावनी के सामने कौन आएगा? मंत्रालय परिसर में ऐसी चर्चा है कि राज्य के सभी गड्ढों की मरम्मत करने के बाद मुख्यमंत्री और आघाड़ी सरकार के मंत्री राज्य के विकास प्रश्नों को झटपट सामने लाएंगे और उनका समाधान करेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

दिल्ली, 29 अगस्त–04 सितंबर 2011

www.chauthiduniya.com

एक और दाग़ी मंत्री की विदाई

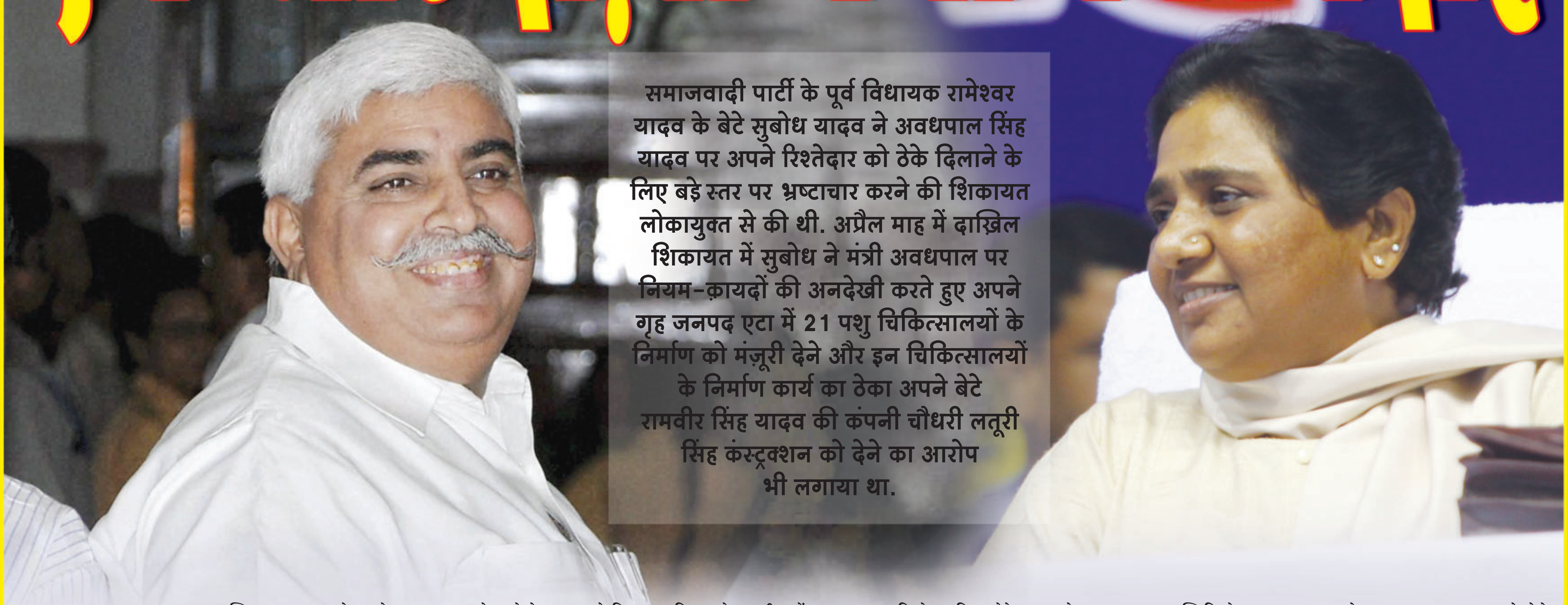

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव के बेटे सुबोध यादव ने अवधपाल सिंह यादव पर अपने रिश्तेदार को ठेके दिलाने के लिए बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने की शिकायत लोकायुक्त से की थी. अप्रैल माह में दाख़िल शिकायत में सुबोध ने मंत्री अवधपाल पर नियम-क़ायदों की अनदेखी करते हुए अपने गृह जनपद एटा में 21 पशु चिकित्सालयों के निर्माण को मंज़ूरी देने और इन चिकित्सालयों के निर्माण कार्य का ठेका अपने बेटे रामवीर सिंह यादव की कंपनी चौधरी लतूरी सिंह कंस्ट्रक्शन को देने का आरोप भी लगाया था.

अजय कुमार

आखिरकार न-न करते-करते माया के चहेते पशुधन विकास मंत्री अवधपाल सिंह यादव ने नैतिकता के आधार पर अपना पद त्याग ही दिया. यह और बात थी कि काफ़ी समय से इस्तीफ़े के लिए ना-नुकुर कर रहे अवधपाल की नैतिकता तब जागी जब मुख्यमंत्री मायावती ने उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया. लोकायुक्त की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के हाथों में आने के बाद अवधपाल ने 17 अगस्त को अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, जबकि यह इस्तीफ़ा काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था. मुख्यमंत्री मायावती को सौंपे गए त्यागपत्र में अवधपाल सिंह ने कहा कि नैतिकता के आधार पर स्वेच्छा से पद छोड़ रहे हैं. यह और बात थी कि मंत्री जी पर इस्तीफ़े का दबाव बना रहा विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं दिखा. विपक्ष का कहना था कि अवधपाल को बर्ख़ास्त करना चाहिए था. लोकायुक्त की रिपोर्ट पर पद छोड़ने वाले अवध पाल माया सरकार के दूसरे मंत्री हैं, इससे पहले मायावती के राज्य मंत्री राजेश त्रिपाठी को भी मंत्री पद छोड़ना पड़ा था. माया सरकार के दो मंत्रियों को भले ही लोकायुक्त की रिपोर्ट पर अपने पद से हाथ धोना पड़ा हो, लेकिन आपराधिक कृत्य और भ्रष्टाचार के कारण माया सरकार के आधा दर्जन मंत्री अभी तक लाल बत्ती गंवा चुके हैं. हाल में ही मंत्री पद छोड़ने वाले अवधपाल की बात की जाए तो प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा ने भ्रष्टाचार और जबरन भूमि क़ब्ज़े के लगे आरोपों की जांच में मंत्री अवधपाल को दोषी पाया था. दोषी पाए जाने पर मंत्री जी को पद से हटाने की सिफ़ारिश करते हुए लोकायुक्त ने बीते 16 अगस्त को मुख्यमंत्री को जांच रिपोर्ट सौंप दी थी. रिपोर्ट मिलने के दूसरे ही दिन मायावती ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया था. लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री को भेजी अपनी रिपोर्ट में अवधपाल पर मंत्री पद की शपथ की अवहेलना का दोषी क़रार देते हुए उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाए जाने की सिफ़ारिश करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत मुक़दमा चलाए जाने और प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन क़ानून की धारा 122 बी के तहत भी कार्रवाई किए जाने की भी संस्तुति की थी.

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव के बेटे सुबोध यादव ने अवधपाल सिंह यादव की ओर से अपने रिश्तेदार को ठेके दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत लोकायुक्त से की थी. अप्रैल महीने में दाख़िल शिकायत में सुबोध ने मंत्री अवधपाल पर नियम-क़ायदों की अनदेखी करते हुए अपने गृह जनपद एटा में 21 पशु चिकित्सालयों के निर्माण को मंज़ूरी देने और इन चिकित्सालयों के निर्माण कार्य का ठेका अपने बेटे रामवीर सिंह यादव की कंपनी चौधरी लतूरी सिंह कंस्ट्रक्शन को देने का आरोप भी लगाया था. मंत्री के विरुद्ध ग्राम सभा, एक विद्यालय और चकरोड आदि की ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़े के आरोप भी लगे थे. इसके अलावा मंत्री के ख़िलाफ़ अवैध क़ब्ज़े के साथ ही पराग डेयरी में दूध के पाउच भरने तथा सुरक्षा का ठेका अपने साले अजय यादव की कंपनी को देने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए. पाल पर मैनपुरी में पराग डेयरी का अपना भवन होने के बावजूद अपने साले के मकान को किराए पर लिए जाने का भी आरोप लगा है. इसी तरह पशु चिकित्सालयों के लिए दवाओं तथा उपकरणों आदि की ख़रीद में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप भी सामने आए हैं. लोकायुक्त की ओर से मुख्यमंत्री को जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही सपा और भाजपा ने भ्रष्टाचार में लिप्त पशुधन मंत्री को हटाये जाने की मुख्यमंत्री से मांग की थी. इससे पूर्व विधानसभा में विपक्षी दलों ने पशुधन मंत्री पर लगे आरोपों पर सदन में जमकर हंगामा किया था, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. अवधपाल का भ्रष्टाचार से ही नहीं, अपराधों के साथ भी चोली-दामन का साथ है. इससे पूर्व अगस्त में माया के वफ़ादार और दबंग पशुधन मंत्री अवधपाल सिंह के ख़िलाफ़ एटा की एक अदालत के आदेश पर बीते जून माह में हुए तीहरे हत्याकांड के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज हो चुका है. एटा ज़िले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बुद्धि सागर मिश्र ने बीते जून महीने में हुए तिहरे हत्याकांड में मारे गए एक गनर के भाई के प्रार्थना पत्र पर 06 अगस्त को ज़िले की अलीगंज थाने की पुलिस को अवधपाल सिंह यादव, इनके विधान परिषद सदस्य भाई चंद्रपाल और अमर पाल तथा पुत्र रंजीत के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए. अलीगंज थाने के जैथरा इलाक़े में गत दस जून को विजय वर्मा, उनके पुत्र अभिनव वर्मा तथा गनर संतोष यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. विजय वर्मा के दूसरे बेटे ने मीडिया को दिए बयान में इन हत्याओं में अवधपाल आदि के शामिल होने का आरोप लगाया था, हालांकि प्रारंभिक प्राथमिकी में इनको नामज़द नहीं किया गया था. बाद में गनर संतोष यादव के भाई अनुरोध यादव ने इस संबंध में अदालत में अर्ज़ी दाख़िल करके मंत्री यादव और नौ अन्य के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज कराए जाने का आग्रह किया था. अवधपाल के ख़िलाफ़ शिकायतकर्ता ने प्रदेश के लोकायुक्त एन.के. मेहरोत्रा को एक सीडी भी सौंपी थी, जिसमें जैथरा की तिहरी हत्या में मारे गए वर्मा के बेटे और पत्नी को इन हत्याओं में मंत्री एवं उनके परिजनों का हाथ होने का आरोप लगाते दिखाया गया था. लोकायुक्त ने यह सीडी मुख्यमंत्री को भिजवा दी थी, क्योंकि आपराधिक मामलों की जांच उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है. मायावती मंत्रिमंडल में अवधपाल सिंह अकेले मंत्री नहीं हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के अरोप लगे हैं. अवध की तरह ही कई और मंत्रियों के ख़िलाफ़ भी आपराधिक वारदात में शामिल होने का आरोप लग चुका है, इसमें से कुछ को तो अदालत ने कटघरे में खड़ा कर दिया है, वहीं कई अभी भी बेलगाम घूम रहे हैं. मामला अपराध तक ही नहीं सीमित है. वर्तमान में प्रदेश के लोकायुक्त के पास भी भ्रष्टाचार के क़रीब 80 मामले ऐसे हैं, जिनमें राजनेताओं और नौकरशाहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है, लेकिन माया सरकार और शासन की तरफ़ से इजाज़त नहीं मिलने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा हैं. राज्य सरकार और शासन स्तर पर सहयोग नहीं मिल पाने से आहत लोकायुक्त एन के महरोत्रा ने बीते दिनों राज्यपाल बीएल जोशी को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया. लोकायुक्त द्वारा राज्यपाल को भेजे गए प्रतिवेदन मे तीन मंत्रियों, एक सांसद, एक विधायक, चार पूर्व विधायकों, ग्यारह निकाय अध्यक्ष, तीन आईएएस अधिकारियों सहित कई बड़े लोगों के नाम भ्रष्टाचार आदि में शामिल होने की बात कही गई है. मंत्रियों के ख़िलाफ़ जांच आगे बढ़ाए जाने का आदेश सरकार को देना है, जबकि नौकरशाहों के ख़िलाफ़ मुख्य सचिव को अनुमति देना है, लेकिन दोनों ही स्तरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. लोकायुक्त न्यायमूर्ति मेहरोत्रा द्वारा पिछले पांच वर्ष के दौरान की गई जांच में जो वर्तमान या पूर्व मंत्री विधायक आरोपी या लिप्त मिले हैं. इनमें अमर जीत सिंह, राजेंद्र सिंह राणा, अवधेश प्रसाद चौधरी, मुहम्मद बशीर, धर्म सिंह सैनी, कपिल देव यादव, सुधाकर वर्मा, शिशुपाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, अनीस अहमद ख़ां, फूलबाबू और अवधपाल सिंह यादव हैं. लोकायुक्त का कहना था कि कैबिनेट मंत्री रंगनाथ मिश्र और नारायण सिंह के अलावा विधायक भगेलू राम, मोती सिंह, प्रदीप माथुर, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल और एन.के. सिंह आकद के संबंध में भी उन्हें शिकायतें मिली हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है. ज़्यादातर के ख़िलाफ़ विधायक निधि और पद के दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने व ज़मीन क़ब्ज़ाने की शिकायतें हैं. लोकायुक्त इस बात से ख़ुश दिखे की मुख्यमंत्री मायावती ने इनकी रिपोर्ट मिलने के 24 घंटे के भीतर अवधपाल को हटा दिया.

विपक्ष बोला, पूरी सरकार भ्रष्ट

माया राज में फैले भ्रष्टाचार पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही का कहना था कि माया सरकार के कुछ मंत्री नहीं पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है. मुख्यमंत्री मायावती से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ लगाम लगाएं, क्योंकि कि वह तो स्वयं ही इस भ्रष्टाचार की जनक हैं. अवधपाल को हटा कर माया अपनी छवि बचाना चाहती हैं, लेकिन यह होना असंभव है. सपा के राष्ट्रीय महासचिव मो. आज़म ख़ान ने कहा है कि यूपी में न क़ानून है और व्यवस्था. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा ने कहा कि अवधपाल जैसे नेता तो मोहरा मात्र हैं. बसपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अपराध के दलदल में फंसी हुई है.

मुझे फंसाया गया : अवधपाल सिंह यादव

लोकायुक्त के घेरे में आने के बाद मंत्री पद छोड़ने वाले अवधपाल सिंह ने ख़ुद पर लगे आरोपों को पूरी तरह ग़लत बताते हुए कहा कि उन्हें साज़िश रच कर फंसाने का काम किया गया है. बेटे की कंपनी को ठेका दिए जाने के संबंध में उनका कहना था कि कोई भी काम नियम विरुद्ध नहीं किया गया. वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि एटा के जैथरा में हुआ तिहरा हत्याकांड सपा के कार्यकर्ताओं ने कराया था और इस मामले में मुझ पर साज़िश के तहत आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि मैं न तो अपराधी रहा हूं और न कभी हो सकता हूं. मैंने अपने जीवन में किसी की हत्या नहीं की. एटा के तिहरे मर्डर में मेरा एक परसेंट भी हाथ नहीं है.

दाग़ियों की सूची लंबी है

मायावती सरकार के दाग़ी मंत्रियों की बात की जाए तो अवधपाल से पूर्व हमीरपुर में व्यापारी नीरज गुप्ता की हत्या में शामिल आरोपी रिश्तेदार को बचाने के मामले में मायावती के सबसे विश्वसनीय मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी का नाम आया था. सरकार इस मामले में चुप्पी साधे रही, कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया था. अब हाईकोर्ट के आदेश से उक्त मामले की सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन सिद्दीक़ी के रुतबे में आजतक कोई कमी नहीं आई है. यही हाल बाबू सिंह कुशवाहा और अनंत कुमार मिश्र उर्फ़ अंटू का रहा. दो सीएमओ की हत्या के बाद दोनों को माया मंत्रिमंडल से तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन आज भी यह दोनों आराम से घूम फिर रहे हैं. इसी तरह ग़ाज़ियाबाद हत्याकांड के आरोपी माया के कैबिनेट मंत्री वेदराम भाटी भी बचे हुए हैं. मंत्री पर तिहरे हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा तो सरकार ने डीजीपी जांच का आदेश दे दिया, लेकिन सरकारी रुख़ को भांप कर डीजीपी ने रिपोर्ट भाटी के पक्ष में ही दे दी. प्रदेश के राज्य मंत्री जयवीर सिंह पर अभियंता पत्नी ने पति की हत्या का आरोप लगाया. पीड़िता को इंसाफ़ के नाम पर जेल जाना पड़ गया. इसके पश्चात आरोपी मंत्री को मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दे दी. बात यहीं ख़त्म नहीं हुई. सीएमओ हत्याकांड के आरोपी अनंत मिश्र तथा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्र पर एक शिक्षिका ने अपने पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अरोप लगाया था, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. मायावती राज में ऐसे दाग़ी मंत्रियों की संख्या भी कम नहीं हैं जिन्हें मायावती ने विभिन्न निगमों में उपाध्यक्ष बनाकर राज्यमंत्री का दर्जा दे रखा है. इसमें से कुछ तो ईनामी भी थे. अपने कार्यकाल में पांच साल पूरा करने की ओर अग्रसर मायावती सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में कुछ मंत्रियों से इस्तीफ़ा दिलवाकर ही उन्हें बख़्श दिया गया, लेकिन अदालत और लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सरकार को न चाहकर भी कार्रवाई करनी पड़ी. बात माया सरकार के गठन वाले साल से शुरू की जाए तो सत्तारूढ़ होने के कुछ समय बाद राज्यमंत्री रघुनाथ प्रसाद शंखवार का नाम दवा घोटाले में आने के बाद उन्हें मंत्री पद से हटाया गया. शंखवार सेवानिवृत्त सीएमओ थे और पहली बार बसपा के टिकट पर जीत कर आए थे. माया सरकार के एक और राज्य मंत्री आनंद सेन को अपहरण और बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास हो चुका है. सेन को जब मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय लिया था, तब वे जेल में ही थे और रिहा होने के बाद उन्हें राजभवन में मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई थी. राज्यमंत्री जमुना निषाद (दिवंगत) को हत्या के एक मामले में मंत्री पद से इस्तीफ़ा देकर जेल जाना पड़ा, जबकि दर्जा पाए राज्यमंत्रियों में मत्स्य निगम के उपाध्यक्ष राममोहन गर्ग, वन निगम के उपाध्यक्ष विनोद कुमार तेजियानी को विभिन्न आरोपों के चलते न सिर्फ़ पद से हटाया गया, बल्कि पार्टी से निकालते हुए उन्हें जेल भेजा गया. महिला से छेड़छाड़ के आरोपों के चलते एससीएसटी कमीशन के उपाध्यक्ष और गन्ना संस्थान के उपाध्यक्ष इंतिज़ार आब्दी को केवल जेल भेजा गया. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और दर्जा पाए राज्य मंत्रियों के अलावा सत्तारूढ़ बसपा के एक दर्जन से ज़्यादा विधायकों को इन पांच सालों में कई बार जेल जाना पड़ा. कई अभी भी जेल में ही हैं. ये ऐसे मामले हैं जो मायावती सरकार की पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आक्रोशित किसानों ने आवास विकास परिषद की अति महत्वाकांक्षी वृंदावन योजना का काम रुकवा दिया.

हिमालय के मिज़ाज के अनुरूप निर्माण कार्य की तकनीक न अपनाने के कारण संवेदनशील क्षेत्रों से छेड़छाड़ को आफ़त के लिए ज़िम्मेदार माना जा रहा है.

चौथी दुनिया

एक नज़र

ऐसे मिलता है दिल के दौरे को न्योता

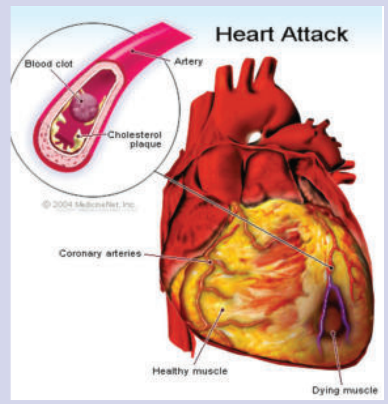

लखनऊ में जुटे देश-विदेश के चिकित्सकों ने एक नए शोध में पाया है कि आप जिस दिल को बचाने के लिए हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं. वही दवा आपको हार्ट अटैक के मुहाने तक ले जा सकती है, जबकि मरीज़ के शरीर के सरकेडियम रिदम का अध्ययन करने के बाद दी जाने वाली दवाओं से सोते समय दबे पांव आने वाले हार्ट अटैक के ख़तरे को कम किया जा सकता है. शोध में पाया गया है कि बिना पूरी जानकारी के डॉक्टरों द्वारा दी जा रही दवाएं व्यक्ति को हाईपर टेंसिव बना कर हाई रिस्क के दायरे में ले जा सकती हैं. अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मीनोसाटा के सहयोग से उच्च रक्तचाप वाले मरीज़ों पर किए जा रहे शोध में शामिल फिजियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर नर सिंह वर्मा का कहना था कि हर व्यक्ति के शरीर का अलग-अलग सरकेडियम रिदम होता है. इसी के अनुसार हृदय गति से लेकर शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं में उतार-चढ़ाव आता है. दिल के डॉ.पी.लाल कहते हैं कि हाई ब्लडप्रेसर को मूक हत्यारा कहा जाता है, क्योंकि यह दिल, गुर्दे और मस्तिष्क को धीरे-धीरे नुक़सान पहुंचाता है. विभाग में चल रहे शोध में जापान निर्मित एंबुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन का भी प्रयोग किया गया. मोबाइल के आकार की यह मशीन शरीर में बांधी और जेब में रखी जा सकती हैं. इस मशीन का एक भाग हृदय के पास तारों से लगा होता है. चौबीस घंटे चलने वाले उपकरण से इस बात की जानकारी हो जाती है कि व्यक्ति में किस समय उच्च रक्तचाप की शिकायत होती हैं. सामान्यत: रक्त का दबाव रात में सोते समय कम और सुबह चार-पांच के बीच बढ़ जाता हैं. प्रोफेसर वर्मा ने बताया कि अध्ययन में यह भी पाया गया कि हार्ट की बीमारी वाले कुछ मरीज़ों में रक्त का दबाव रात में बढ़ता है. ऐसे में रक्त का दबाव बढ़ने पर जिस व्यक्ति के हृदय के बदलाव की क्षमता अच्छी होगी उनमें हार्ट अटैक का ख़तरा कम होगा. इसके विपरीत पहल से ही हार्ट की बीमारी होने पर मरीज़ में अचानक अटैक और डेथ की आशंका बढ़ जाती है. रात में सोते समय होने वाली मौतों में साठ फ़ीसदी इसी कारण होती है. दवा का निर्धारण करने से उच्च रक्तचाप के कारण शरीर के अन्य भाग हृदय, गुर्दे आदि पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सकता है.

गैस उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे

उत्तर प्रदेश एक तरफ़ पर्यावरण संरक्षण में कुछ ख़ास नहीं कर पा रहा है तो दूसरी तरफ़ राज्य ने धरती को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बाक़ी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक़ जलवायु परिवर्तन से जुड़े ख़तरों के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश अधिक कर रहा है. राज्य से उत्सर्जित होने वाली कुल ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का अंश दो तिहाई, जबकि मीथेन की भागीदारी 26 और नाइट्रस ऑक्साइड 8 फ़ीसदी है. अकेले कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही प्रदेश के वायुमंडल में 289 मिलियन टन से अधिक पाया गया. पिछले 15 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तीन गुना से अधिक पहुंच गया हैं. विद्युत सेक्टर से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा 45 फ़ीसदी आंका गया है, जबकि उद्योगों से 27 फ़ीसदी आंका गया है. उधर, सूबे में धान की खेती और नाइट्रोजन और कृत्रिम उर्वरकों की बढ़ती खपत ने दूसरी ग्रीन हाउस गैसों मीथेन व नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर बढ़ाने में ख़ास योगदान दिया है. धान की खेती से मीथेन का 15 फ़ीसदी हिस्सा वायुमंडल में पहुंचता है. लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग में रिकॉर्ड तोड़ दिया.

कुसुमा नाइन और फक्कड़ को उम्रक़ैद

कुख्यात दस्यु राम आसरे तिवारी उर्फ़ फक्कड़ और उसकी साथी दस्यु सुंदरी कुसुमा नाइन समेत पांच लोगों को उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के विशेष न्यायाधीश संदीप जैन ने अपहरण और हत्या करके शव नदी में बहा देने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 40-40 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई. इससे पूर्व अन्य दो मामलों में फक्कड़ और कुसुमा नाइन को फांसी तथा उम्र क़ैद की सज़ा हो चुकी है. ग़ौरतलब हो, थाना भरेह क्षेत्र के गांव हरौली निवासी आदेश तिवारी तथा शिवशंकर को आठ मार्च 1998 को रामआसरे उर्फ़ फक्कड़ तथा कुसुमा नाइन गैंग ने अपहरण करके पांच लाख रुपये की फ़िरौती मांगी थी. तीन सप्ताह बाद आदेश तिवारी की बिल्लौड़ के बीहड़ में हत्या करके शव क्यारी नदी में बहा दिया गया था. मई माह में शिवशंकर फिरौती देकर मुक्त हो गया था. उसने आदेश तिवारी की पत्नी हीरा देवी को आकर हक़ीक़त बताई थी. घटना के क़रीब 13 साल बाद पांचों अभियुक्तों को 10 अगस्त 201 को सज़ा सुनाई गई.

रामदेव ने आज़ादी को अधूरी बताया

प्रसिद्ध योगगुरु बाबा रामदेव ने देश में मिली आज़ादी को अधूरी बताया है. रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में संवाददाताओं से कहा कि आज की आज़ादी अधूरी है. भारत में वैधानिक व्यवस्थाओं पर क़ब्ज़ा जमाए हुए एक प्रतिशत लोगों ने देश की 99 प्रतिशत जनता को गुलाम और बेकार बना दिया है. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही नीतियों को बदलने और अंग्रेजी काले क़ानूनों को ख़त्म करने का काम शुरू होना चाहिए. इसी तरह से देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की ज़रूरत है. बाबा रामदेव ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर मुक़दमा चलाकर त्वरित न्यायालयों द्वारा छह महीने में उनका फ़ैसला किया जाना चाहिए और भ्रष्टाचारियों की सजा आजीवन कारावास तथा मृत्युदंड होना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में कर व्यवस्था ही ग़रीबी का सबसे बड़ा कारण है. रामदेव ने अन्ना हज़ारे को अपना समर्थन देते हुए अन्ना के मंच पर जाने के मामले में चुप्पी साध ली. अन्ना के लोकतांत्रिक आंदोलन को केंद्र सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बसपा और बामसेफ में दरार

श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर)

[illegible]

> बामसेफ के मंच पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के साथ शरद यादव और रामविलास पासवान भी नज़र आएंगे. हालांकि शरद यादव भाजपा के एनडीए गठबंधन में संयोजक हैं और रामविलास पासवान कांग्रेस के यूपीए गठबंधन में हैं. ये दोनों नेता अपने गठबंधन के किसी नेता को बामसेफ के मंच तक नहीं ले जा रहे हैं.

[illegible]

feedback@chauthiduniya.com

बादल फटने से कई लोगों की मौत

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में बारिश के कारण अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सैणा गांव की थलीछानी गांव में बादल फटने के बाद हुए भूस्खलन से पांच लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई. मरने वालों में चार एक ही परिवार के थे. इस घटना में 22 मवेशी भी मारे गए. दूसरी घटना में थौलधार ब्लॉक में नगण-भवन मोटर मार्ग पर नाला खोदते हुए पहाड़ का मलबा दरक कर वर्षा के साथ आने से तीन नेपाली मज़दूर मारे गए. तीनों शवों को राजस्व पुलिस के मदद से मलबे से बाहर निकाला गया. इन मौतों ने राज्य के आपदा प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी, जिसमें साफ़ दिखा कि आपदा के समय प्रबंधन का कहीं अता-पता नहीं रहता. मृतकों में सैंणा (मोलधार) निवासी गोबरू, बबीता, उर्मिला, मीला के साथ गोबरू के समधी भरत सिंह निवासी सीरा उत्तरकाशी भी शामिल हैं. इस हादसे में एक मात्र महिला सदस्य शांति देवी को ही जीवित निकाला जा सका, जिसे दून में उपचारार्थ भर्ती किया गया है. ख़ासा विलंब से पहुंचे क्षेत्रीय विधायक खजानदास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री शिवेंद्र सिंह रावत ने मृतक के परिजनों को एक-एक लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की. टिहरी के सांसद विजय बहुगुणा ने मृतक के परिवार को पांच लाख की सहायता देने की मांग की है. भूस्खलन में टेकचंद, गणेश प्रसाद, गीतादेवी की दबकर मौत हो गई. राज्य के लगभग 700 गांवों को भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के लिहाज़ से संवेदनशील माना गया है. इन गांवों के लोगों को अन्यत्र बसाने की योजना राज्य गठन के दस वर्ष बाद भी केंद्र और राज्य के मध्य उलझी हुई है. अब तक राज्य सरकार अपनी पुनर्वास नीति न होने की बात कहकर बचती रही है. अब राज्य की अपनी पुनर्वास नीति बन जाने के बाद भी सरकार की ग़लत नीति के कारण इस दिशा में कोई कार्यवाही नज़र नहीं आ रही है. नेशनल रिमोट सेसिंग एजेंसी हैदराबाद जी.एस.आई. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में जो बात प्रकाश में आई है, उसी के आधार पर इन गांवों को चिन्हित किया गया है जो उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, पौढी, टिहरी पिथौरागढ़ जनपद के हैं. राज्य सरकार का कहना है कि इन गांवों के पुनर्वास के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के पास प्रस्ताव भेजा है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई मदद राज्य सरकार को नहीं मिल पाई है. राज्य [illegible]

feedback@chauthiduniya.com

अब तक हुई मौतें

वर्ष 1967 में 8 सितंबर को नानक मत्ता में 80 लोगों की मौत हुई. वर्ष 1971 में धारचूला में एक दर्जन लोग मारे गए तो वर्ष 1976 में कपकोट में 11 लोग मारे गए. वहीं 1977 में तवाघाट में 44 लोग मारे गए. [illegible]

एक नज़र

नेताओं-नौकरशाहों ने भ्रष्टाचार बढ़ाया

उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष जनरल टीपीएस रावत ने कहा कि उत्तराखंड ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन भ्रष्ट नेता-नौकरशाहों के गठजोड़ ने छवि ख़राब कर दी है. दस साल में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है. उन्होंने कहा कि जनता के भरोसे उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आंदोलन खड़ा किया है. जनरल रावत ने कहा कि पलायन से पहाड़ों का इतना बुरा हाल है कि पूरे देश में आबादी बढ़ रही है, पहाड़ के गांव आबादी विहीन हो रहे हैं. पर्वतीय क्षेत्रों से चार लाख मतदाता कम हो गए, इसकी क़ीमत परिसीमन में पहाड़ को छह सीटें कम कर चुकानी पड़ी. नाबार्ड के अनुसार उत्तराखंड की आय में खेती का अंश 35 प्रतिशत से कम होकर 22 प्रतिशत रह गया है. ग्यारह साल बाद भी राजधानी का मुद्दा अनसुलझा है. उद्योगों में राज्य की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि देने के बाद भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिला. उन्होंने सरकार पर सीधे आरोप लगाया कि वह सरकारी निगमों के हाथों काम छीनकर बाहरी एजेंसियों को काम दे रही है. केएमवीएन, जीएमवीएन, उपनल और उत्तराखंड अवस्थापना विकास निगम संकट के दौर से गुज़र रहे हैं. 40 शहादतों के बाद बने राज्य में घोर निराशा छाई हुई है. रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ उन्होंने हमेशा बिगुल बजाया. कांग्रेस में रहते हुए यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप रहता तो मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यपाल बन जाता. इस तरह का आश्वासन भी कांग्रेस की तरफ़ से मिला था. उन्होंने कहा कि जनता के भरोसे यह आंदोलन वह आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने अन्ना के आंदोलन का भी समर्थन किया. इस मौक़े पर प्रसिद्ध लोकगायक व गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी ने आह्वान गीत सुनाया और कहा कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ वे लड़ते रहेंगे. सम्मेलन में ले. जनरल जगमोहन सिंह रावत, जनरल एचवी काला, जनरल शैलेंद्र राज बहुगुणा, जनरल एस कुंवर, पूर्व आइएएस एसएस पांगती, पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त एसएस रावत, प्रो कुंवर आदि मौजूद थे. संचालन पीसी थपलियाल ने किया.

स्वास्थ्य केंद्र पर ताला

डेढ़ साल पूर्व निर्मित स्वास्थ्य केंद्र का ताला अब तक नहीं खुला. कार्यकर्ता दूसरे के घर बैठकर कार्यों की ख़ानापूर्ति कर रही हैं. मामला रुपईडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्राम वीरपुर झलहिया के ललकपुरवा का है. यहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेढ़ साल पूर्व उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया. लाखों रुपये की लागत से उपस्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद आज तक इसमें ताला लगा है. उक्त ग्राम में तैनात महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कभी कभार यहां आती हैं और लोगों को उनके आने जाने का पता भी नहीं चल पाता है. इससे ग्राम ललकपुरवा तथा आस-पास की गर्भवती महिलाओं, शिशुओं तथा बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं मिल पाती है. निर्माण के उपरांत अब तक इस केंद्र के न खुलने का ख़ामियाज़ा क्षेत्रीय लोग भुगत रहे हैं

चार नए ज़िलों की घोषणा

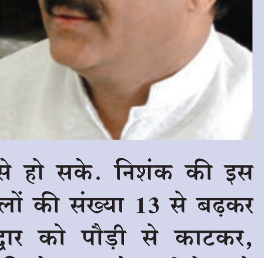

देहरादून. मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य में चार नए ज़िलों के गठन की घोषणा की. साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक नया क़ानून लाने का आश्वासन भी दिया. स्थानीय परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराने के बाद निशंक ने कहा कि राज्य में यमुनोत्री, कोटद्वार, डीडीहाट तथा रानीखेत नाम से चार नए ज़िले बनाए जाएंगे, ताकि प्रशासन का कार्य बेहतर और अधिक सुचारू रूप से हो सके. निशंक की इस घोषणा के बाद अब उत्तराखंड में नए ज़िलों की संख्या 13 से बढ़कर 17 हो जाएगी. नए ज़िलों को कोटद्वार को पौड़ी से काटकर, यमुनोत्री को उत्तरकाशी से, डीडीहाट को पिथौरागढ़ और रानीखेत को अल्मोड़ा से काटकर बनाया जाएगा. निशंक ने कहा कि प्रशासनिक चुस्ती के लिए छोटी प्रशासनिक इकाइयां अधिक बेहतर होती हैं इससे इलाक़े का विकास होता है तथा प्रशासन तक लोगों की पहुंच आसान होती है. उन्होंने कहा कि नए ज़िले बनाने का कार्य यहीं ख़त्म नहीं होगा. ज़रूरत पड़ने पर और नए ज़िलों का गठन किया जा सकता है.

उक्रांद भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ेगा : पुष्पेश

द्वाराहाट : उक्रांद ब्लॉक इकाई की बैठक में आवारा व जंगली पशुओं की समस्या से निजात को ठोस नीति बनाने व वन अधिनियम को शिथिल बनाने की मांग की गई. मुख्य अतिथि विधायक पुष्पेश त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के भष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है. पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार और राज्य सरकार बुरी तरह भ्रटाचार में डूब चुकी है. यूपीए सरकार ने 7 लाख करोड़ व राज्य सरकार ने 10 हज़ार करोड़ के घोटालों को अंजाम देकर देश को शर्मसार किया है. सरकारों के नुमाइंदे भ्रष्टाचार रोकने के बजाय अपने को पाक साफ़ बताने में लगे हैं. उन्होंने कहा कि उक्रांद भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए सभी ताक़तों को एकजुट करके मोर्चा खोलेगा. बैठक में आवारा व जंगली पशुओं की समस्या से निजात के लिए ठोस नीति बनाए जाने और वन अधिनियम को शिथिल बनाने की भी मांग की गई. इस अवसर पर जन नेता स्व. विपिन त्रिपाठी की पुण्यतिथि समारोह की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. उक्रांद के संस्थापक सदस्य स्व. डी.डी. पंत 90वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान एक दर्जन लोगों ने उक्रांद की सदस्यता ग्रहण की. अध्यक्षता कैलाश फुलारा और संचालन आनंद सिंह बिष्ट ने किया. जगदीश बुधानी, लक्ष्मण किरौला, कमला कैड़ा, पूरन पांडे, चंद्रशेखर जोशी, भीम सिंह किरौला, पार्वती कैड़ा, भैरव दत्त सती, बहादुर सिंह आदि ने विचार रखे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अन्ना की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से कांग्रेस बैकफुट पर

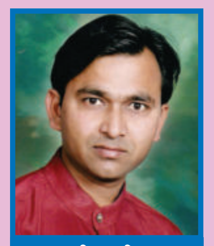

ब्रजेश पटेल

अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई को उत्तर प्रदेश के हर शहर में भरपूर समर्थन मिल रहा है. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बसपा को घेरने का प्रयास कर रही थी, अन्ना के आंदोलन इसे ही बैकफुट पर खड़ा कर दिया है. प्रदेश में मिशन 2012 का नारा देकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपना 22 साल पुराना वनवास ख़त्म करना चाहती है, लेकिन भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को कांग्रेस को जो बढ़त मिली थी, अब ख़त्म होती नज़र आ रही है. सिविल सोसायटी ने जन लोकपाल बिल के ज़रिये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का अभियान शुरू किया है. इससे पहले बाबा रामदेव ने विदेश में जमा काला धन देश में वापस लाने के लिए जो अभियान शुरू किया था. केंद्र सरकार ने उसे लाठी के बूते दबा दिया. अन्ना हज़ारे को भी सरकार ने घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही. अन्ना का आंदोलन दिल्ली में चला, पर उनके समर्थन में भी प्रदेश के हर शहर में लोग सड़क पर उतरे. आगरा, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और बरेली में लोगों ने जुलूस निकाले और धरने पर बैठे. प्रदेश में कांग्रेस पिछले दो साल से भ्रष्टाचार के लिए बसपा की सरकार को कोसती आ रही थी. कांग्रेस ने विधान सभा चुनाव में भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाने का ऐलान किया. लेकिन अन्ना हज़ारे ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो आंदोलन शुरू किया, कांग्रेस हाईकमान विरोध में खड़ी हो गई. ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के लिए भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बयान बेमतलब लगते हैं.

अन्ना हज़ारे के आंदोलन का प्रदेश के विधान सभा चुनाव में बड़ा असर दिखाई देगा. अन्ना का आंदोलन ग़ैर राजनीतिक है. लेकिन जनविरोध जो सड़कों पर दिख रहा है, इसकी तासीर सियासी है. अन्ना हज़ारे के आंदोलन में छिपा यह नतीजा आरएसएस ने भांप लिया है. उसने अपने कार्यकर्ताओं को अन्ना के आंदोलन में शामिल होने को कहा है. अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही अन्ना के आंदोलन में दिखाई पड़ रहे हैं. बसपा ने इस आंदोलन का समर्थन तो किया है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को इससे दूर रखा है. सपा भी अन्ना के साथ है, लेकिन आंदोलन से दूर है. जीत होगी तो जनता के बीच भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखेंगे. ऐसे में जनता से संवाद और सहानुभूति का लाभ भाजपा को मिलना लाज़िमी है. अन्ना के आंदोलन में अब तक जो लोग सड़कों पर हैं, उनमें ज़्यादातर वे लोग हैं जो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ख़ुद को नहीं जोड़ते. इस भीड़ में संख्या छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुज़ुर्गों और महिला संगठनों की है. यह वही भीड़ है जो हर चुनाव में अपनी आज़ाद अभिव्यक्ति के चलते चुनाव में प्रत्याशी चुनते हैं. कांग्रेस को प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी यह समझ में नहीं आ रहा है. अन्ना के आंदोलन का प्रदेश की सियासत में प्रत्यक्ष फ़ायदा तो किसी को नहीं दिखता है, लेकिन भाजपा और बसपा के नेता ख़ुश हैं. भाजपा इसलिए ख़ुश है, क्योंकि भाजपा सांसद से सड़क तक इस आंदोलन में ख़ुद को शामिल कर चुकी है. बसपा इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब इससे ज़्यादा उंगली कांग्रेस पर उठ रही है. जो कांग्रेस कल तक प्रदेश में मायावती को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सड़क पर आ रही थी अब ख़ुद अपना चेहरा छिपा रही है. बसपा के लिए चौतरफ़ा प्रहारों के बीच एक मोर्चा ख़त्म हुआ. वहीं इसके मुस्लिम वोट बैंक में बंदरबांट में एक हिस्सेदार कम होता नज़र आ रहा है. अन्ना हज़ारे की सिविल सोसायटी का प्रदेश में कोई संगठन नहीं है. इसका लाभ यह है कि कोई किसी के दबाव में आंदोलन में नहीं है. जिसे जब जहां समझ में आ रहा है जूलूस निकाल रहा है और प्रदर्शन कर रहा है. कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन इस आंदोलन में सीधे नहीं जुड़े हैं, पर भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) के लोक कलाकार इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरएसएस और वामपंथी मौक़ा आने पर कई बार साथ-साथ नज़र आए. देश में सन 1974 में पहली बार जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ. तब इमरजेंसी के बाद सरकार पलटी थी. दूसरी बार सन 1987 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन हुआ और सरकार बदली गई. इन दोनों आंदोलन के दौरान भी कोई सियासी नज़रिया नहीं था. वक़्त आने पर जनता पार्टी और जनता दल का चेहरा नज़र आया. सिविल सोसायटी में विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन मोर्चा की तरह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पर सिविल सोसायटी की ताक़त बढ़ेगी तो वह दिन दूर नहीं होगा जब इसकी धमक प्रदेश के विधान सभा चुनाव में सुनाई देगी.

feedback@chauthiduniya.com

सोनिया-राहुल के गढ़ में अन्ना को बढ़त

यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जनमत संग्रह ने अन्ना समर्थकों के हौसले बढ़ा दिए हैं, वहीं सोनिया और राहुल को जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है. रायबरेली और अमेठी में क्रमश: 96 और 95 फ़ीसदी लोगों ने अन्ना के पक्ष में वोट किया है. इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लखनऊ कोऑर्डिनेटर आर.के. अग्रवाल कहते हैं कि अन्ना को लेकर केंद्र सरकार जिस तरीक़े से पेश आ रही है इससे आग और भड़क गई है. उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं. जनमत संग्रह में रायबरेली में 96 प्रतिशत लोग अन्ना हज़ारे के साथ हैं, जबकि सिर्फ़ 4 प्रतिशत कांग्रेस के, वहीं अमेठी में कांग्रेस को पांच प्रतिशत लोगों का विश्वास हासिल रहा. यह जनमत संग्रह रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र में एसएमएस के माध्यम से कराए गए थे. रायबरेली सीट से लगातार लोकसभा का चुनाव जीतती रही. सोनिया गांधी और युवा नेता राहुल गांधी की छवि को उक्त जनमत संग्रह ने काफ़ी क्षति पहुंचाई है. ऑपरेशन के सिलसिले में बाहर गईं हुई सोनिया को हो सकता है कि इस जनमत संग्रह की जानकारी न हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द घूमने वालों को ज़रूर सतर्क हो जाना चाहिए हैं. सोनिया देश से बाहर हैं और उनके विरोधी उन्हें मात देने के लिए इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि के माध्यम से अन्ना के समर्थन में मौन अभियान जारी रखे हैं. रायबरेली और अमेठी दोनों ही जगह अन्ना की गिरफ्तारी के बाद यहां की जनता का मौन अभियान सड़कों पर उतर आया है. आने वाले दिनों में सोनिया और राहुल के संसदीय क्षेत्र में अन्ना के समर्थकों का दबदबा क़ायम हो सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अधिग्रहण की आग लखनऊ तक फैली

किसानों की भूमि के अधिग्रहण के मामले पर माया सरकार को कहीं से राहत नहीं मिल रही है. एक तरफ़ कोर्ट की फटकार तो दूसरी तरफ़ केंद्र और विपक्ष के दबाव ने प्रदेश भर के किसानों के हौसले बुलंद कर दिए हैं. भूमि अधिग्रहण के दसियों साल पुराने इन मामलों को भी हवा दी जा रही है, जिससे माया सरकार का कोई लेना-देना नहीं है. विधान सभा के दोनों सदनों में भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर विपक्षी तेवरों से जूझ रही माया सरकार के लिए इस समय मुश्किलें और भी बढ़ गईं, जब यह आग राजधानी लखनऊ को भी झुलसने लगी है. 1983 और इसके बाद 1999 में भाजपा शासन काल में आवास विकास परिषद, लखनऊ द्वारा वृंदावन योजना (रायबरेली रोड) के लिए किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था. कहीं कोई विवाद नहीं बचा था, लेकिन हवा का रुख़ भांप कर (क़रीब 12 साल बाद) मुआवज़ा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतर आए. इस बात का पता जब इन किसानों को लगी जिनकी ज़मीनें लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बसंत कुंज योजना(हरदोई रोड) के लिए की गई थी, तो वह भी उत्तेजित हो गए. किसानों ने चेतावनी दी कि बसंत कुंज योजना में प्रभावित किसानों को बढ़ा हुआ मुआवज़ा नहीं मिला तो वह मकानों पर क़ब्ज़ा कर लेंगे. वृंदावन योजना के किसानों ने पुलिस प्रशासन को बेहद छकाया. लाठी-डंडे से लैस होकर किसान सड़क पर उतर आए.

> आक्रोशित किसानों ने आवास विकास परिषद की अति महत्वाकांक्षी वृंदावन योजना का काम रुकवा दिया. पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया तो वे हाथापाई पर उतर आए. यह नज़ारा राजधानी की सड़कों पर 10 और 11 अगस्त को देखने को मिला.

आक्रोशित किसानों ने आवास विकास परिषद की अति महत्वाकांक्षी वृंदावन योजना का काम रुकवा दिया. पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया तो वे हाथापाई पर उतर आए. यह नज़ारा राजधानी की सड़कों पर 10 और 11 अगस्त को देखने को मिला. पुलिस की मौजूदगी में पहले दिन 10 अगस्त को किसानों ने ट्रामा सेंटर, दुकान और मकानों के निर्माण कार्य रुकवाकर मज़दूरों को भगा दिया. इसके साथ ही परिषद के बोर्ड और ट्री गार्ड को भी ध्वस्त कर दिया. यही नहीं प्रदर्शनकारियों ने योजना के कुछ हिस्से पर क़ब्ज़ा करने का भी ऐलान किया. इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी लाठी डंडे, हसिया से लैस होकर पहुंची थी. पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत दस अगस्त की सुबह भाकियू की अगुवाई में 13 गांवों के किसान और महिलाएं पीजीआई के पास नहर पुल पर सभा करने के लिए जमा हुए. बताते चलें कि यहां पर 11 जुलाई से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था. सभा के दौरान किसानों ने वाजिब मुआवज़े की मांग पर आवास आयुक्त से ठोस आश्वासन के लिए दिन के 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया. इसके बाद वृंदावन योजना की ज़मीन पर क़ब्ज़े की चेतावनी दी. हालात बिगड़ते देख घटना स्थल पर मौजूद एसडीएम सदर पवन गंगवार और सीओ मोहनलालगंज त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने मोहनलालगंज इंस्पेक्टर, निगोहा, नगराम काकोरी सहित छह थानों के प्रभारी पुलिस और पीएसी बुला ली. इसके साथ एसडीएम और सीओ ने किसानों की मान मनौव्वल शुरू की. अधिकारियों ने आवास आयुक्त के बीमार होने के चलते बात करने में असमर्थता ज़ाहिर की तो किसानों ने मुख्यमंत्री या शासन में उनके किसी प्रतिनिधि से वार्ता की शर्त रखी. दोपहर एक बजे तक परिषद के सचिव से भी वार्ता नहीं होने के बाद डेढ़ बजे तीन चार सौ किसानों ने भाकियू नेता हरनाम सिंह वर्मा की अगुवाई में योजना की तरफ़ कूच कर दिया. किसानों ने सेक्टर चार में पीजीआई के ट्रामा सेंटर, पानी की टंकी, अपार्टमेंट, निजी आवास, मार्केट और सेक्टर 16 में तालाब के सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य रुकवा कर मज़दूरों को भगा दिया. विस्तार योजना में तोड़फ़ोड़ कर किसानों ने डिवीजन कार्यालय पर प्रदर्शन किया. इस दौरान सीओ, एसडीएम, आधा दर्जन थाना प्रभारी और पुलिस कर्मी पीछे-पीछे चलते रहे. तीन बजे किसान धरनास्थल पर वापस लौटे और आंदोलन जारी रखने का फ़ैसला कर लिया. दूसरे दिन 11 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला. उग्र किसानों ने वृंदावन योजना में काम कर रहे किसानों को वहां से खदेड़ दिया. आवास विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा वार्ता नहीं किए जाने से आक्रोषित किसानों ने वृंदावन स्थित परिषद के कार्यालय में ताला डाल दिया. इस दौरान एक निजी डेवलपर के गार्ड से किसानों ने मारपीट भी की. किसानों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि उनके द्वारा 10 अगस्त को काम बंद कराने के बाद दूसरे दिन शुरू कैसे हो गया. क़रीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा, क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज ने किसानों को समझाने की कोशिश की तो वह उनसे भी उलझ गए. भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पुलिस पर किसानों के साथ अभ्रदता करने का अरोप लगाया. भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने कहा कि उन्होंने प्रशासन के अफ़सरों को जिलाधिकारी आवास आयुक्त से वार्ता कराने के लिए काफ़ी समय दिया था. 12 जुलाई से किसानों का आंदोलन चल रहा है. 27 जुलाई को दस सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री मायावती को भी दिया गया था, लेकिन कोई अफ़सर वार्ता करने नहीं आया. किसान नेता का आरोप था कि 10 अगस्त को भी किसान गिरफ्तारी देना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया. उधर, बसंत कुंज योजना से प्रभावित किसानों का पक्ष रखते हुए भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष राजाराम लोधी ने कहा कि ज़मीन की वाजिब क़ीमत एलडीए से वसूली जाएगी. ग़ौरतलब हो वृंदावन योजना के लिए 13 गांवों की कई हज़ार एकड़ ज़मीन 1983 में 2.37 रुपये प्रतिवर्ग फिर 1999 में 18 रुपये प्रतिवर्ग के हिसाब से मुआवज़े के साथ अधिग्रहीत की गई. मुआवज़ा 2003 और 2008 में पुरानी ही दर पर मिला. किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवज़ा 35 से 40 लाख रुपये प्रति बीघा चाहिए. किसानों ने ऐलान किया है कि वृंदावन योजना में निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा. इसकी ज़िम्मेदारी विस्तार योजना के अलग-अलग गांवों के किसानों की टोलियां करेंगी. 13 गांवों के किसान उचित मुआवज़े के लिए आंदोलित हैं. हर गांव के किसानों न अपनी अपनी टोलियां गठित करने की घोषणा की है. वहीं पूरे प्रकरण पर आवास विकास परिषद ने सरकार को रिपोर्ट भेज दी है. रिपोर्ट में किसानों की दस सूत्रीय मांगों का बिंदुवार जवाब तथ्यों के साथ दिया गया है. रिपोर्ट में किसानों की मुआवज़ा राशि बढ़ाए जाने की मांग को सिरे से ख़ारिज कर दिया गया.

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com